# हरियाणा विधान सभा

# की

# कार्यवाही

## 10 मार्च, 1987

### खण्ड, अंक 10

### अधिकृत विवरण

### विषय सूची

### मंगलवार, 10 मार्च, 1987

पृष्ठ संख्या


| | |
|---|---|
| तारांकित प्रश्न एवं उत्तर | (10)1 |
| नियम 64 के अधीन वक्तव्य–– | |
| मुख्य–मंत्री द्वारा, राज्य में ओलावृष्टि से हुई क्षति तथा प्रभावित जनता को राहत देने संबंधी | (10)23 |

| | |
|---|---|
| नियम 15 के अधीन प्रस्ताव | (10)25 |
| नियम 16 के अधीन प्रस्ताव | (10)25 |
| नियम 121 के अधीन प्रस्ताव | (10)26 |
| सरकारी संकल्प– | |
| (1) हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (डिसस्वालिफिकेशन औफ मैम्बर्ज औन ग्राउन्ड औफडिफैक्शन) नियम, 1986 की स्वीकृति सम्बन्धी | (10)27 |
| (2) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण की सीमा को राज्य सरकार द्वारा निश्चित करने की स्वीकृति सम्बन्धी | (10) 31 |
| बिल्ज–– | |
| (1) दि इंडियन इलैक्ट्रिसिटी ( हरियाणा अमैंडमैंट ) बिल, 1986 | (10)32 |
| (2 ) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन ( नं ० 4 ) बिल, 1987 | (10)35 |
| (3) दि पंजाब ऐंटरटेनमैंट डियूटी ( हरियाणा अमैंडमैंट ऐंड वलिडेशन ) बिल, 1987 | (10) 62 |
| (4) दि पंजाब बैकवर्ड क्लासिज ( ग्रांट औफ लोन्ज ) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1987 | (10) 65 |

| | |
|---|---|
| (5) दि पंजाब ग्राम पंचायत ( हरियाणा अमैंडमैंट ) बिल, 1987 | (10) 66 |
| (6) दि पंजाब पंचायत समितिज ( हरियाणा अमैंडमैंट ) बिल, 1987 | (10) 66 |
| (7) दि पंजाब ऐक्सौइज ( हरियाणा. अमैंडमैंट ) बिल, 1987 | (10)73 |
| (8) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स ( अमैंडमैंट ) बिल, 1987 | (10) 75 |
| (9) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली ( फैसीलिटीज टू मैम्बर्ज ) अमैंडमैंट बिल, 1987 | (10) 79 |
| (10) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज ऐंड अलाउंसिज ( अमैंडमैंट ) बिल, 1987 | (10)82 |
| सिंचाई तथा बिजली मंत्री /अध्यक्ष आदि द्वारा धन्यवाद देना । | (10) 83 |

# हरियाणा विधान सभा

## मंगलवार, 10 मार्च, 1987

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह ) ने अध्यक्षता की ।

## तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

**श्री अध्यक्ष :** मैम्बर साहेबान, अब क्वैश्चंज होगे ।

**Replacement of old transformers and supply of low-voltage capacitors**

***1281. Chaudhri Lila Krishan:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the old transformers by heavy KVs. transformers at various places in the State where the water level has gone down; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to supply low-voltage capacitors to the farmers to tide over the problem of uneven distribution of electricity?

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) :

(a) wherever the ground water table goes down and the

agricultural consumers need extension in connected load to pump out water from greater depth, the transformers are replaced with higher capacity ones, if necessary.

(b) No, Sir.

**चौधरी लीला कृष्ण :** स्पीकर साहब, पानी की सतह लगातार डाउन जा रही है और जो किसानों की मोटरें हैं उन पर इतना लोड पड़ता शै कि वे जल जाती हैं । कई बार अगर मोटर बच जानी है नौ ट्रांसफारमर पर इतना लोड पड़ता है कि वह सड जाता है । क्या मन्द्री महोदय बताएंगे कि अधिक लोड को देखते हुए ट्रांसफारमर्ज बदले जाएंगे?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांस– फारमर्ज 46328 हैं । हम सेफटी फैक्टर के लिहाज से हर ट्रांसफारमर पर 80 प्रतिशत लोड रखते हैं, 100 प्रतिशत लोड नहीं रखते । जैसे जैसे अथोराइज्ड और अन–अथोराइज्ड कनैक्टड लोड बढ़ता है तो हम या तो ट्रांसफारमर को हायर कैपेसिटी के ट्रांसफारमर से रिप्लेस कर देते हैं या और ट्रांसफारमर ऐड कर देखे हैं । अथोराड्ज्ड लोड का तो हमें खुद पता लग जाता है लेकिन अन–अथोराइज्ड लोड का पता नहीं लगता । अगर किसी प्राइवेट सूचना से पता लग जाए कि अन–अथोराईज्ड लोड बढ़ गया है तो उसको भी देखते हैं । इस साल यानी 1988–87 में पांच हजार नए डिस्ट्रीव्यूशन ट्रांसफारमर ऐड किए गए हैं और तीन हजार अगले दो–तीन

महीनों में ऐड हो जाएंगे । इसलिये यह कत कहना कि आज तक कोई ट्रांस– फारमर ऐड नहीं किया गया, गलत है । लोड निरन्तर इनक्रीज करने लग गयाहै और इसमें जो ज्यादा नुकसान की बात है वह यह है कि अगर तो कोई इजाजत लेकर लोड इनक्रीज करे तब तो पता लग जाएगा और उसका इलाज भी हो जाएगा लेकिन अन–अथोराइज्ड लोड बहुत ज्यादा है इसलिये उसका पता न लगने से ट्रांसफारमर का नुकसान हो जाता है । फिर भी सरकार और बिजली बोर्ड इस बारे में पूरी तरह से 'जागरूक है ।

**श्री नेकी राम :** अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हू कि सारे प्रदेश में कितने सब–स्टेशन हैं और जो बिजली के बिल है क्या वे वक्त पर दिए– जाते हैं या नही? मन्त्री जी यह डिटेल भी बताएं कि एक एस० डी ० ओ० के पास कितने ट्रासफारमर होते है जिनको वह कन्ट्रोल करता है ?

**श्री अध्यक्ष :** यह रैलेवैटं सवाल नही है ।

**ठाकुर बहादुर सिंह :** स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी के नोटिस में यह बात है कि बहुत से सबस्टेशन भी ओवर लोड चल रहे हैं, अगर हैं तो क्या उनकी कैपेसिटी डबल करने का इरादा है? मेरे हल्के में नाथुपुर सब स्टेशन पर ज्यादा लोड है, क्या उसके 'ट्रांसफारमर को बदलने का प्रोग्राम है?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, जिसे तरह से ट्रांसफारमर पर लोड इनक्रीज होता है उसी तरह से

टोटल ट्रांसफारमर्ज का लोड होने की वजह से सब–स्टेशन पर भीं लोड पड़ता है । निरन्तर यह बात, मौनिटर की जाती है ' जहां जरूरत होती है वहां रिप्लेसमैंट भी की जाती है और ऐडीशन भी की जाती है । इसलिए सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है । यह ठीक है कि चूंकि सिस्टम बहुत जल्द ओवर लोड हो रहा है इसलिए वह ऐट पेस नहो रह सकता । अगर ऐडवांस में ही सारा सिस्टम अपग्रेड करदिया जाए तो ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी । परन्तु इसके लिए साधनों की आवष्यकता है । फिलहाल' जैसे जैसे जरूरत– है हम इसे अपग्रेड करने लग रहे हैं ।

**चौधरी साहब सिंह सैनी :** स्पीकर साहब, यह बात तो सभी को मालूम है कि सारी स्ट्रेट में साउंड वाटर का लैवल बहुत नीचे जा रहा–है विशेषकर कुरुक्षेत्र जिले' में । क्य इस वाटर लैवल को बढ़ाने के लिए सरकार कोई प्रयत्न कर रही है ?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, वाटर लैवल के नीचे जाने के दो प्रमुख कारण हैं । एक तो अंडर ग्राउंड वाटर को ऐक्सप्लायटेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि. ट्यूबवैल बक्र गिनती में लगाए जा रहे हैं । ट्यूबवैल्ज के लिए जो लैंड मौर्गेज बैक लोन देता है उसके लिए सरकार कन्ट्रोल करती है कि 85 प्रतिशत से ज्यादा लोन न दिए जाए । लेकिन प्राईवेट लोग जो अपने पैसे से ट्यूबवैल लगाते हैं उस पर हमारा कोई नियन्त्रण नही है । इसलिये कई एरियाज मे 100 प्रतिशत से ज्यादा पानी की ऐक्सप्लायटेशन हो चुकी है । अगर अच्छी रेन फाल न हो तब

भी पानी का लैवल नीचे चला जाता है । आज बहुत से एरियाज में पानी नीचे जा रहा है । इसके लिए हम लोगों में प्रचार करते है कि पानी की एक्सप्लायटेशन न की जाहू । दूसरे कुरक्षेत्र और अम्बाला के एरियाज में कुछ स्कीम्ज हुं जिनके बारे में पहले भी बताया गया है कि दो नान नहरे जमुना से निकाल रहै हैं । यह एक मल्टी परपज रकीम है । इम स्कीम के तहत हम जहां पैडी गिरयाज को फसल के लिए पानी देंगे वहां पानी री–चार्ज भी होगा ।

**चौधरी कुन्दन लाल :** स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जीं से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का नए ट्रांसफारमर खरीदने का विचार –है, अगर है तो कब तक खरीदेगे ?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, पांच हजार ट्रांसफारमर तो अब से पहरने लगाए जा चुके है और तीन हजार और लगेंगे । ये निरन्तर लगते रहते हैं । इनमें से अधिकतर बिजली बोर्ड खरीदता है बाकी कुछ हमारा वर्कशाप भी बनाता है । सरकार तो पालिसी देती है कि इतने ट्रांसफारमर चाहिए और उनको खरीदता है बिजली बोर्ड । यह काम नो निरन्तर चलता रहता है ।

**श्री भले राम :** स्पीकर साहब, में जानना चाहता हूं कि जब ये टयूबवैल्ज लगाए थे उस समय वाटर टेबल क्या था और

अब कितना है और अगर कई सॉल बारिश न हो तो वाटर टेबल कितना और नीचे चला जाएगा ?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, भले राम जी के ट्यूबवैल का तो उन्ही को पता होगा । मुझे तो पता नही कि ये कौन से टयूबवैल का पूछ रहे हैं । जनरली बहुत ज्यादा टयूबवैल्ज लगने मे पानी बहुत ऐक्सप्लायट हो गया है ।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़ :** मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भी ट्रांसफारमर ओवर लोड की वजह से जल जाता है वह कई कई महीनों तक बदला नही जाता । इस वजह से किसान बहुत दुखी होते हैं । क्या ऐसा करेंगे कि जहां ट्रांसफारमर ओवर लोड हो जाए वहां अफसरों को हिदायत. करेंगे कि पुराने ट्रांसफारमर को फौरन बदल दें । जो अफसर इस बात की परवाह नहीं करते क्या उनको सजा देंगे तथा–आगे के लिए हिदायत करेगे कि ऐसा न हो?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** सर, ये तो पहले से ही हिदायतें हैं कि जव कोई ट्रांस– फारमर जल, जाये तो उसको जितना जल्दी हो सके वदल दिया जाये । इनका यह फरमाना कि कई–कई महीनों तक ट्रांसफारमर बदले नहीं जाते, ठीक बात नहीं है । इस समय तो यह सिचुएशन है कि यदि ट्रांसफारमर जल जाता है तो उसको बदलने में 5–7 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता । आज से 4– 5 महीने पहले जो? 6 महीने का समय था

उस दौरान जाए? हुए ट्रांसफारमरों को बदलने में जरूर कुछ देरी हुई थी । उस समय जले हुए ट्रांसफारम को बदलने की बड़ी सीरियस समस्या हो गई थी । उसका कारण यह था कि ट्रांसफारमर्ज मे जो आयल डालना होता है और जिस फर्म से वह आयल लेना था उसका सैम्पल डिलीवरी से पहले टैस्ट करवाया गया वह फेल हो गया जिसकी वजह से उस वक्त हमें ट्रांसफारमर्ज रिप्लेस करने में काफी दिक्कत हुई थी । इसलिए उस समय इस ट्रांजैक्शन में और आयल खरीदने में काफी गैप होने की वजह से ही दिक्कत आई थी । उस समय हमारे पास बैकलोग इकट्ठा हो गया था । तेल आने के बाद जितना जल्दी हो सका जले हुए ट्रांसफारमर्ज मे तेल बदला । इस समय यह स्थिति है कि यदि कोई ट्रांसफारमर जल जाता है तो उसको बदलने में फार दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता ।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़ :** मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या भविष्य मे ट्रांसफारमर्ज के ओवर लोड होने से पहले या उनमें तेल की कमी होने से पहले ही तेल डालने का या उनको बदलने का कोई प्रबन्ध कर देंगे ताकि ट्रांसफारमर कम से कम जरर सकें?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, ट्रांसफारमर्ज अकेले ओवरलोडिंग की वजह सेही नही सड़ने । कई बार लोग उनमें छेड़–छाड़ करते रहते हैं । गांव के अन्दर लोग ट्रांसफारमर्ज को अपने आप ही ओन–ओफ करते रहते हैं । दूसरे

कई बार बोर्ड के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से भी ट्रांसफारमर जल जाते हैं । अकेले ओवरलोडिंग ही ट्रांसफारमर जलने का कारण नहीं है ।

**श्री कंवल सिंह :**स्पीकर साहब, पहले बिजली की लाईनों में ताम्बे की तार लगी होती थी लेकिन उनकी चोरी होने की वजह से बाद में वे बन्द कर दी गई और उनके स्थान पर ऐलूमिनियम की तार इस्तेमाल की जाने लगी है । मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसे भी वाक्यात होते हैं कि बोर्ड के कुछ कर्मचारी ट्रांसफारमरर्ज का कुछ आयल टैम्पर कर लेते हैं जिसकी वजह से वाद में ओवर लोड होने के कारण ट्रांसफामरर्ज सड़ जाते हैं या फेल हो जाते हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का केस इनके नोटिस में आया है, यदि आया है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** मैं यह नही कहता कि विजली बोर्ड के कर्मचारी हेरा–फेरी नहीं करते होंगे बिजली बोर्ड मे लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं । हरेक कर्मचारी की ईमानदारी की कसम भी नही उठाई जा सकती । कोई विशेष शिकायत इनके पास हो तो हमें बतायें, कार्यवाही करेंगे । दूसरे बोर्ड के नोटिस में भी यदि ऐसी कोई शिकायत आई होगी तो उस पर बिजली बोर्ड ने जरूर कार्यवाही की होगी ।

**मास्टर राम सिंह :** स्पीकर साहेब, सारी स्टेट के अन्दर वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है । वाटर लैवल कम होने की वजह से लोगों ने अपने ट्यूबवैल्ज की मोटरें पानी उठाने कें लिए काफी गहरे गड्ढे खोद कर लगाई हुई हैं ताकि पानी आसानी से उठ सके । बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है औ पानी भर जाने के बादइनमें फिर गैस बन जाती है 1 इस गैस की वजह से मेरे हल्के क्एय कुछ गांवों में कई मौतें हो चुकी हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ये ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि इन गड्ढों में गैस पैदा न हो सके?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, जब कोई ट्यूबवैल या कुआ इस्तेमाल नहीं होता तो उसमें गैस भर जाती है । यह गैस खासकर बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भरने की वजह से इकट्ठी हो जाती है । इसके लिए तो सरकार यही कर सकती है कि लोगों को डग वारे में ऐजूकेट किया जाने । सवसे ज्यादा सेवा ये अपने इलाके के लोगों की यही कर सकते हैं कि बरसात के बाद जब वे ऐसे बन्द पड़े ट्यूबवैल्ज या कुओं से पानी निकालें तो पहले उन गड्ढों में रस्सी डोल वगैरह डालकर एयर को पानी में से निकाल दें तो अच्छा रहेगा । ऐसी गैस को खत्म करने के लिए कोई मैडिसन हमारे ध्यान में नहीं है । यदि इनके ध्यान में हो तो हमें बता दें, उसका प्रबंध हम करवा देंगे ।

**ठाकुर बहादुर सिंह :** स्पीकर साहब, मंत्री जी अपने विभाग के बारे में बहुत वाकिफ हैं । ये हर सवाल का बड़ा

माकूल–जवाब देते हैं । कल भी इन्होने एम० आई० टी ० सी० मे सम्बन्धित एक सवाल के बारे में बताया कि लोग सीमेंट खरीद लेते हैं या इटे' खरीद लेते हैं । आज भी ये कह रहे हैं कि लोग अपने–आप ही ट्रांसफारमर्ज को ओन–ओफ करते रहते हैं जिसकी वजह से ट्रांसफारमर्ज जल जाते हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या मारा कसूर लोगों का ही है, इनके कर्मचारियों का कोई कसूर नही है?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** मैंने यह कभी नही कहा कि सारा कसूर केवल किसानों का ही है । माननीय सदस्य अपनी बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं । महकमे का भी कसूररू हो सकता है और किसानों का भी कसूर हो सकता है । महकमा और किसान दोनों एक ही हैं । किसानों के परिवारों में से ही 90 प्रतिशत आदमी बिजली बोर्ड में काम कर रहे हैं और वही लोग खेती कर रहे हैं । जब कोई पर्टिकुलर शिकायत हमारे पास आती है तो उस पर बिजली बोर्ड जरूर कार्यवाही करता है । अब कोई इनके पास पर्टिकुलर शिकायत हो तो हमारे नोटिस में लाये हम उस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे । बोर्ड अपना कसूर भी मानने के लिए तैयार है ।

**चौधरी लीला कृष्ण :** स्पीकर साहब. इन्होंने मेरे सवाल के ''बी'' भाग का उत्तर नहीं दिया है । फतेहाबाद कांस्टिचुऐंससी में इस समय भी 25 के करीब ट्रांसफारमर्ज पिछले 2 महीनों से जले पडे शै और वे अभी तक बदले नहीं जा सके है । क्या मंत्री

जी इसकी इन्कवायरी करवा कर उनको बदलवाने की कोशिश करेंगे ?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेबाला :** ''दी' ' पार्ट का जवाब भी मैंने उस समय दे दिया था, शायद इन्होंने सुना नहीं है । जहां तक इस बात का सवाल है कि पिछले दो महीने से इनके एरिया में 25 के करीब ट्रांसफारमर जले हुए हैं और अभी तक बदले नहीं जा सके हैं, ऐडी बात यी हो सकती । माननीय सदस्य आज से पहले कभी भी यह बात मेरे नोटिस में नहीं लाये । अब ये मुझें बता दें कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी डेटस से ट्रांसफारमर जले हुए हैं, उनको बदलवा दिया जायेगा । दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उनको न बदले जाने में रिस किसी भी कर्मचारी /अधिकारी का दोष होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे । लेकिन मुझे अभी भी इस बारे में डाउट है कि वहां पर दो महीने से जले हुए ट्रांसफारमर्ज बदले नहीं गए हैं ।

**चौधरी लीला कृष्ण :** स्पीकर साहब, जब पिछले दिनों बिजली की कमी हो गई थी तो उस समय किसानों के लिए मिस्त्रियों ने बाजार में कुछ केपेसिटर बना दिए जो सिंगल फेज को 3 फेज का कर देते थे । लेकिन मिस्त्रियों ने जो देसी कैपेसिटर बनाए थे उनसे मोटरें जल गई फिर भी डिपार्टमैंट ने कहा कि ये कैपेसिटर जायज हैं और किसान लगा सकते हैं । क्या मंत्री जो कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि ऐसे कैपेसिटर बनाये जायें जिनसे किसानों की मोटरें जलने से बचाई जा सकें ?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** सर, बिजली बोर्ड ने यह फैसला किया था कि चाहे कोई इण्डस्ट्री हो और चाहे कोई किसी किसान का ट्यूबवैल हो जब तक वे कैपेसिटर नहीं लगायेंगे उस वक्त तक उनको बिजली का कनैक्शन नही दिया जायेगा । पावर फैक्टर को मेनटेन करने के लिए कैपेसिटर बहुत जरूरी है । लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसानों ने कैपेसिटर नहीं लगाये । हम समय समय पर फारमर्ज को नए कनैक्शन देने के लिए डेट ऐक्सटैंड करते रहे हैं कि आप कैपेसिटर लगा लें आपको कनैक्शन दे दिया जायेगा लेकिन किसानों ने हमारी इस बात की तरफ सुआन नहीं दिया । टूसरे किसानों ने भी कैपेसिटर लगाया जाना उचित नहीं समझा । बाद में फिर बोर्ड ने फैसला लिया कि फारमर्ज को कैपेसिटर न लगाये जाने से छूट दे दी जाये और उनके कनैक्शन रीलिज कर दिए जायें । लेकिन इण्डस्ट्रीज पर अभी भी यह कन्डीशन लगी हुई है कि जब तक वे कैपेसिटर नहीं लगा लेंगे तब तक उनको बिजली का कनैक्शन नहीं दिया जायेगा । सरकार और बिजली बोर्ड कोशिश करता– रहा है कि किसान अपनी सुरक्षा के लिये कैपेसिटर लगाये । जहां तक मुझे मालूम है कि कैपेसिटर लगाने के लिए शायद सरकार की तरफ से कुछ सबसिडी भी दी जाती है । जहां पर सरकारी तौर पर कैपेसिटर लगाये गए थे वहां पर लोगों ने यह समझा कि इन कैपेसिटर से तो बिजली बोर्ड को फायदा होगा, हमें नहीं और उनको उतार दिया ।

**Amount spent on construction of school buildings**

***1284. Chaudhri Azmat Khan :** Will the **Minister** for Education be pleased to state--

(a) whether any amount has been spent on the construction of school buildings in the State during the year. 1986-87 (up to 31-1-1987); and

(b) if so, district-wise and block-wise details thereof ? -

**Education Minister (Shrimati Sharda Rani) :**

(a) Yes.: Sir.

(b) District-wise/Blcck-wise statement of the amount spent during 1986-87 (up to 31-12-86) on the, construction of school buildings are laid on the Table of the House.

**Statement**

| Sr. | Name of school | C.D . Block. | Amount' spent (Rs. in lakhs) |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| | District Ambala | | |
| 1. | Govt. Primary School, Khanpur | Barara | 4.95 |
| 2: | Govt. Primary School; | Pinjore | 1. 95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Charnia | | |
| 3. | Govt. High School Balana | Ambala- | 1 .13 |
| 4: | Govt. High School, Nankpur | Chandimandir | 3.77 |
| | District Bbiwani | | |
| 1 | Govt. Primary School, Badala | Dadti-I | I .74 |
| 2 | Govt. Primary School, Pur | Bawani Khera | 0.01 |
| 3 | Govt. Middle School, Chandawas | Bhiwani | 2.38 |
| 4 | Govt. Middle School, Sighani | Loharu | 0.28 |
| 5: | Govt. High School,Jamalpur | Bawani Khera | 7.20 |
| 6. | Govt. Primary School, Birban Bhiwani | Urban | 1 .*54* |
| 7 | Govt. Primary School, Shardanand Bhiwani | Do | 3.44 |
| 8 | Govt. Primary School; Tiyan, Bhiwani | Do | 0.01 |
| 9. | Govt. Primary School; Manan Pana Bhiwani | Do | 1.71 |
| | District Faridabad | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Govt. Primary School, Palri | Hodal | 0.01 |
| 2. | Govt. High School Badouli | Hodal | 2.98 |
| 3. | Govt. Primary School, Sahurur | Ballabgarh | 0:03 |
| 4. | Govt. High School, Mohana | to | 0:71 |
| 5. | Govt. High School, Chhainse | Hathin | 1.81 |
| 6. | Govt. Middle School; Pirthala | Palwal | 1.73 |
| 7 | Govt. Girls High .School, Palwal | Urban | 0:85 |
| 8 | Govt. High School, Faridabad | Do | 1.44 |
| | District Gurgaon | | |
| 1. | Govt. Middle School, Bandhwadi | Sohna | 0.02 |
| 2. | Govt. High School, Harchandpur | Do | 1.33 |
| 3. | Govt. Middle School, Sewari | Gurgaon | 0.03 |
| 4. | Govt. High School, Patli Station | Do | 0.05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Govt. Primary School, R.R. Camp, Gurgaon | Urban | 0.69 |
| 6 | Govt. Primary School, Railway Station, Gurgaon | Do | 0.02 |
| 7 | Science Block in SCERT Gurgaon | Do | 2.12 |
| | District Hisar | | |
| 1 | Govt. Primary School, Gamra | Narnaund | 0.32 |
| 2 | Govt. High School, Kapro | Do | 0.03 |
| 3 | Govt. Girls Middle School, Chuli-Bagrian | Adampur | 0.01 |
| 4 | Govt. Middle School, Bhoda Hoshnak | Fatehbad | 0.01 |
| 5 | Govt. High School, Kanwari | Hansi-I | 0.74 |
| 6 | Govt. Girls High School, Barwala | Urban | 0.01 |
| 7 | Govt. Sr. Secondary School, Hansi | Do | 0.05 |
| | District Jind | | |
| 1 | Govt. Primary School, Deola | Rajound | 1.09 |
| 2 | Govt. High School, Deola | Do | 2.23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Govt. Primary School, Nandgarh | Julana | 0 . 30 |
| 3 | Govt. Middle School, Dhathrath | Safidon | 0.01 |
| 4 | Govt. High School, Dhathrath | Do | 1 .87 |
| 5 | Govt. Middle School. Sindhvi Khera | Jind | 2.32 |
| | District Kurukshetra | | |
| 1. | Govt. Middle School, Kasan | Kaithal | 1 .54 |
| 2. | Govt. High School, Keorak | Do | 0.44 |
| 3. | Govt. Middle School, Kurd | Shahbad | 0.02 |
| 4. | Govt. Primary School, Phoji group | Pehowa | 0.03 |
| 5. | Govt. Girls Primary School, Pehowa | Urban | 0.04 |
| 6.. | Govt. Primary School., Ladwa | Do | 0.01 |
| 7. | Govt. Gills Sr, Secondary School, Kaithal | Do. | 0.2 |
| | District Mahendragarh | | |
| 1 | Govt. Middle School, | Khol | 0-.19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bhotawas Ahir | | |
| 2 | Govt. Middle School, Seeha | Do | '2.'30 |
| 2 | Govt. Primary School, Nangli Paraspur | Bawal | 2:89 |
| 3 | Govt. Girls High School, Mahendragarh | Urban | 6 :88 |
| | District Rohtak | | |
| 1 | Govt. Middle School, Retauli Kabulpur | Kalanaur | 0.03 |
| 2 | Govt. High School, Sampla | Sampla | 2.71 |
| | District Sirsa | | |
| 1. | Govt. Girls Primary School, Baraguda | Baraguda | 0.01 |
| 2. | Govt. High School, Phaggu | Do | 1:07 |
| 3. | Govt. High School, Rori | Do | 1.90 |
| 4. | Govt. High School, Baraguda | Do | 0.03 |
| 5. | Govt. Middle School, Sawant Khera | Dabwali | 0.42 |
| 6.. | Govt. Sr. Secondary School, Sirsa | Urban | 0.15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | District Sonepat | | |
| 1. | Govt. Primary School, Mail | Ganour | 1.83 |
| 2. | Govt. High School, Khrbra | Do | 1.44 |
| 3. | Govt. Middle School, Kasandi | Gohana | 1.45 |
| 4. | Govt. Girls High School, Beodhal | Do | 0.05 |
| 5. | Govt. Girls Middle School, Bhatgaon | Sonepat | 1.74 |
| 6. | Govt. Primary School, Nayat | Gohana | 0.60 |
| 7 | Govt. Girls High School, Rohna | Sampla | 4.55 |
| | District Karnal | | |
| 1. | Govt. Primary School, Palri | Samalkha | 0.65 |
| 2. | Govt. Middle School, Didwadi | Samalkha | 0.30 |
| 3. | Govt. Primary School, Bir-Bhandari | Madlauda | .0.02 |
| 4. | Govt. High School, Kheri Sharafli | Assandh | 4.29 |
| 5. | Govt. High School, Raison | Nilokheri | 0.03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Govt. High School, Prem Nagar Karnal | Urban | 1.42 |
| | | Grand Total : | 91.97 |

**चौधरी अजमत खां :** स्पीकर साहब, मुझे जो डिटेल चाहिए थी, वह मिल गई है ।

**सेठ राम दास धमीजा :** स्पीकर साहब, अम्बाला जिला स्कूलों के मामले में बहुत पीछे है । अम्बाला जिले में भी अम्बाला कैट तो बहुत ही पीछे है । अम्बाला कैट के अन्दर गवर्नमैंट के 12 स्कूल हैं । वहां पर स्कूलों की बिल्डिंगें 40 साल से भी अधिक पुरानी बनी हुई हैं । अम्बाला कैट के अन्दर एक हाई स्कूल की विल्डिग की हालत तो बहुत ही चिन्ताजनक है । इसके अलावा कई स्कूलों के कमरों की छतों की भी बुरी हालत है । वहां पर सरकार ने कई सालों से नए स्कूल भी नहीं बनाये हैं । मेरे हल्के में सरकार ने पिछले पांच सालों में सात स्कूल अपग्रेड किए हैं, उनके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं । स्पीकर साहब, मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे हल्के के जिन स्कूलों की बिल्डिंग्ज की कन्डीशन वहुत खराब है उनकी रिपेयर जल्दी से जल्दी कराई जाये ।

**श्रीमती शारदा रानी :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि वहां पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, ऐसी बात नही है । वर्ष 1986–87 में अकेले अम्बाला जिले के अन्दर 11 लाख 80 हजार रुपया स्कूलों की बिल्डिंगों की रिपेयर पर और नई बिल्डिंगें बनाने

पर खर्च हो चुका है और मेवात में गुड़गांव जिले को छोड़ कर 1982–83 से लेकर अब तक 63 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं ।

**श्री मोहन लाल पिपल :** स्पीकर साहब मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि पिछले साल नयी और खंडहर बिल्डिगों को बनाने के लिए कितना पैसा दिया है? सरकार ने मेरे हल्के में पातली हाजीपुर गांव के लिए 14 लाख रुपया दिया है और सिवाड़ा मिडल स्कूल के लिए 10 लाख रुपया दिया है । क्या मंत्री महोदया बताने का काट करेगी कि वहाँ पर अभी तक काम क्यों नहीं शुरू किया और अगर शुरू नहीं किया तो कब तक शुरू करने का विचार है?

**श्रीमती शारदा रानी :** अध्यक्ष महोदय, इस साल सिवाडी मिडल स्कूल पर भी कुछ पैसा खर्च हो चुका है और पातली हाजीपुर पर भी खर्च हो चुका है । दोनों जगहों पर काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही काम पूरा हो जायेगा ।

**चौधरी लीला कृष्ण :** स्पीकर साहब, गवर्नमैंट गर्ल्ज हायर सैकंडरी स्कूल फतेहाबाद और गवर्नमैंट बुआयज हायर सैकंडरी स्कुल, मोहम्मदपुर सोत्तर सैक्शन हो चुके हैं लेकिन इस सारी लिस्ट में फतेहाबाद का कहीं नामोनिशान ही नहीं है । मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि वे इस लिस्ट में सै क्यों निकाल दिये गये?

**श्रीमती शारदा रानी :** अध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट सिर्फ 1986–87 की है और जो रुपये मंजूर हुए थे वे सन 1985 –86 में हुए थे और तभी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल मिली थी तो इन स्कूलों में काम चलता रहा है । पी ० डब्ल्यू० डी ० से जो रिपार्ट सन 1986–87 की मिली है वह केवल उसी की है जो पैसा 1986– 87 में खर्च किया गया था ।

**श्री नेकी राम :** स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने जो विवरण. सदन के पटल पर रखा है उसको देखते हुए यह प्रतीत होता है कि हिसार जिले को बहुत थोड़ा पैसा दिया गया है । मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि स्कूलों की बिल्डिग्ज की रिपेयर के लिए पैसा बांटने का क्या तरीका है ?

**श्रीमती शारदा रानी :** स्पीकर साहब, कम पैसा नहीं दिया गया, काफी दिया गया है लेकिन सिर्फ 1986–87 में जिन स्कूलों में काम चलता रहा है उनका ही. ब्योरा दिया गया है

**श्री नेकी राम :** स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाव नहीं आया । (विघन )

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री महोदया यह कह रही है कि पैसा काफी दिया गया है लेकिन मन् 1986–87 में जिन स्कूलों में काम चलता रहा है उनका ब्यौरा दिया गया है ।

**श्री बनारसी दास बाल्मीकि :** अध्यक्ष महोदय स्कूलों से जो बिल्डिग फन्ड वसूल किया जाता है, क्या उस फन्ड को उन्हीं स्कूलों में लगाये जाने का विचार है ?

**श्रीमती शारदा रानी :** जी हां । पहले बिल्डिग फन्ड कौमन पूल में आ जाता था लेकिन अब यह क्राइटेरिया बना दिया है कि 70 परसैन्ट बिल्डिंग फन्ड इन्सीच्यूशन में रहेगा औररू तीस परसैन्ट डी ० ई० ओ० के पास जायेगा । इसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है, वह अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सकती है । इस करे मे मैं डिटेल बता देती हूं । प्राथमिक विद्यालय स्तर पर यह कमेटी पांच हजार, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर आठ हजार और उच्च विद्यालय स्तर पर दस हजार तक खर्च कर सकती है । दिन प्रति दिन की मरम्मत इस तरह से हो सकती है । इसके अलावा पचास हजार रुपये तक की मरम्मत का काम डी ० ई० ओ० से परमिशन ले कर कर सकते हैं ।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़ :** स्पीकर साहब, हांसी सीनियर सैकन्डरी स्कूल की बिल्डिंग पिछले दस साल से अन–सेफ डिक्लेयर हो चुकी है और इसमें हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं । वहां पर आठ कमरे पब्लिक ने बनाये थे । उस स्कूल का 26 लाख रुपये का ऐस्टिमेट मंजूर हो चुका है लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल अभी तक नही मिली है । मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि उसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल दिला कर उसका काम शुरू करवायें ।''

**श्रीमती शारदा रानी :** यथा सम्भव शीघ्र करेंगे ।

**श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया :** स्पीकर साहब, मेरे हल्के राधाढानी गांव के स्कूल के लिए सवा छः लाख रुपया मजूर हुआ था लेकिन यह पता नही लगा कि वह पैसा वापिस क्यों हो गया? मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि क्या वह पैसा उस स्कूल के लिए वापिस दिया जायेगा? दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहती है कि सन 1987–88 में स्कूलों के लिए कितने पैसे का प्रावधान कर रहे हैं?

**श्रीमती शारदा रानी :** अध्यक्ष महोदय, सन् 1987–88 में 19० लाख रुपये का प्लान बजट में है लेकिन अलग–अलग स्कूलों. के बारे में चूकि इस समय मेरे पास फिगर्ज नही हैं इसलिये मैं अलग–अलग स्कूलों के बारे में नहीं बता सकती ।

**श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया :** स्पीकर साहब मै विधायक हू । मेरे हल्के का पैसा वापिस चला गया है इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि वह क्यों वापिस गया और उस स्कूल को वापिस मिलेगा या नहीं?

**श्री अध्यक्ष :** वे कहती है कि इस समय उनके पास एक–एक स्कूल का रिकार्ड नहीं है ।

**श्री भले राम :** स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि बिल्डिंग फण्ड का कौमन पुल में कितना पैसा है और स्कूलों के पास कितना है ?

**श्रीमती शारदा रानी :** 70 परसैन्ट स्कूल के पास रहता है और तीस परसैन्ट डिस्ट्रिक्ट लैवल पर हैडक्वार्टर पर रहता हैं ।

**श्री अध्यक्ष :** उनका यह सवाल नहीं है । वे यह जानना चाहते है कि टोटल बैलेन्स कितना है ?

**श्रीमती शारदा रानी :** टोटल बैलेन्स की फिगर डस वक्त मेरे पास नहीं है ।

**चौधरी अजमत खां :** स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदया ने बताया कि मेवात एरिया में 63 लाख रुपया स्कूलों पर खर्च कर चुके हैं । मेरे पास मेवात एरिया के आकड़े मौजूद है । इन आकड़ों के हिसाब से इस साल हथीन ब्लाक में एक स्कूल में 1 लाख 81 हजार रुपये खर्च हुए हैं और गुड़गांव जिले में– सारे मेवात हिस्से में एक भी स्कूल में एक पैसा नहीं लगाया है । मंत्री महोदया ने 63 लाख रुपये की बात की है । हो सकता है ये मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की बात कर रही हों । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐजूकेशन डिपार्टमैंट ने अपने फन्ड से स्कूलों के लिए कितना पैसा दिया है? जो पैसा मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के नाम सै दिया जा रहा है उस सैसे को इस पैसे में क्यों शामिल करके बताया जा रहा है ? इस साल गुड़गांव जिले के एरिया के ब्लाक में 4.26 लाख रुपया खर्च हुआ है । नूह, तावडू, फिरोजपूर झिरका और नगीना ब्लाकों में एक पैसा भी खर्च नहीं हुअ', जब

कि फरीदाबाद जिले में इस साल नौ लाख से ऊपर खर्च हुआ है । हथीन में 1.81 लाख रुपया खर्च हुआ है ।

**श्रीमती शारदा रानी :** अध्यक्ष महोदय, 40.90 लाख खाया मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड को प्राइमरी स्कूलों के लिए मंजूर हुआ था, वह खर्च हो चुका है । वह 40. 90 लाख रुपया ऐजूकेशन डिपार्टमैंट के फन्ड से गया है और वह पैसा मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की डिस्पोजल पर रखा गया था । इस पैसे से गुडगांव जिले के अन्य स्कूल कवर नहीं हुए । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव जिले के लिए सन 1986–87 में एन ० आर ० ई ० पी ० के तहत हमने अपना 25 परसैंट शेयर दिया जोकि. करीब 7.30 लाख रुपये था । उसमें से भी चार लाख के करीब मेवात की तरफ खर्च हुआ है । मेवात में सब से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों के कमरे बने हैं और सब से ज्यादा पैसा वहां पर खर्च किया गया है । यह पै सा वहां की स्थिति को देखते हुए खर्च किया गया शै ।

**चौधरी साहब सिंह सैनी :** स्पीकर साहब ऐजूकेशन डिपार्टमैंट की ओर से अलग अलग ढंग से पैसा दिया जाता? है । क्या पैसा देने के बारे में कोई. क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है क्योंकि स्कूलो की बिल्डिंग्ज की रिपेयर करने के लिए हर जिले के हर हल्के में जरूरत होती है । मैं यह जानना चाहता हू कि क्या आप बिल्डिंग्ज की कंडीशन के बारे में डी ० ई ० लो ० या

हैडमास्टर से रिपोर्ट मंगवाते हैं, यदि हां, नो इसके लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है ?

**श्रीमती शारदा रानी :** अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं था । सन 1982 में प्लान वजट से इसके लिए पैसा देना शु रू हुआ है । पिछले प्लान में 1400 लाख रुपए के करीब पैसा रखा गया और इस प्लान में 1700 लाख रुपये के करीब रखा गया है जिसमें से 360 लाख रुपया सन 1985–86 में मिला था और 364 लाख रुपया पिछले साल मिला है । इस साल के प्लान बजट में 190 लाख रुपया रखा गया है और नौन प्लान से भी इतने ही लाख हो जायेगा । जिन स्कूलों की हालत खराब है, उनका हमारे पास पी ० डब्ल्यू ० डी ० से ऐस्टिमेट बन कर आता है । उन ऐस्टिमेटस के मुताबिक और अपने बजट के मुताबिक हम ऐडमिनिस्टेर– टिव ऐप्रूवल देते हैं फिर वह काम पी ० डब्ल्यू ० डी ० द्वारा किया जाता है । लेकिन ऐसा कुछ ही स्कूलों में हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन का स्कूल खराब नहीं होता है वह भी ऐस्टिमेट बनवा कर डिपार्टमेंट में भेज देते हैं जिस वजह से पैसे की, कमी हो जाती है । इसके अलावा कहीं कहीं तो बहुत बुरी हालत होती है और रिपेयर करने के लिए इल्कीव्यूशन के पास कुछ नहीं होता । उनके पास कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं होता और न ही किसी अधिकारी की उधर नजर जाती है कि वहां पर रिपेयर करवाई जाए । वे छोटी–मोटी मरम्मत के लिए भी तरसते हैं । अब तक जो

बिल्डिंग फन्ड जमा होता था वह कौमन पूल मैं चला जाता था और विभाग की मर्जी से खर्च होता था लेकिन अब नई पालिसी के अनुसार इन्सीच्यूशन की मर्जी से खर्च होगा । पहले छोटी मोटी मरम्मत न होने से काम और ज्यादा बढ़ जाता था । हमने अब इसको काफी डी–सैन्ट्रेलाइज कर दिया है जिससे सभी इन्सीच्यूशन्ज का भला हो सकेगा ।

**श्री लछमन सिंह :** स्पीकर साहब, मेवात की हालत काफी कमजोर है इसलिए उसकी स्थिति को देखते हुए पैसा दिया है । इसलिए मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि जो मोरनी हिल्ज ओर छछरौली साइड के पिछड़े हुए और गुरबत से दबे हुए इलाके हैं, बिलों पावटी लाईन हैं, क्या उन इलाको आइन्दा बजट में ज्यादा पैसा देने के बारे मैं विचार करेंगे? उन स्कूलो की बड़ी खस्ता हालत है और वहां जाने के लिए कोई सड़क भी नहीं है ।

**10.00 बजे ।**

**श्रीमती शारदा रानी :** माननीय सदस्य उन स्कूलों के नाम हमें लिख कर दे दें । उनकी बात पर अवश्य गौर किया जायेगा । बहिन शान्ति देवी. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से और मंत्री महोदया से एक निवेदन करना चाहती हूं । यह प्रश्न बहुत विशाल बन गया है इसलिए मैं भी करनाल के हालात आपके सामने पेश कर दू । मैं पिछले 4 साल से हर सैशन में यह कहती आ रही हूं कि प्रौपर करनाल में? प्राइमरी

ऐजूकेशन सरकार के हाथों से बिल्कुल बाहर निकल चुकी है । बाकी जगहों का तो मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे इस बात का कोई लाभ नजर नहीं आया । वहां पर एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसकी बिल्डिंग में बच्चे बैठ कर पढ़ सकें । उन स्कूलों में अच्छे घरों के बच्चे नहीं आते केवल गरीब बच्चे ही आते हैं । वहां पर बच्चों के बैठने के लिये कमरे नहीं, टाट–बोरी या दूसरा कोई सामान नहीं है । करनाल शहर में केवल एक प्राइमरी स्कूल का भवन है जो सरकारी है । जब श्री जगदीश नेहरा शिक्षा मंत्री थे, उस समय इनको वह स्कूल की बिल्डिंग दिखाने का मुझे अवसर मिला था । इन्होंने उस स्कूल में बच्चों के बैठने की हालत पर तरस खा कर वहां पर 5 कमरे नये बनाने की इजाजत दी थी । लेकिन आज तक वहां पर वे कमरे नहीं बने हैं । सिर्फ एक तरफ की दीवार बनी है । इस स्कूल की जगह में डंगर और सूअर वगैरह खुले तौर पर घूमते रहते हैं । अगली दीवार अभी भी बननी बाकी रहती है । मुझे दो दिन पहले एक चिट्ठी मिली थी जिसमें यह लिखा है कि करनाल में अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु 5,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी लेकिन अभी तक वह राशि पूरी नहीं भेजी गयी है । अध्यक्ष महोदय, आप ही सोचिए 5 कमरे 5,000 रुपये में कैसे बन सकते हैं? मेरा मती महोदया से नम्र निवेदन है कि 5 कमरे जितने रुपये में बनें, उतना रुपया वहां के लिये प्रदान किया जाये । वहां पर कम से कम एक प्राइमरी स्कूल तो ऐसा हो जिस्में बच्चे अच्छी प्रकार से बैठ सकें । जब से चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री बने हैं, तब से इन्होंने वहां पर

कालेज का भवन तो बनवाना शुरू कर दिया है । ( व्यवधान व शोर ) स्पीकर साहब, आज ही मैं पहली बार बोलने लमी हूं । इसलिए मुझे दो मिनट के लिये तो बोलने का अवसर प्रदान करें । मेरे हल्के का यह बहुत बड़ा दुःख है जो बड़ा लम्बा चौड़ा और गहरा हो चुका है । इसलिये कृपया आप मुझे जरा कह लेने दीजिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ।

**श्री अध्यक्ष :** वैसे आपको यह हक है कि इनकी गाड़ी जब उधर जाये तो रास्ते में रोक लेना ।

**बहिन शान्ति देवी :** स्पीकर साहब मैंने तो इनकी कई बार यह कहा है कि आप उस स्कूल को चल कर देखो लेकिन इनको समय ही नहीं है । मैंने वह स्कूल बी ० ई० ओ० और डी ० ई० ओ० को दिखाया है । उन्होंने वहां पर चल रहे पुराने प्राईमरी स्कूल जो किराये पर है, की जमीन एक्वायर करने के लिये मालिकों की मर्जी से कागजात भेजे हैं । वे पुराने मकान लिए जा सकते हैं और 5 कमरे बनवाने के लिये जो मंजूरी दी गई थी, उसके लिये पैसा पूरा दिया जाये । चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मन्त्री बने हैं, इन्होने करनाल में कालेज के निर्माण का काम शुरू करवाया है । उसके लिये इनकी बहुत–बहुत मेहरबानी है । मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे अपने ही शासन काल में वहां पर जो 6 प्राइमरी स्कूल्ज की बिल्डिग्ज बननी हैं, अगर उन बिल्डिंग्ज को बनवाने की कृपा करेंगे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी । धन्यवाद ।

**श्रीमती शारदा रानी :** स्पीकर साहब, बहिन जी को मैं यह कहना चाहती हूं कि मैंने करनाल प्रौपर के कुछ स्कूल्ज जरूर देखें हैं । जिन स्कूलों की बिल्डिंग्ज बनाने के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल हो चुकी हैं, उनके लिये हम जरूर पैसा देंगे । बहिन जी ने जिस स्कूल का जिक्र किया है उस स्कूल की भी शायद ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल हो चुकी है । (व्यवधान व शोर ) अगर ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल नही मिली है तो भी हम उनके स्कूल को ऐडमिनिस्ट्रे– टिव एप्रूवल देंगे और वहां पर कमरे अवश्य बनवाएंगे । एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं कि पहरने यह स्थिति हुआ करती थी कि लोग बिल्डिंग्ज बना दिया करते थे और सरकार वहां पर स्कूल खोल दिया करनी थी और नन्हें चलाती थी । ऐजूकेशन का वजट पहले इतना नही था । अब प्रोब्लम क्या हुई है कि स्कूल तो हर जगह गाव–गांव में और शहर गहर में हो गये है लेकिन बिल्डिंग्ज नहीं है । शहरों में पहले म्यूनिसिपल कमेटीज बिल्डिंग बनाती थीं । सरकार का शिक्षा विभाग उनका चलाता था लेकिन अव मुश्किल इसलिये हो रही है कि पब्लिक ने यह देख कर कि सरकार यह काम कर ही रही है तो लोगों ने करना वन्द कर दिया है । म्यूनिस्पिल कमेटीज या पंचायतो ने अपना कन्ट्रीब्यूशन देना अब बन्द सा कर दिया है । पचायतें तो अभी भी कही कही पर यह काम कर रही हैं । एन०आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जो ० पी ० गे बहुत कुछ काम हो रहा है । जहां पर लोग स्कूल्ज का काम नहीं कर रहे हौ वहां पर स्कूलों की हालत खराब हो गयी है । अगर इस काम के लिये पव्लिक का

कट्रीव्यूशन नहीं मिलेगा तो सौ करोड रुपये का कम से कम बजट हो तब कही जा कर स्कूलों की बिल्डिंग्ज रिपेयर होंगी और हजार करोड़ रुपये का बजट हो तो एडीशनल बनाये जा सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कितना पैसा सरकार के पास इस काम के लिये रहता है । फिर भी हम फेंज्ड प्रोग्राम बनाकर स्कूलों की बिल्डिंग्ज की स्पिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं । हम सभी स्कूलों को दिखायेंगे और जिनको रिपेयर की जरूरत है, उनको रिपेयर करने की कोशिश की जायेगी ।

**श्री अध्यक्ष :** इसका मतलब यह हुआ कि क्वैश्चन की लम्बाई के हिसाब मे जवाब भी लम्बा हो सकता है । (हंसी )

**ठाकुर बहादुर सिंह :** स्पीकर साहब, मन्त्री–महोदया ने सवाल के जवाब में यह––बताया है' कि स्कूल बिल्डिंग्ज की रिपेयर पर 91.97 लाख रुपया खर्च किया गया है । अपर इसमें सिरसा जिला को देखें तो यह पता चलेगा कि वडा–गूढा ब्लाक मे चार स्कूलों की बिल्डिंगों की रिपेयर पर 3 लाख रुपया खर्च किया गया है जबकि 'डबवाली ब्लौक में 42000 रु० और सिरसा (शहरी क्षेत्र ) में केवल 15,000 रुपया ही खर्च किया गया है । क्या क्राइटेरिया यह है कि जहां 'का 'शिक्षा मन्त्री रहा हो, वहां पर ज्यादा बिल्डिंग्ज बनाई जायेगी क्योंकि वहां के एम० एल० ए० पहले शिक्षा मन्त्री रह चुके हैं '

**श्रीमती शारदा रानी :** यह तो काम शुरू हो गया है । अगर ज्यादा काम होगा तो काम कन्टीन्यू करेगा और चलता रहेगा ।

**चौधरी धर्मवीर गाबा :** क्या मन्त्री महोदया बतायेगी कि जो पैसा तकसीम कर रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है? किसी एक स्कूल के लिये जो 2– 3 हजार रुपये देते हो, क्या वह पैसा सफीशिएंट होता है? दूसरी बात यह है कि पी ० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट पर जो गवर्नमैंट स्कूल्ज नहीं हैं उनकी रिपेयर नहीं की जा सकती। मैं यह जानना चाहता हू कि क्या मच्छी जी ऐसा करेंगे कि सारे स्कूल पी ० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट पर आ जायें ताकि जरूरत के मुताबिक उनकी रिपेयर हो सके?

**श्रीमती शारदा रानी :** अगर वह पी ० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट पर ही किसी स्कूल को लाना चाहते हैं तो हम वह भी ला देंगे । लेकिन यह जो रिपेयर का काम है यह कई सालो से रुका हुआ है । मैंने बताया है कि हम यह काम फेज्ड प्रोग्राम के तहत करेंगे । हम एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी ० के बजट में भी अपना शेयर देते हैं । 1986–87 में भी हमने एक करोड़ रुपयो दिया है । कुछ पैसा लोग इकट्ठा करके देते हैं और कुछ पैसा मैचिग ग्रान्ट के रूप में सरकार देती है । वह पैसा भी इस ओर खर्च होता है । इसके अलावा सरकार से विभिन्न तरीकों सेभी पैसा जाता है । जो स्कूल 'पी ० डब्ल्यू० डी० की लिस्ट मे नहीं होते उनको भी हम कुछ न कुछ पैसा जरूर देते हैं इसके

अलावा पी० डब्ल्यू० डी० भी जरूरत के मुताबिक रिपेयर का काम करता हैं ।

**श्री अध्यक्ष :** 'इनका कहना यह है कि जो आप 2–3 हजार रुपया एक स्कूल के लिये देते हो, इसका क्या फायदा है? यह बहुत कम पैसा है । अब आप शाहबाद को ही देखें । वहां पर केवल 2,000 'रुपया 'ही दिया गया है । इतने कम पैसे से क्या काम होगा ?

**चौधरी धर्मवीर गाबा :** स्पीकर साहब, हमारे यहां भीमबढ़ी गांव के स्कूल के लिये नयी बिल्डिंग बननी है । उसके लिये भी सिर्फ 2,000 रुपये दिये जा रहे हैं । इतने कम पैसे मे क्या बनेगा?

**श्रीमती शारदा रानी :** आपको तो खुश होना चाहिये । इसका मतलब यह हुआ कि आपका काम ऐप्रूव हो गया है । बहुत जल्दी ही काम शुरू होने वाला है । यह तो टोकन मनी दिया गया है । यह बल्डिंग बहुत जल्दी ही बनेगी ।

**श्री कंवल सिंह :** स्पीकर साहब, देहात में जब भी कोई स्कूल अपग्रेड किया जाता है तो उससे पहले गांव वाले बिल्डिग बनाकर देते है, जमीन देते हैं और अपने पास से पैसा भी इकट्ठा करके लगाते हैं और शानदार बिल्डिग बनाते हैं लेकिन उसकी मेटीनेस लोग पू री तरह से नहीं कर पाते है । क्या मन्त्री महोदया इस बात पर विचार करेगी कि जिस वक्त कोई स्कूल अपग्रेड करें

उस वक्त बिल्डिग का स्टैण्डर्ड निर्धारित कर दें कि इस तरह की बिल्डिग होनी चाहिए और जैसे ही गवर्नमैट स्कूल को अपग्रेड करे साइमलटेनियसली गवर्नमैंट उस्को टेकओवर कर ले और उसकी सेन्टीनैस सरकार खुद ही करे?

**श्रीमती शारदा रानी** : अध्यक्ष महोदय, नार्म्ज तो निर्धारित है कि किस तरह की बिल्डिग होनी चाहिये तभी वह स्कूल अपग्रेड कया जाएगा । हम तो चाहते हैं कि सारी रिपेयर्ज गवर्नमैंट करे लेकिन यह सं भव नहीं हो पाता ।

**Filling of posts of teachers in upgraded high schools**

***1282. Chaudhri Lila Kristian :** Will the Minister for Education be pleased to state--

(a) whether any posts of teachers are lying vacant in any of the recently upgraded high sohools in the State: and

(b) if so, the number thereof together with the time by whioh such vacancies are likely to be filled up ?

**Education Minister (Shrimati Sharda Rani) :**

(a) Yes, Sir.

(b) 16 posts of Headmasters, 12 posts of Masters and 8 posts of C&V teachers are lying vacant in the recently upgraded high sohools. Efforts are being made to fill-up these vacancies shortly.

**चौधरी लीला कृष्ण :** स्पीकर साहब, पिछले अधिवेशन में भी बार–बार वेकेन्सीज के बारे में जिक्र आया था और हर बार अश्योरैस मिनती रही कि जल्दी ही वेकेन्सीज फिल–अप कर दी जाएंगी । यह बडा सीरियस मामला है । हैडमास्टर्ज के बिना स्कूल्ज लावारिस पड़े हुए हैं और जे ० बी० टी० टीचर्ज की भी वेकेन्सीज खाली पड़ी हुई हैं । क्या मन्त्री महोदया इस मसले पर वार लैवल पर सोचकर विश्वास दिलाएंगी कि फलां स्पेसिफिक डेट तक वेकेन्सीज फिल–अप कर दी जाएगी ?

**श्रीमती शारदा रानी :** अध्यक्ष महोदय इस साल 303 स्कूल अपग्रेड हुए जिनमें सोलह वैकेन्सीज हैडमास्टर्ज की खाली हैं । इसकी वजह यह है कि हम कुछ मास्टर्ज को प्रोमोट करके लगाते हैं और कुछ मिस्ट्रेसिज को प्रोमोट करके लगाते हैं । होता यह है कि कुछ को दूर जाना पड़ता है या ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहां वे नहीं जाना चाहते और वे प्रोमोशन फोरगो कर देते हैं । हमको कुछ समय तक तो इन्तजार करना पड़ता है और फिर दूसरी लिस्ट बनानी पड़ती है । इस प्रौब्लम की वजह से सोलह जगह खाली पड़ी हैं । डिपार्टमैंट की तरफ से कोई कोताही नहीं है ।

**श्री नेकी राम :** स्पीकर साहब, मेरे हल्के में दो जगह साधनवास की ढाका और तलवाड़ा–तलवाड़ी की ढानी ऐंसी है जहां पर गांव तो एक है लेकिन दो जगह पर बसा हुआ है और वहां पर स्कूल एक जगह से दो किलोमीटर दूर पड़ता है । घग्गर

का इलाका है और वहां पर पानी आ जाता है । बच्चों को स्कूल के लिए पानी मैं से गुजर कर जाना पड़ता है । क्या मन्त्री महोदया ऐसी जगहों पर स्कूल और स्कूल टीचर देने की कृपा करेंगी ?

**श्रीमती शारदा रानी :** स्पीकर साहब, मैम्बर साहव लिखकर दे दें हम देख लेगे ।

**श्री भले राम :** स्पीकर साहब, पहले जो हैडमास्टर लगता था वह बी ०ए ० बी० एड० होता था और हैडमास्टर के प्रोमोशन के लिए आठ सात का तजुर्बा होना जरूरी होता था । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि अव हैडमास्टर के लिए क्यों एस० ए०, बी ० एड० क्वालिफिकेशन रखे दी है ?

**श्रीमती शारदा रानी :** अध्यक्ष महोदय, अब बहुत अच्छे पढे लिखे लोग उपलब्ध हैं । जिनको हम हाई स्कूल का हैड मास्टर प्रोमोट करते हैं उनके लिए एम० ए० होना जरूरी नहीं है लेकिन जिनको हम डायरैक्ट सिलैक्ट करते हैं उनके लिए एम०ए० प्रैफ्रेन्शियल क्वालिफिकेशन है ।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़ :** मन्त्री महोदया ने वताया है कि सोलह हैडमास्टर्ज की जगह खाली पड़ी हैं । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि उन स्कूलों के क्या नाम हैं जहां पर ये जगह खाली हैं क्योंकि मेरे हल्के में भी दो जगहें खाली थीं और

एक पर अभी हैडमास्टर नही पहुंचा है, लिस्ट से पता लग जाएगा कि आया इनकी लिस्ट में वह जगह खाली है या नही है ?

**श्रीमती शारदा रानी :** अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नाम नो उपलब्ध नही है

**श्री कंवल सिंह :** क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि जब किसी स्कूल को अपग्रेड किया जाता है तो जो पोस्ट्स वहां के लिए बननी हैं उनकी अप्वायंटमैंट कें आर्डर साथ ही भेज देते है या पोस्ट्स खाली रहती हैं ? अगर खाली रहती है लो कितने दिन के बाद स्टाफ भेजा जाता है?

**श्रीमती शारदा रानी :** स्पीकर साहब, साथ ही साथ भेज देते है ।

**चौधरी लीला कृष्ण :** अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हैडमास्टर्ज की एक लिस्ट बनाई थी ओंर उस लिस्ट में से आधे लोग सीनियोरिटी के हिसाब से लगा दिए और फिर लिस्ट खत्म कर दी । क्या मन्त्री महोदया उस लिस्ट में से हैंडमास्टर्ज अप्वायंट करने की कृपा करेंगी?

**श्रीमती शारदा रानी :** स्पीकर साहब, वह 4– 5 साल पूरानी लिस्ट हो चुकी है ।

**चौधरी लीला कृष्ण :** स्पीकर साहब. वह लिस्ट दो साल पुरानी है पांच साल पुरानी नहीं है ।

**श्रीमती शारदा रानी :** स्पीकर साहब, वह लिस्ट दो साल से अवश्य ज्यादा की है । छः महीने की लिस्ट वैलिड रहती है ।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़ :** अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने सोलह हैडमास्टर्ज की जगह खाली बताई हैं लेकिन मुझे लगता हैं कि सोलह जगहों से ज्यादा जगह खाली हैं । क्या मन्त्री महोदया वह लिस्ट बताने की कृपा करेंगी?

**श्रीमती शारदा रानी :** स्पीकर साहब, सोलह की लिस्ट उन हैडमास्टर्ज की है जो हमने अपग्रेड किए हैं ।

**श्री भले राम :** स्पीकर साहव, प्राईमरी स्कूल से जो स्कूल मिडिल होते हैं उनमें तो हेडमास्टर की पोस्ट नहीं होती सिर्फ हाई स्कूल में होती है । क्या सरकार की पौलिसी है कि प्राईमरी स्कूल में भी जो जे ० बी० टी ० सीनियर होगा वह हैडमास्टर बनेगा औंर मिडिल स्कूल में भी वही बनेगा जो सीनियर होगा और उनके ग्रेड अलग होंगे?

**श्रीमती शारदा रानी :** स्पीकर साहब, अब तक तो यह होता रहा है कि जो मिडिल स्कूल को हैड करता था उसको पचास रुपया महीना ऐक्सट्रा दिए जाते थे । लेकिन अब नए ग्रेड आ रहे हैं और स्केल रिवाइज होने जा रहे हें और अब नई पौलिसी बनेगी ।

**Irregular use of electricity at Dharuhera**

***1285. Chaudhri Azmat Khan :** Will the Minister

for Irrigation and Power be pleased to state whether any vigilance enquiry has been conducted by the Vigilance Cell of the Haryana State Electricity Board about the irregular use of electricity at Dharuhera, during the period from 12-1-87 to 16-1-87; and if so, details of the report/observations made about the irregularities naiad togetherwith the action, if any, taken -against the defaulting officials ?

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Yes, Sir. An enquiry was conducted by the Vigilance Section cf Haryana State Electrioity Board, about irregular use of electiicity at Dharuhera during 12-1-87 to 16-1-37. The enquiry report has been recently received by the Board and is presently under consideration. However the Xen (Operation) Dharuhera has been placed under suspension on the basis of preliminary examination of the vigilance report.

**चौधरी अजमत खां :** स्पीकर साहब मोहतरिम मिनिस्टर साहब ने मेरे सवात के जवाब में कहा है कि दिनांक 1 2— 1— 1987 से 1 6— 1— 1987 कीं अवधि के दरम्यान धारुहेड़ा में बिजली के अनियमित प्रयोग के बारे में जांच रिपोर्ट हाल हो में प्राप्त हो चुकी है । हम यह चाहते थे कि वह जो जांच रिपोर्ट आयी है, उसकी क्या औवजर्वेशन है, अगर वह इस सदन के पटल पर रखी जाती तो अच्छा होता क्योंकि यह मसत्रा छोटा नहीं है । इस बारे में 29— 11— 1986 के अखबारों मे भी खबरें छपी थीं उसके बाद भी यह वात वार बार हरेक अखबार मे अति। रही हैं । रिवाड़ी के लौकल अखवार में भी खबर आयी है । हिन्दुस्तान टाईम्ज, पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून, हिन्दी व इंगलिश और

नवभारत टाईम्ज के आधार पर मैंने सारे आकड़े इकट्ठे किये हैं और यह देखा गया है कि बिजली की बहुत सारी अनियमितता हुई हैं ।

**श्री अध्यक्ष :** अजमत खां जी चाहे यह स्व कुछ अखबारों मे आया, चाहे कुछ भी हुआ, इस बारे में इंक्वायरी की गयी है, ऐक्सीअन को सस्पैन्ड कर दिया गया है अब आप और क्या चाहते हैं ?

**चौधरी अजमत खां :** स्पीकर साहब अखबारों में बदनामी हुई है । जो इंक्वायरी रिपोर्ट आयी है, अगर उसका यहां पर कुछ जिक्र हो जाता तो अच्छा था ।

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, अक्तूबर 1986 को इस तरह की शिकायत पहली बार मिली कि धारुहेड़ा में कुछ अनियमितताएं हुई हैं । शिकायत मिलते ही एक एस० ई० को सस्पैन्ड कर दिया । उसके बाद 30—1—86 को एक रिटन शिकायत मिली और उसको विजीलैन्स के सुपुर्द कर दिया गया । 12—2—87 को विजीलैन्स की रिपोर्ट मिली थी जिसको हम ऐग्जामिन कर रहे है । वहां का जो ऐक्सीयन (आपरेशन ) था, उसको सस्पैन्ड कर दिया गया था । इसके अलावा जिस किसी के खिलाफ इम्पलीकेशन्ज मिलेगी उसके खिलाफ ऐक्शन लेंगे । मुख्य रूप से यह शिकायत है कि पावर रेगुलैटरी मैयर्ज जो थे, उनको वायलेट करते हुए किसी इंडस्ट्री को अधिकारियों ने विजली दे दी थी,

और भी छोटी मोटी शिकायतें हैं । रिपोर्ट अभी मिली है और उसको ऐग्जामिन किया जा रहा है । रिपोर्ट काफी बड़ी है, उसके काफी पेजिज हैं । (विघ्न ) बिजली बोर्ड उसको ऐग्जा– मिन कर रहा है, सरकार एग्जामिन नही करती । सरकार तो तव उसमे दखल देती है जब यह समझें कि बोर्ड ठीक ऐग्जामिन नहीं कर रहा है । मैम्बर साहेबान ने अखबारों की खबरो का जिक्र किया है, उसका हम स्वागत करते हैं । अखबारों के अपने कर्तव्य है, वे अपना कर्तव्य निभाते हैं । इस में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है । बदनामी इस चीज का नाम नहीं है कि अखबारों में खबरे छपती हैं । अखबारों को तो अपना काम करना है, उनको तो खबरें छापनी हैं । चाहे प्राईवेट आदमी खबर दे, सरकारी कर्मचारी खबर दे या कोई एम०एल० ए० खबर दे, उसका स्वागत किया जाता है । सरकार खुद यह चाहती है कि अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसका दमन किया जाए और हमें जहां से कोई खबर मिलेगी, हम उसका स्वागत करेंगे चाहे किसी भी सोर्स से खवर मिले । जो खबर हमें मिली, हमने उस पर ऐक्शन लिया है, किसी बात कौ छुपाया नही है, किसी कैं।. मदद नही की है ।

**चौधरी अजमत खां :** स्पीकर साहब, मेरी शिकायत करने से पहले ऐक्सीयन को सस्पैन्ड नहीं किया गया था । इररैगुलैरिटीज तो अवश्य हुई हैं और उन लोगों को 24 बंटे विजली दी गया है । यह वड़ा ही गम्भीर मामला है । किसानों का हक काट कर उन फैक्ट्रीज वालो को बिजली दी गयी है, यह कोई

उचित बात नहीं है । यह रिकार्ड की बात है । आपका जो इंडस्ट्रीयल फीडर होता है उसमें यूनिट्स रिसीव्ड और यूनिट्म सोल्ड दोनों में कम से कम साढ़े सात परसैन्ट की कमी आनी चाहिये और रूरल फीडर में 16 परसैन्ट की जबकि इंडस्ट्रीयल फीडर में एस० डी० ओ० ने रिपोर्ट दी है कि इंडस्ट्रीयल फीडर नम्बर 1 में 1 लाख 84 हजार 720 यूनिट्स आए । (शोर )

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहब, इररैगुलेरिटीज तो अवश्य हुई हैं और वे इस बात को मान रहे हैं । सम्बन्धित अधिकारियों को सस्पैन्ड भी कर दिया है तथा विजिलेन्स की रिपोर्ट को सरकार एग्जामिन कर रही है ।

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, अगर ये सचमुच में सरकार की मदद करना चाहते हैं तो चोरी वगैरह की जो इंफर्मेशन इनके पास है, वे हमें दे दें । हम उस पर ऐक्शन लेंगे । अगर इसके सिवाये कोई और इनका मुद्दा है तो उस मामले में हम इनकी कोई मदद नही कर सकते ।

**श्री कंबल सिंह :** अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बिजली लोगों ने अन–आथोराइज्ड इस्तेमाल की है या डाइवर्ट की है? क्या यह केस डाईवर्शन का था या इसमें कोई थैफट आफ इलैक्ट्रीसिटी का भी केस बनता था ? क्या इस बात को चौक करने के लिये सरकार कोई उपाय करवाती है कि दूसरे किसी ऐक्सीयन? एस० डी० ओज० से लाईन लौसिज को भी

कम्पेयर करवाया जाए कि दोनों में लाईन लौसिज का कितना अन्तर है? कहीं यह तो नहीं होता हो कि लाईन लौसिज दिखा दिये जाते हों लेकिन ऐक्चुअली बिजली की चोरी होती हो या डाईवर्शन होती हो?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, जहां तक नेचर आफ कम्पलेन्ट की बात है यह अन–आथोराईजड यूज आफ पावर सप्लाई आफ पावर के बारे में है । प्रमुख ऐलीगेशन है कि पावर जिनको निर्धारित घंटों में नहीं दो जानी थी, उन घंटो में दी गयी । इसके इलावा और भी छोटी मोटी अनियमितताएं है, जो इल्जाम है उनकी पूरी तरह से पड़ताल की जा रही है । जहां तक लाईन लौसिज का सवाल है, यह सस्पैक्ट किया जा सकता है कि चोरी होती होगी । इसके लिये बिजली बोर्ड रैगुलरली डेली और वीकली यूनिट्सवाइज मोनीटरिंग करता है तथा कमैरीजन करता है । इसके अलावा कहीं और जो छोटी मोटी कमी रहती है. और जो बात हमारे नोटिस में आती है, उस पर बाकायदा कार्यवाही की. जाती है ।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़ :** अध्यक्ष महोदय, क्या मिनिस्टर. साहब बताएंगे कि इसी तरह बिजली की चोरी की कम्पलेन्ट्स कहीं और जगहों से भी सरकार को प्राप्त हुई हैं ? अगर कोई ऐसा मामला सरकार को नोटिस में आया है तो क्या उसकी विजीलैन्स द्वारा जांच करवायी गयी है और कोई आफिसर्ज भी सस्पैड किये गये हैं? इसके साथ साथ' मेरा दूसरा सवात भी है । इस वक्त मेरे

विचार में इंडस्ट्रीज की तरफ लाखों रुपए के बिल बकाया हैं । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि उनमें से कितने बिल भरे जा चुके हैं और कितने अभी तक बकाया हैं?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, बहुत अच्छा होता अगर आनरेबल मैम्बर यह सवाल पूछ लेते और मेरे को भी आकड़े इकट्ठे करने का मौका मिल जाता । इस वक्त यह सूचना मेरे पास नहीं है कि किस किस इंडस्ट्रीज के पास कितना कितना बिजली का बिल बकाया है और कितना भरा जा चुका है । जनरल बात उन्होंने एक और कही कि क्या इस तरह के केसिज कहीं और भी पकड़े गये हैं और यदि हां तो उन पर क्या ऐक्शन हुआ है? इस बारे में मैं बता देता हूं कि यह बहुत बड़ा विभाग है । इस तरह के केसिज पकड़े भी जाते हैं और ऐक्शन भी होते हैं । किसी खास केस के बारे में अगर ये पूछें तो मैं बता सकता हूं । जनरल बात का तो जवाब यही है कि जब कोई ऐसे केसिज पकड़े जाते हैं तो ऐक्शन होता है ।

**श्री नेकी राम :** अध्यक्ष महोदय, हिसार में जनता सैक्टर में एक सरकारी उद्योग है । बिजली न मिलने के कारण वह घाटे में जा रहा है जिसके कारण से वहां के वर्कर्ज पर भारी असर पड़ रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर उस उद्योग को बिजली न मिल सकती हो तो उसकी जगह कोई दूसरा प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ताकि वहां के वर्कर्ज को कोई परेशानी न हो और उनको रोजगार मिलता रहे?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** स्पीकर साहब, अगर इनका मतलब वहां के स्टील प्लांट से है तो उसको हम प्रेफरैन्शियल बेसिज पर बिजली देते हैं । पहले वह यूनिट सिक थी लेकिन अब पिछले कई सालों से काफी इम्प्रूव कर रही है ।

**Mr. Speaker :** Now Questions are over

## नियम 64 के अधीन वक्तव्य–

मुख्य मन्त्री द्वारा, राज्य में ओलावृष्टि से हुई क्षति तथा प्रभावित जनता को राहत देने सम्बन्धी ।

**मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल ) :** स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक स्टेटमैंट देना चाहूंगा ।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है ।

**Shri Bansi Lai :** It is a matter of great distress that wide- spread damage has been caused in 10 out of 12 districts of the State due to hailstorms which occurred on 15th/16th February and again on 23rd/24th February, 1987. The damage is partioularly severe in the districts of Faridabad, Gurgaon, Rohtak and Bhiwani. Special Girdawari of the hailstorm -hit areas was ordered throughout the State and is nearing completion. While the total area damaged and the extent of damage in individual fields would have to be based on the result of this special girdawari, preliminary reports indicate that the total number of villages affected is about 875 and the total area affected in the State is about 6 lakh acres.

2. In order to suggest relief measures to meet this situation Government have constituted a Cabinet Sub-Committee headed by Shri Shamsher Singh Surjewala, Irrigation and Power Minister, and this Committee is considering the question of giving all possible relief to the hailstorm affected people in the State. The Deputy Commissioners have been directed to depute all the available officers in the districts to undertake cent-per-cent ohecking cf the hailstorm affected areas so as to ensure that the `kharaba' is worked out accurately and realistically, and no deserving person is left cut of the relief measures. Instructions have also been issued that any wrong assessment of 'Kharaba' by the revenue staff would invite strict disciplinary action.

3. The Government of India have been informed about this extensive damage and immediately after getting results o f the special girdawari, a detailed memorandum will be submitted to them fcr providing liberal relief in the affected areas. I have personally written to Shri G.S. Dhillon, Union Agriculture Minister, Government of India requesting him to straightaway depute concerned officers from the Government of India to have a quick survey so that they can see for themselves the severity of the damage caused. However, as a measure of immediate relief, the Haryana Government have decided to give gratuitous relief to the tune of about Rs: 10 crores to the affected farmers whose orops have been damaged. Where the loss to the standing crops is above 75 %, this relief shall be paid at the rate of Rs. 400/- per acre. Likewise where the damage is above 50% and upto 75 %, the quantum of relief paid will be Rs. 300/- per acre and for loss between 25% to 50 %. the payment will be made at the rate of

Rs. 200/- per acre. Another sum of Rs. 1.10 crore will be paid as gratuitcus relief to the farmers whose crops were affected by the hailstorms last year. In addition, a sum of Rs. 2 orore is being advanced for disbursement as fodder taocavi in these areas.

4. In order to help the wage earners who are normally dependent upon agricultural operations and would now be deprived of their income, Government have already diverted a sum cf Rs. 4 crores under Food for Work (NREP and RLEGP etc..) for giving gainful employment in the hailstorm affected areas. Under these programmes, the panchayats are required to contribute substantial amounts from their own resources to meet a part of the cost of building material for creation of permanent community assets. Since many of the panchayats in the affected areas would not be in a position to bear this additional burden, the Government have further decided to give an additional amount of Rs. 2 crores to the panchayats to enable them to meet this liability.

5. The Hon'ble Members would, thus, like to note that the 'Haryana Government have already decided to provide Rs. 15 crore from the State Budget itself for granting immediate relief to the hailstorms affected population. At the same time, all out efforts will be made to get maximum assistance from the Government of India as well. I would like to take this opportunity to fully assure the House that all possible measures will be taken by the Government to mitigate the hardship of the farmers in the hailstorms hit areas.

**श्री नेकी राम :** स्पीकर साहब, मैं आपेकी इजाजत सदन के नेता से एक सवाल पूछना चाहता हूं । मेरे रतिया हल्के में गांव भी लगते हैं और डेढ़ साल पहले तहसील फतेहाबाद के कुछ एरिया में ओले पड़े थे । उसकी गिरदावरी भी हो गई थी और एस० डी ० एम० ने केस डी ० सी को भेज दिया था । अब वह केस सरकार के पास है । लोग मेरे से पूछते हैं कि उस केस का क्या हुआ । क्या सदन के नेता उस बारे में बताएंगे?

**श्री बंसी लाल :** स्पीकर साहब, एरियाज के बारे मे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर पिछले साल तक करीब एक करोड़ रुपया ऐसा है कि जो ओले पड़े थे उसकी रिलीफ नहीं दी गई थी । हम इस सात में वह रुपया भी दे रहे हैं ।

**चौधरी अजमत खां :** स्पीकर साहब, परसों हमारे इलाके में ओले फिर पड़ गए हैं, क्या वहां दोबारा गिरदावरी करवाएंगे?

**श्री बंसी लाल :** स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर को गवर्नमैंट की फैकशनिग का पता नहीं है । जब मैं कह रहा हू कि सबको रिलीफ देंगे तो नई गिरदावरी करवाने का क्या फायदा है । ये तो हवा में बात कर रहे हैं और चीप पापुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं ।

## नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष :** अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 15 के तहत मोशन मूव करेंगे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

## प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

## नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष :** अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 16 के तहत मोशन मूव करेंगे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के उठने पर साइने डाई ऐडजर्न रहेगी ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के उठने पर साइने डाई ऐडजर्न रहेगी ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

## नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष :** अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 121 के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Speaker Sir, I move—

That the provisions of Rules 228, 230, 230B and 260A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so far as they relate to the term of office of members of the-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. be suspended.

Sir, I also move—

That the members of-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

who were elected by the House for the year 1986-87 shall continue to serve as members of their respective Committees during the year 1987-88.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ–

That the provisions of Rules 228, 230, 230B and 260A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so far as they relate to the term of office of members of the-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committer on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes be suspended. That the members of the -

(i) Committee on Public Accounts;

(i) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

who were elected by the House for the year 1986-87 shall continue to serve as members of their respective Committees during the year 1987-88.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है—

That the provisions of Rules 228, 230, 230 B and 260A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so far as they relate to the term of office of members of the—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes be suspended. That the members of-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

who were elected by the House for the year 1986-87 shall continue to serve as members of their respective

Committees during the year 1987-88.

The motion was carried.

## सरकारी संकल्प

## (1) हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (डिसक्वालिफिकेशन औफ मैम्बर्ज पौन ग्राउन्ड औफ डिफैक्शन) नियम, 1986 की स्वीकृति संबंधी ।

**श्री अध्यक्ष :** अब एक मिनिस्टर आफिशियल रैजोल्यूशन पेश करेंगे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) Sir, I beg to move—

That this House unanimously approves under sub-paragraph (2) of paragaph 8 of the 10th Schedule of the Constitution of India, the Haryana Legislative Assembly (Disqualification of Members on Ground of Defection) Rules, 1986 framed by the Speaker in exercise of the powers conferred upon him by the above Constitutional provisions without any modification.

अध्यक्ष महोदय, जनवरी 1985 में लोक सभा ने कान्स्टीच्यूशन में 52वी अमैंडमैंट की थी, और वह अमैंडमैंट ऐन्टी डिफैक्शन के नाम से पापुलर हुई । डिफैक्शन की बीमारी राजनीति में एक कैसर की तरह लगी हुई थी । पिछले 30 सालों के दौरान इस बारे में कई कमेटीज बनीं और इस पर अनेक बार कई मौकों पर चर्चाएं भी होती रहीं । इस बारे में कई बार

पार्लियामैंट में भी और स्टेट की असैम्बलियों में भी रैजोल्यूशन समय समय पर आते रहे । लेकिन यह श्रेय हमारे नौजवान और डायनामिक प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी को जाता है जिन्होंने जनवरी, 1985 में पार्लियामैंट के चुनावो के तुरन्त बाद पहले ही सैशन में डस अमैंडमैंट को पास करवाया । इस में यह भी प्रावधान है कि हर हाउस के स्पीकर या कौसिल के चेयरमैन इस एक्ट को लागू करने के लिए फ्रेम करेंगे । इस ऐक्ट को लागू करने के लिए यह बात भी इसमें लिखी. हुई है कि जो रूल्ज संबंधित विधान सभाओं द्वारा बनाये जाएंगे, उन्हें हाउस के पटल पर रखा जाएगा । जब हाउस की सीटिंग एक सैशन में शै या एक से ज्यादा सैशन हो तो 30 दिन का समय निकल जाने के बाद ये रूल्ज आटोमैटिकली लागू हो जाएंगे । अब इन रूल्ज को टेबल पर ले किए हुए 27 दिन हो चुके हैं । 30 दिन पूरे होने में केवल 3 दिन का पीरियड रहता है । आज हाउस की बैठक उठने वाली है और नए चुनाव तक हाउस की और कोई बैठक होने की संभावना नहीं है । इसलिए मैं सभी मैम्बरों से प्रार्थना करता हूं कि जो रूल्ज रखे हैं, उनको सर्वसम्मति से एडौप्ट किया जाये । प्रधान मन्त्री जी ने यह एक अच्छा कानून बनाया है और एक अच्छी मर्यादा कायम की है । अब राजनीति में सभी को एक तरह से सम्मान का दर्जा मिलेगा । मैं हाउस के मैम्बरों से फिर प्रार्थना करता हूं कि जो रूल्ज फेम किए गए हैं, उनको सर्वसम्मति से पास करें ताकि यह हाउस अपनी इसी टर्म में इनको एडौप्ट कर सके । अगर आज भी यह रैजोल्यूशन नहीं आता तो अगली दफा जब भी हाउस मीट

करता तो उसके तीन दिन गुजरने के बाद ये रूल्ज अपने आप एडौप्ट होने थे ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

That this House unanimously approves under sub-paragraph (2) of paragraph 8 of the 10th Schedule of the Constitution of India, the Haryana Legislative Assembly (Disqualification of Members on Ground of Defection) Rules, 1986 framed by the Speaker in exercise of the powers conferred upon him by the above Constitutional provisions without any modification.

**श्री लछमन सिंह (कालका ) :** स्पीकर साहब, यह बड़ा अच्छा रैजोल्यूशन है । हरियाणा तो डिफैक्शन के मामले में आया राम गया राम के नाम से बदनाम था । इम बारे में मैं पार्लियामैंट अफेयर्ज मिनिस्टर से एक बात की कलैरिफिकेशन चाहूंगा । इसके अन्दर एक डिस्क्वालिफिकेशन वर्ड लिखा है । मैं जानना चाहूंगा कि डिसक्वालिफिकेशन कितने अर्से के लिए है ? जो मैम्बर डिफैक्ट करता है क्या वह परमानैटली अनसीट हो जायेगा या डिसक्वालिफाई हो जायेगा? इस बारे में मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा । वैसे डिसक्वालिफिकेशन का मतलब तो यही है कि he is disqualified permanently for whole of his life. इसमें कुछ एम्बीग्यूटी है । इस बारे में मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा । आप भी मेरे ख्याल से मेरी मदद करेंगे । डिसक्वालिफिकेशन का मतलब अनसीट से है या डिस– क्वालिफिकेशन से है । पीपल्ज

रिप्रैजैन्टेशन ऐक्ट के मुताबिक एक आदमी यदि क्रप्ट प्रैक्टिस करता है तो वह 6 साल के लिए डिसक्वालिफाई हो जाता है । कोई मैम्बर यदि अनसीट हो जाता है तो what is the meaning of disqualification ?

**श्री भले राम (बड़ौदा, अनुसूचित जाति ) :** स्पीकर साहब, मैं इस रैजोल्यूशन की ताइद करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में काफी कुछ देखा है । जब मैं जनता पार्टी से चुन कर आया था तो हमारे अढ़ाई साल तक पैर टिकने मुश्किल हो गए थे । हम उम समय कभी दिल्ली भागे जा रहे थे तो कभी भारत दर्शन के लिए जा रहे थे । उस समय हरियाणा काफी बदनाम हुआ था । प्रधान मन्त्री जी ने एन्टी डिफैक्शन बिल पास करवा करके एक अच्छा काम किया है । स्पीकर साहब, मैं इस रैजोल्यूशन के बारे में यह भी चाहूंगा कि इस में उन लोगो का भी कोई प्रबन्ध होना चाहिए जो हाउस की बैठक में भाग नहीं लेते । लोगों ने उन्हें इसीलिए चुन कर भेजा था कि वे उन लोगों की समस्याओं के बारे में हाउस में चर्चा करेंगे । इसके अलावा उन लोगों का भी कोई प्रबन्ध होना चाहिए जो चुनाव जीतने के बाद ओथ नहीं लेते । स्पीकर साहब, शायद आपको भी मालूम होगा कि गांवों में पचायामें की बैठकों में भी यदि कोई पंच या सरपंच लगातार तीन या चार बैठकों में भाग नही लेता तो वह डिसक्वालिफाई हो जाता है । मैं चाहूंगा कि इसी तरह की कोई अमैंडमैंट इस रैजोल्यूशन में उन मैम्बरों के लिए भी की जाये जो हाउस की बैठक में भाग नही लेते और

ओथ नहीं लेते । मैं चाहूंगा कि ऐसी अमैंडमैंट करने के लिए भारत सरकार से सिफारिश की जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस रैजोल्यूशन का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी ) :** स्पीकर साहब, मैं भी इस रैजोल्यूशन की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह एक अच्छा रैजोल्यूशन है । इस से राजनीति साफ सुथरी रहेगी । (विघ्न' ) यह भी ठीक है कि हम डिफैक्ट करके इधर आये हैं लेकिन जो अच्छे काम होते हैं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए । जनता पार्टी अपने समय में इस बिल को लाने के लिए बहुत शोर मचा रही थी लेकिन वे भी अपने समय में इस बिल को पार्लियामैंट में पास नहीं कर सके । यह सारा श्रेय हमारे नौजवान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को जाता है जिन्होंने राज– नीति को साफ–सुथरा रखने के लिए यह बिल पास करवाया । जो रैजोल्यूशन हमारी सरकार लाई है उसका भी मैं समर्थन करता हूं । जनता भी अब उन्हीं लोगों को चुन कर भेजेगी जो एक पार्टी में रह कर उनकी सेवा कर सकेंगे । अब हमारे यहां पर चुनाव होने हैं । उसके बाद यहां पर कुछ नए और कुछ पुराने चेहरे नई आशाओं के साथ आएंगे । अव जिन मैम्बरों को जनता चुन कर भेजेगी वे उसी पार्टी में रह कर लोगों की सेवा कर सकेंगे जिस पार्टी से वे जीत कर आयेने । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इम रैजोल्यूशन का समर्थन करता हूं ।

**सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी ) :** स्पीकर साहब, मैं इस रैजोल्यूशन की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । अब हरियाणा से आया राम गया राम की कहानी समाप्त हो जायेगी । अव जिस दल से मैम्बर चुनकर आएंगे उसी दल में रह कर वे लोगों की सेवा कर सकेंगे । अगर इस बात को कोई मैम्बर नहीं निभा सकता तो इस्तीफा देकर उस दल से चुनाव लड़ कर आयेगा जिसमें वह विश्वास रखता हो । सरदार लछमन सिंह जी ने जो बात कही है उसकी भी यहां पर मच्छी जी को क्लैरिफकेशन देनी चाहिए । एक बात भले राम जी ने यह कही है कि जो मैम्बर हाउस में नहीं आते.और जो चुनाव जीतने के बाद ओथ नहीं लेते उनका भी कोई इंतजाम अवश्य होना चाहिए । जो मैम्बर चुनाव जीतने के वाद हाउस में भाग न ले और ओथ न ले तो ऐसे मैम्बरों को लोगों की नुमाइन्दगी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए । अगर सही मायनों में देखा जाये तो ऐसे लोग जनता के साथ धोखा कर रहे हैं । अन्त में मैं इस रैजोल्यूशन का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं और साथ ही साथ सुझाव देता हूं कि ऐसे मैम्बर जो हाउस में नहीं आते और चुनाव जीतने के बाद ओथ नही लेते, का इन्तजाम करने के लिए इस बिल में जो पार्लियामेंट ने पास किया है, अमैंडमैंट के लिए भारत सरकार से सिफारिश की जाए ।

**शिक्षा मंत्री (श्रीमती शारदा रानी ) :** अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर यह है कि जहां पर मैम्बर कहीं ऐबस्टेन करता है या

कांटरेरी टू दि पार्टी डायरैक्शन वोट देता है तों उसकी डिस–क्वालिफिकेशन हो जाती है लेकिन इधर एक बात यह भी है–

"A member may be regarded as having abstained from voting only when he, being entitled to vote, voluntarily refrained from voting."

सर, यहां पर जो बहुत से अपोजीशन के सदस्य थे, वे हाउस में हाजिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उनके लीडर की डायरैक्शन यह होगी कि हाउस से गैर–हाजिर रहना है लेकिन जनता की डायरैक्शन यह है कि वे यहां आ कर बैठें और जो भी चीज हाउस में होती है, उस पर वोट दें । स्पीकर साहब, इस बारे में कोई विचार होना चाहिए, उन्होंने पूरी तरह से अपने कर्त्तव्य का पालन न करते हुए कोताही की है । उन्हें डिस–क्वालिफाई करने का कोई न कोई प्रोविजन अवश्य होना चाहिए ।

**सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ) :** अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर वहस में हिस्सा लेते हुए सरदार लछमन सिंह, सेठ राम दास धमीजा, श्रीमती शारदा रानी और मक्कड़ साहब ने कुछ बातें कहीं हैं । सरदार लछमन सिंह जी का मुद्दा यह था कि वह पूरी उम्र के लिए डिस–क्वालिफाई होगा या केवल उसी टर्म के लिए होगा। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि टैन्थ शिडयूल के तहत यह डिस–क्वालिफिकेशन हए यानी जिस पीरियड के लिए वे चुन कर

आये हैं, फ्युचर के लिए नहीं । दूसरी बात जो उन्होंने उठायी वह यह है कि जो लोग मैम्बर बन कर आये हैं और उन्होंने हाउस अटैन्ड नहीं किया है, अपने कर्त्तव्य की पालना नहीं की है, उनके खिलाफ पैनेल्टी होनी चाहिए । इन्सीडैन्टली ऐसी बात हो गई वरना यह वात किसी और पर्पज के लिए थी । यह बात तो डिफैक्शन के लिए थी । जो बात उन्होंने कही यह न ऐक्ट में है और न ही रूल्ज में है । मेरे ख्याल में इस प्रस्ताव के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन किसी वक्त जब ये लोग विधान सभा के मैम्बर्ज नहीं रहेगे, उस वक्त आप तो अध्यक्ष होंगे, यानी जब भी आपकी कोई आल इंडिया लैवल पर स्पीकर्ज कान्फ्रेंस होगी तो उस समय यह बात आप द्वारा सैपरेटली उठायी जा सकती है । मुझे आशा है कि आप इस बात को जरूर उठायेंगे । जब भी आल इंडिया स्पीकर्ज कान्फ्रेंस हो, उस समय आप इस बात को उठायें । यह वाकई में एक ऐसा वैक्यूम शै जिसके बारे में कार्यवाही की जानी चाहिए । आज के कायदे कानून के मुताबिक जब डिफैक्शन इतनी बड़ी डिस– क्वालिफिकेशन बना दी है तो उससे भी सीरियस बात यह भी है । जो लोग चुन कर आते हैं, इतनी बड़ी भारी कम्पेन चलायी जाती है, सरकार का और लोगों का पैसा खर्च होता है यदि वे हाउस अटैन्ड न करें तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए । वे लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं । कांस्टिच्चूशन का उल्लंघन करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को तारपीडो करते हैं । यह बड़ी दु:खदायी वात है । उनके खिलाफ जरूर कोई कार्यवाही होनी चाहिए । अगर पंचायत स्तर पर सरपंच

और कोआप्रेटिव सोसाइटीज का मैम्बर जतनी उन्होंने मीटिंग अटैन्ड करनी हैं, उतनी न करें तो वे डिस–क्वालिफाई हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं तो मैम्बर विधान सभा का भी कुछ होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह प्रस्ताव पास किया जाये ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है

That this House unanimoulsy approves under sub-paragraph (2) of paragraph 8 of the 10th Schedule of the Constitution of India, the Haryana Legislative Assembly (Disqualification of Members on Ground of Defection) Rules, 1986 framed by the Speaker in exercise of the powers conferred upon him by the above Constitutional provisions without any modification.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**(2 ) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण की सीमा को राज्य सरकार द्वारा निश्चित करने की स्वीकृति संबंधी**

**श्री अध्यक्ष :** अब मिनिस्टर साहब अगला औफिशियल रैजोल्यूशन पेश करेंगे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—.

That this House approves under sub-section (3) of

Section 65 of the Electricity (Supply)Act,1948 (Central Act 54 of 1948),the fixation by the State Government of a higher maximum amount of 6C0 crores of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under stb-section (1) of that section.

स्पीकर साहब, अब से पहले बिजली बोर्ड को चार सौ करोड़ रुपए तक कर्जा लेने का अख्तियार था । कायदे के मुताबिक उसे वह हाउस से ऐप्रूव करवाना पड़ता है लेकिन चूं कि इलैक्ट्रिफिकेशन का काम ऐक्सटैन्ड हो रहा है और रुपये की की मत कम हो रही है इसलिये उनका बौरो करने का अख्तियार बढ़ाया जाये यानी उनकी कर्जा लेने की? लिमिट बढ़ायी जाये । इस आश्य के सा व यह प्रस्ताव हाउस मै रखा गया है ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ––

That this House approves, under sub-section(3) of Section 65 of the Electricity city (Supply) Act,1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of 600 crores of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under subsection(1) of that section.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

That this House approves, under sub-section (3) of Section 65 of the Electri(Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of 600 crores of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under

sub-section(1) of that seotion.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिल्ज –

(1 ) दि इंडियन इलैक्ट्रिसिंटी (हरियाणा अमैंडमैंट ) मिल 1986

**Mr. Speaker :** Now the Irrigation and Power Minister will move that the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, 1986, as reported by the Select Committee, be taken into consideration at onoe.

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, as reported by the Select Committee, be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ–

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, as reported by the Select Committee, be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

That the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, as reported by the Seleot Committee, be taken into consideration at once.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

**क्लाज–2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज– 3**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज– 4**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज– 5**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है––

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट वने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज– 6**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है–

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज– 7**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है–

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज– 8**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है–

कि क्लाज 8 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लाज– 9**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 9 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज– 10**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 10 बिल का पार्ट बने,

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज– 11**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

कि क्लाज 11 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**अनौक्टग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**टाइटल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**Mr. Speaker :** Now the Minister will move that the Bill, as reported by the Select Committee, be passed.

**Irrigation and Power Minister(Chaudhri** Samsher Singh Surjewala) Sir, I beg to move—

That the Bill, as reported by the Select Committee, be passed.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Bill, as reported by the Select Committee, be passed.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Bill, as reported by the Select Committee, be passed.

The motion was carried.

## (2 ) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न० मै ) बिल, 1987

**श्री अध्यक्ष :** अब फाइनेस मिनिस्टर दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं ० 4 ) बिल को इंट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

**11.00 बजे ।**

**Finance Minister** (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir, I introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1987.

I also move--

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ––

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

**श्री भले राम (बड़ौदा, अनुसूचित जाति ) :** स्पीकर साहब, मैं एप्रोप्रिएशन (नं ० 4 ) बिल के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान बिजली और पानी की तरफ दिया थैं । अभी सुरजेवाला साहब ने बिजली बोर्ड की कर्जा लेने की लिमिट 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये करने के लिये हाउस से इजाजत मांगी थी ताकि लोगों की जो बिजली की जरुरतें बढ़ रही हैं, उनको पूरा करने के लिये बिजली का जाल बिछाया जा सके । बहुत सी स्कीमें सरकार के विचाराधीन है और वहुत सी स्कीमें चरा रही हैं । चाहे वह थर्मल प्लांट हों, या 33 के०वी ० सब–स्टेशन हों सरकार यह चाहती है

कि बिजली ज्यादा पैदा करके किसान के ट्यूबवैल को बिजली दी जाये । ऐसा देखने में आया है कि जब बिजली की लाईनें बिछाई जाती हैं, चाहे वह किसी भी जगह बिछाई जाती हैं, उस समय घरों का ध्यान नहीं रखा जाता । यदि कहीं पर किसी का प्लौट होता कुए या किमी का घर होता है तो उसकी छत के ऊपर से तार निकाल ली जाती है । हमारे पास इस तरह की बहुत शिकायतें आती हैं कि हमारे मकानों के ऊपर से तारे निकाली हुई हैं । जिनके मकानों की छत के ऊपर से तारे निकली हैं, उनकी दूसरी स्टोरी नहीं बन सकती क्योंकि तार उनके मकान के ऊपर से गुजरना है । यदि कोई आदमी बिजली बोर्ड को ऐप्लीकेशन देता है कि इसको यहां से हटाया जाये, तो कई–कई सालों तक उसकी ऐप्लीकेशन का निपटारा नहीं करते । यह कहते हैं कि ऐस्टीमेट बनायेंगे, जब वह पास होगा तभी हम इस वारे में देखेंगे । लोग अपना मकान आगे बनाने के लिये मारा मैटीरियल खरीद करके कई–कई सात्र तक बैठे रहते हैं लेकिन वे बेचारे मकान नहीं बना पाते । इसलिये इस बात की बड़ी दिक्कत है । मैं सुरजेवाला साहब से यह कहूंगा कि ऐसे मकान जिनके ऊपर से बिजली की तारे गुजरती हैं, और कईयों के घरों में खम्भे गाड़े होते है, उनको वहां से दूर हटाया जाये । बिजली बोर्ड वाले यह कहते पैं कि जिस समय खम्भे गाड़ कर तारे बिछार्ड गई उस समय प्लौट खाली पड़ा था, मकान नही वना था । भले आदमियों को यह तो देख लेना चाहिये कि किसी का तो प्लौट है । उसके एक कोने में खम्भा अगर गाड़ना ही है तो गाड़ त्रो यह एक बड़ी भारी समस्या

है । मेरा कहना यह है कि आगे से जो स्कीमें बनायें, उनमें तो कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये । दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा । इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो मीटर रीडर्ज होते हैं, वे भर बैठकर मीटर रीडिंग कर लेते हैं । पिछले महीने का बिल देखकर ऐवरेज लगाकर बिल भेज देते हैं । कईयों का विरर बहुत ज्यादा होता है हालांकि वहां पर केवल एक–एक बल्ब लगा होता है । कई बार मीटर बन्द होता है लेकिन फिर भी बिल आता रहता है। इसके अलावा जो बिल डिस्ट्रिब्यूटर होता है, वह 5–6 गांवों के लिये एक–एक लगा हुआ है । वह बिल कोलैक्ट करने नही जाता । इससे बड़ी परेशानी होती है ।

इसके अलावा, मैं पंचायतों के बारे मे भी बात कहना चाहता हूं । हमारे हरियाणा में जो पंचायतें हैं, वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं । बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां पर पंचायतें ठीक काम कर रही हैं लेकिन कुछ गांव की पंचायतें ऐसी हैं जो अपनी सारी टर्म में एक पैसा भी गांव की बहबूदी के लिये खर्च नहीं कर स्की हैं । इसका कारण यह है कि या तो मैम्बर कोआप्रेट नहीं करते या कई बार सर– पंच ऐसा निकम्मा आ जाता है कि वह कोई काम नहीं होने देता । इसका भी कोई इलाज होना चाहिये । उनको हम हटा नही सकते क्योंकि उनका डायरैक्ट. इलैक्शन होता है । मिसाल के तौर पर मेरे हल्के में एक गांव कथूरा है । वहां के लोग यह कहते हैं कि हमारे गांव में किसी भी काम पर पंचायत का एक पैसा भी नहीं लगा । इसके अलावा कई गांवो में

पंचायतों की बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो लोगों ने हथिया ली है और ऐसे लोगो को बेदखल करना मुश्किल है । जो जमीनें गांवों में खाली पड़ी है, चाहे वह जोहड़ों की है या चाहे चरागाह की जमीन है, किसी को मिल जाये, लोग उसे हथियाने की कोशिश करते हैं । इस ट्रैन्ड कों रोका जाये । –इसके अलावा सरकार ने म्यूनिसिपल कमेटीज के ऐम्पलाईज की ट्रांसफर करने का जो फैसला किया है, यह बहुत ही अच्छा किया है अब उनको भी स्टेट के दूसरे ऐम्पलाईज की तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है । अब उनकी भी ट्रांसफर हुआ करेगी । इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जो छोटा स्टाफ है, उसको रैगुलर जरूर किया जाना चाहिये । चाहे उसको आप भंगी कह दो, जमादार कह दो या कुछ और कह लो, इनको आज भी डेली वेजिज पर रखा जाता है । यह बेचारे 8– 8 और 10– 10 साल तक रैगुलर नहीं हो पाते । यहां पर डिगनिटी आफ लेबर नहीं है । उन लोगों के साथ जो सफाई का काम करते हैं, ठीक व्यवहार होना चाहिये । वे सारे शहर की सफाई करते हैं । उनको 10–12 साल तक डेली वेजिज पर रखा जाता है और रैगुलर नहीं किया जाता । यह ठीक बात नही है कि केवल दफ्तर में बैठकर ही काम होता है । जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग है, उनको अवश्य ही रैगुलर किया जाना चाहिये । हमारे जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के भाई हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सरकार ने उनकी बहुत मदद की है । कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विशेषकर नये मुख्य मन्त्री के आने के बाद इतनी मदद की है कि शायद ही आज से पहले किसी ने की हो ।

उनकी भलाई के लिये कई स्कीमें चलाई हैं । दो हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक के बिना ब्याज के कर्जे दिये जाते हैं । इस काम के लिये इसी साल में डिस्ट्रिक्टवाईज जौ पैसा आया है, वह पिछले साल की निस्बत बहुत ज्यादा था । पहले हम भी उस कमेटी में बैठा करते थे । पहले उसमें 20–25 हजार रुपये से ज्यादा पैसा नहीं आया करता था सोनीपत जिले में इस बार सौ लोगों को 2,000 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपया बिना ब्याज का कर्जा वाटा गया है । हमारे यहां पर जो सौ के करीब दरख्वास्तें आयी थीं, उनको 2,000 रुपये बिना व्याज के तौर पर दिये गये णै । अब हम उनको 10,000 रुपये तक बांटेंगे । 40 लाख रुपये के करीब रुपया हमें और मिलेगा । मेरा कहने. का मतलब यह है कि सरकार हरिजनों की खास तौर पर मदद कर रही है । मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे हरिजन भाइयों को भी कुछ सोचना चाहिये और हम यह उम्मीद रखते हैं कि समाज के दूसरे लोग उनकी कदर करें । इसके लिये हमें सोचना चाहिये हमारे साथी' हरिजन भाई सभी यहां पर बैठे हैं, मिनिस्टर भी बैठे है और एम०एल०ए ० साहेबान भी बैठे हैं । सरकार ने तो यह कोशिश की है कि इन्टर–कास्ट मेरिजिज हों ताकि छुआछूत खत्म हो सके । इसके अलावा कमजोर वर्ग की लड़कियों की शादी के लिये भी कुछ पैसा दिया गया है । हरिजन भाइयों को सोचना चाहिये कि दूसरे भाई तो आपको गले लगाये और आप आपस में ही मिलकर न रहें, हरिजनों की जातियों में ही आपस में छुआ–छूत हो, यह ठीक नहीं है । मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि

आम तौर पर हरियाणा में शिड्यूल्ड कास्टस में तीन ही की जातियां है । एक चमार, दूसरे बाल्मीकि और तीसरे धानक । आप ही बतायें कि कहां पर ये भाई मिलकर बैठते हैं और कहीं पर ये भाई साथ रहते हों ? इनको आपस मे मिलकर रहना चाहिये । दूसरे तोरा इनको आकर बहकाते हैं । राजनीतिक तौर पर इनका शोषण करते हैं । खास तौर पर लोक दल वाले इनका शोषण करते हैं । कहीं पर तो धानकों का सम्मेलन करते हैं और इनको बहकाते हैं कि आपको टिकट देंगे । कहीं पर बाजीगरों का सम्मेलन और कहीं पर वैकवर्डज का सम्मेलन करके इसी प्रकार से इनकी ऐक्स– प्लायटेशन करते है । बड़े दु:ख की बात है कि हमारी स्टेट के सीनियर आई०ए ०एस० आफिसर जो हरिजन थे और कमिश्नर रैंक के थे, वे भी उनकी बातों में आ जायें, मेरा कहना तो यह है कि अगर कोई हरिजन अच्छे पद पर होगा तो वह अच्छी सेवा कर सकेगा । बड़े ही दु:ख की बात है कि लोग उनको बहकाते हैं और कहते हैं कि हम आपको एम०एल०ए० बनायेंगे वजीर बनायेंगे । मैं बहिन जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उनको समझायें । इस कम्युनिटी की ज्यादा सेवा अफसर लोग ही कर सकते हैं । हमारे शिड्यूल्ड कास्टस भाइयों के लिये बहुत सी स्कीमें इस सरकार ने बनाई हैं । उन स्कीमों का फायदा सभी कौ उठाना चाहिये । एक कौम के भाइयों की तरह से सब को एक जैसी सुविधा मिल रही हैं । फीस सभी बच्चों की माफ है चाहे वह बच्चा बाल्मीकि है या चमार है या खटीक का बच्चा है । सब के हक बराबर के हैं तो फिर एक क्यों नहीं होते । भंगियों के यहां

जाएंगे तो वहां कहेंगे चमार तुम्हारे हक खा गए । इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए । मेरा कहना यह है कि मोहल्लों में जाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाए । स्पीकर साहब, सरकार ने बहुत सारी स्कीम्ज चलाई हुई हैं लेकिन वे इम्पलीमैंट नहीं होतीं । आज यह हो रहा है कि कोई आदमी चमड़े के काम के लिए कर्जा लेता है लेकिन वह उसको शादी पर खर्च. कर देता है । कोई भेड पालने के लिए कर्जा लेता है तो उसको किसी और काम पर खर्च कर देता है । स्पीकर साहब, ऐसा करने से लोग स्कीम्ज का फायदा नहीं उठा पाते । इसलिए मेरी हरिजनों से प्रार्थना है कि वे सब मिलकर रहें और दूसरी पार्टीज के बहकावे में न आएं । स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल ने एलान किया है कि आने वाले सालों में हरिजनों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दूंगा, चौपालों के लिए भी अधिक पैसा दूंगा और उनको रोजगार के लिए भी और अधिक पैसा दिया जाएगा । सोलह हजार के करीब लोगों ने विभिन्न कामों के लिए निगम से पैसा लिया और दो लाख लड़कों ने किताबों की शक्ल में और स्कौलरशिप की शक्ल में फायदा उठाया हैं । सरकार ने एलान किया है कि भविष्य में इससे भी अधिक बच्चों को फायदा पहुंचाया जाएगा । स्पीकर साहब, मैं इतना ही कहकर खत्म करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

**चौधरी धर्मवीर गाबा (गुड़गांव ) :** स्पीकर साहब, फाइनैस मिनिस्टर साहब ने जो ऐप्रोप्रिएशन (नम्बर 4 ) बिल हाउस में रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं सब से पहले पंचायत एण्ड डिवैल्पमैंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । कर्नल साहब कृपया ध्यान से सुनें और उन कमियों को दूर करने की कृपा करें । स्पीकर साहब, गुड़गांव में कुछ ऐसा इलाका है जो एन०सी०आर० कें अन्डर आता है । वहां पर कुछ लोगों ने पंचायत की जमीन पर एनक्रोचमैंट करनी शुरू कर दी है और पंचायत के पास उनको खाली कराने की कोई पावर नहीं है । जब तक एस०डी ०एम० या ब्लौक डिवैल्पमैंट औफिसर को इस बारे में दर– ख्वास्त देते हैं, तब तक मकान बनकर तैयार हो जाता है । नतीजा यह है कि पंचायत की जमीन हड़प की जा रही है ।

स्पीकर साहब, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश को आजाद हुए चालीस साल होने जा रहे हैं लेकिन अब भी हरिजनों के साथ इंसानियत का सलूक नहीं किया जाता । अभी पिछले दिनों मुझे एक गांव में जाना पड़ा । वहां पर मुझे यह देख कर दु:ख हुआ कि एक हरिजन महिला को पानी नही भरने दिया गया । जब मैंने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या बात है तो उसने कहा कि कोई स्वर्ण आएगा और मेरे घड़े में पानी डालेगा तब मैं घर जाऊंगी । स्पीकर साहब, मेरा इस बारे में यह कहना है कि अगर किसी पंचायत के एरिया में इस तरह का जुर्म होता है

तो वहां पर पंचों और सरपंच को रहने का कोई हक नही है । यह इसा– नियत के खिलाफ जुर्म है और वहां के पंचों और सरपंच को डिसक्वालिफाई कर देना चाहिए ।

स्पीकर साहव, सरकार ने लोकल बौडीज के लिए दो करोड़ रुपया रखा है । अगर दो करोड़ रुपए को 81 म्यूनिसिपल कमेटीज में कटे तो एक के हिस्से में दो लाख रुपया भी नहीं आएगा । स्पीकर साहब, गुड़गांव म्यूनिसिपल कमेटी में एक गल्त बात हो रही है । वहां पर जो वाल्मीकि भाई हैं, उनको पार्ट टाईम पर रखा जाता है । उनको दो सौ रुपया महीना दिया जाता है और आठ घंटे उनसे काम लिया जाता है लेकिन कहने को चार घंटे काम लिया जाता है । स्पीकर साहब, दो सौ रुपए मे एक फैमिली का कैसे गुजारा हो सकता है?' स्पीकर साहब, जब उनसे इस तरह का काम लिया जाता है जिसको हम खुद नहीं करना चाहते तो उनको पैसे भीं ज्यादा देने चाहिएं । उनको पार्ट टाईम पर नहीं रखा जाना चाहिए । अच्छा तो यह रहेगा कि उनको परमानैन्ट रखा जाए लेकिन अगर उनको परमानैन्ट नहीं रख सकते तो डेली वेजिज पर रखकर डेली वेजिज का पैसा दिया जाए ।

स्पीकर साहब, अब मैं टूरिज्म के बारे मे कहना चाहता हूं । हरियाणा के अन्दर टूरिज्म का बहुत अच्छा काम चल रहा है । वैसे तो यह काम पब्लिक रिलेशंज का काम शै जिसको टूरिज्म डिपार्टमैंट कर रहा है । स्पीकर साहब, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आज विचार करने की बहुत जरुरत है । हमारे सामने जो बजट

आया है उसमें गुड़गांव में टूरिज्म के काम के लिए पैसे का प्रोविजन नही रखा गया है । स्पीकर साहब, गुड़गांव में शे स्टार होटल के लिए गुड़गांव बाई–पास के नजदीक जमीन ऐक्वायर की गई है लेकिन उसकी डिवैल्पमैंट नही जा रही है । गुड़गांव दिल्ली के नजदीक है और जहां जमीन ली गई शै वह बाई–पास के साथ है इस– लिए वहां पर जल्दी से जल्दी होटल बनाया जाए । यह सारा एरिया एन ०सी०आर० के अन्दर आता है और यहां पर अर्बन डिवैल्पमैंट हो रहा है । टूरिज्म डिपार्टमैंट को वहां डिवैल्पमैंट करनी चाहिए क्योंकि यह यूरिया दिल्ली के पास पड़ता है और यहां पर वहुत अच्छा काम 'चल सकता है ।

स्पीकर साहब, अब मैं ऐनीमल हस्बैन्डरी के बारे मे कहना चाहता हू । सरकार की ओर से कहा गया है कि 1987–88 के दौरान तीस पशु चिकित्सालयो का दर्जा बढ़ाकर पूरे हस्पताल बनाने और चालीस नए पशु–चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है । मुझे सी ० एम० साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि मुझ से फाउंडेशन स्टोन न रखवाए बल्कि ओपनिंग सैरेमनी करवाएं । स्पीकर साहब, होता यह है कि फाउंडेशन स्टोन तो रख दिया जाता है लेकिन उसके बाद काम कुछ नही होता और हमारे लिए वह एक मजाक बन जाता है । अगर किसी काम के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है तो उस काम को करने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए । फाउंडेशन स्टोन रखकर उस काम की सुध न ली जाए तो वह हमारी हंसी का वायस बन जाता है ।

हम लोगों को फेस नहीं कर सकते । वे लोग हमसे नाराज होते हैं । सरकार पशु धन को बढ़ावा देने के लिए काफी पैसा खर्च कर रही है । सरकार का ज्यादा जोर ऐग्रीकल्चर, इरिगेशन एरण्ड पावर और ऐनीमल हस्बैन्डरी की तरफ है और इनके लिए सौ करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपया रखा गया है जिससे कि हमारा सूबा आगे बढ़े और लोगों को रोजगार मिले तथा वे खुश– हाल हों । हमारे सूबे ने अनाज की पैदावार में भी काफी तरक्की की है और यह सब पानी और बिजली समय पर मिलने के कारण ही संभव हो सका है । अनाज की पैदावार में हम इतनी तरक्की कर गए हैं कि चालू रबी मौसम के दौरान 54. 90 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य नियत किया गया है । हालांकि हमारे पास जमीन थोड़ी है लेकिन हम पैदावार में काफी आगे बढ़ चुके हैं । स्पीकर साहब, मेरी एक प्रार्थना है कि डिवैल्पमैंट के काम के लिए जो पैसे का वितरण है वह सभी कास्टि– च्युऐंसीज में बरावर का होना चाहिए । ऐसा न हो कि एक ही कांस्टिच्युऐंसी में सारा पैसा लगा दिया जाए । हरियाणा मे हरेक का हिस्सा है और वह हिस्सा उन कांस्टिच्पुऐंसी को मिलना चाहिए ।

स्पीकर साहब, मैं आनरेबल आई० पी ० एम० साहब के नोटिस मे एक बात लाना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर कुछ इलाके जैसे गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ हैं वहां पर सिंचाई कें साधन नहीं हैं । वहां पानी बहुत कम है और वहां पर नहर भी नहीं है । पानी का लैवल काफी नीचा है । यह नहीं होना चाहिए कि जहां

नहर का पानी चलता है वहां के किसान को चार घंटे बिजली मिलती है तो गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ के किसान को भी चार घटै ही बिजली दी जाए । चार घंटे में तो पीने का पानी भी नही मिल सकता । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हरेक जगह के लिए एक ही नार्म नहीं होना चाहिए बल्कि यह होना चाहिए कि जहां जिस चीज की जरूरत है उसके मुताबिक वहां वह चीज दी जानी चाहिए । गुड़गांव और महेन्द्रगढ के इलाकों को ज्यादा घंटे बिजली देने की जरूरत है तभी वहां का काम चल सकता है । अगर इस तरह से काम होगा तो अच्छा रहेगा । यही पौलिसी हमारे सूबे को तरक्की की राह पर ले जाएगी । स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि हमको हमारे हकों से महरूम न किया जाए । इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हू ।

**चौधरी साहब सिंह सैनी ( थानेसर ) :** स्पीकर साहब, हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन ( नम्बर 4 ) बिल पर जो चर्चा हो रही है, मैं भी उसका समर्थन करते हुए कुछ बातें उसके मुताल्लिक कहना चाहचा हूं । आप जानते हैं कि अलग–अलग विभागों के लिये काफी पैसा रखा गया है । यह बड़ी अच्छी बात है । सब से पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरेक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और हरेक जिले में ऐडवोकेट्स हैं लेकिन सरकार की ओर से उनके बैठने के लिये कोई जगह निर्धारित नहीं की गयी है । वे लोग अपने टैम्पोरेरी शैड्ज और खोखे वगैरह बनाकर बैठते हैं जिससे कोर्ट्स की आउट–लुक बड़ी भद्दी लगती

है । कुरुक्षेत्र में वकीलों के लिये केवल 18 चौम्बर बनाये गये हैं जिनमें से एक पोस्ट आफिस को दे दिया गया है और वाकी वकीलों को अलाट किये गये हैं जबकि वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा शै । इसके साथ ही एक बड़ा हाल भी है जहां पर कुछ वकील बैठते हैं और बाकी बाहर झोपड़िया और खोखे बना कर बैठे है उनकी संख्या लगभग 250 के करीब है । कोर्ट्स के बाहर जो खाली जगह है वहां वकील अपने खोखे और झोपड़ियां बनाकर वैठे हुए हैं तो यह कोई शोभा वाली बात नहीं है । वह जगह अगर उन को दे दो जाए और साथ में नक्शे वगैरह भी बनाकर दे दिये जाए तो वे वहां चौम्बर बनाकर तरतीबवार बैठ सकते हैं । इससे उनको काफी सहूलियत मिलेगी । इसी तरह मे जो नये कम्पलैक्स जहां बने हैं वहां पर भी वकीलों के लिये नये चौम्बर बना दिए जाएं तो काफी उचित रहेगा । इस तरह से वहां की आउटलुक भी ठीक रहेगी और वकीलों को बैठने के लिये जगह भी उपलब्ध होगी । इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो पढ़ लिखे लोगों की जमात है, जो समाज को न्याय दिलाने में सहायक होती है, उनको इससे मदद मिलेगी । इससे आगे मैं हस्पतालो के बारे में चची करूंगा । हमारे कुरुक्षेत्र में एक लोक– नारायण जय प्रकाश नाम से हस्पताल है जोकि 100 बिस्तरों का है वहां पर कुछ डाक्टर्ज के लिये रैजीडैन्सिज भी बने हुए हैं जोकि थोड़े हैं । मेरी प्रार्थना है कि हस्पताल की जो जगह खाली पड़ा है वहां पर डाक्टर्जके लिये और रेजीडैसिज बन सकते हैं । इस वक्त सी ० एम ० ओ ० साहब और एक या दो डाक्टर्ज ही वहां पर रह रहे हैं

। अगर और रैजीडैन्सिज वना दिए जाए तो वहां और डाक्टर्ज भी रह सकेंगे । बहां पर ज्यादा डाक्टरों के रहने से पब्लिक को काफी सहूलियत होगी । इसलिए मेरी इस बात को मद्देनजर रखते हुए वहां हस्पताल के पास कुछ और रेजीडेंसियल क्वार्टज डाक्टरों के लिये बनाये जाने चाहिये । उस हस्पताल में कुछ ऐसे कमरे हैं जिन में से कुच कमरों को तो सी० एम० ओ० साहब ने स्टोर बना रखा है और कुछ में डाक्टर्ज रहते हैं । इसलिये स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आवेदन है कि इस काम के लिये और पैसे का प्रावधान किया जाए ताकि डाक्टर्ज के लिये और रैजीडैन्सिज बनाए जा सकें जिससे कि मरीजों को काफी लाभ हो सकता है । इससे अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह रोड्ज से संबंधित है । पिपली से कुरुक्षेत्र जाते समय केवल एक ही लिंक रोड हे । आप जानते हैं कि वह वर्ल्ड फेम सिटी है लेकिन सड़कें बड़ी न होने के कारण काफी परेशानी होती है । अभी सितम्वर में सूर्य ग्रहण का मेला लगने जा रहा है, इसलिये उस लिंक रोड को फोर लेन कर दिया जाए ताकि आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो । आशा है कि सरकार मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देगी और जो–जो मांगे मैंने की हैं, उनको अवश्य ही पूरा किया जाएगा । इन शव्दों के साथ मैं इस विल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं । जय हिन्द ।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी ) :** स्पीकर साहब, वित्त मन्डी महोदय ने जो ऐप्रोप्रिऐशन बिल सदन में ररवा है, मैं उसका

समर्थन करता हूं । अर्बन डिवैल्पमैंट के बारे में मेरे कई साथियो ने यहां पर चर्चा की है । हर शहर में सफाई के लिहाज से कोई अच्छे ढंग का काम नहीं है क्योंकि जितनी संख्या सफाई कर्मचारियों की आज से 20 –25 साल पहले थी अब भी वह संख्या वैसे की वैसी ही है हालांकि अब शहरों की आबादी कई गुना बढ़ गयी है । हर शहर की आबादी काफी बढ चुकी है इसलिये जो अधिकारी हैं, उनको डेली वेजिज पर आदमी रखकर सफाई करवानी पडती है । इसी कारण से सफाई वगैरह अच्छी नहीं होती औंर रुपया भी ज्यादा खर्च होता है । इसलिये मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि म्यूनिसिपल कमेटीज की जो–जो मांगे है, उनको अवश्य ध्यान में रखा जाए और स्वीकार किया जारा तथा सफाई वगैरह के लिये जितने और सफाई कर्मचारी रखने की उनको आवश्यकता है, उसकी मन्जूरी दे दो जाए ताकि परमानैन्ट तौर पर हरेक म्यूनिसिपल कमेटी में सफाई कर्मचारी हो । अगर एम्पलाईज रेगुलर होंगे तो वे काम भी अच्छी तरह से कर सकेगें । इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि वित्त मन्त्री महोदय अवश्य मेरी इस बात को स्वीकार करें ।

स्पीकर साहब, इससे आगे मैं फिशरीज के बारे में भी कहना चाहता हूं । आज किसानों के पास अपनी जमीन बहुत कम रह गयी है । इसलिये सरकार की ओर से किसानों को अन्य सहूलियतें मिलनी चाहियें । जैसे मछली पालन का धन्धा है । इसके लिये सरकार की ओर से लोन्ज वगैरह भी मिलने चाहिये ।

लेकिन किसानों को लोन्ज तब मिलते हैं जब इरीगेशन विभाग वाले, किसानों को जोहड़ मॅं पानी की सप्लाई का कनैक्शन देते हैं । मेरा कहने का मतलब यह है कि इरीगेशन विभाग वाले अविकारी किसानों को पानी के कनैक्शन नहीं देते और किसान जोहड़ों में पानी नहीं भर पाते जिसके कारण उनको लोन नहीं मिलता है । इसलिये वे किसान जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है और न ही कोई दूसरे साधन हैं, वे अपने बच्चों को इस काम धन्धे में लगाने से वंचित रहे जाते हें । मैं समझता हूं कि भूमिहीन किसानों या जिनका और कोई धन्धा नहीं है, उनके लिये व उनके बच्चों के लिये बिजली वगैरह का कनैक्शन जल्दी ही दिलवाया जाए और साथ ही लोन भी कम इंटैरस्ट पर दिलवाया जाए ताकि वे लोग अपना धन्धा कर सकें । इसके साथ–साथ मैं कहना चाहूंगा कि फिशरीज पालन के धंधे के लिये बीमा योजना चालू की जानी चाहिये । डस के लिये भी सरकार को सारा खर्चा वहन करना चाहिये ।

स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर आज सड्कों का जाल बिछा हुआ– है हरियाणा प्रदेश इसके लिये सारे देश में प्रसिद्ध हैं कि हरियाणा के हर शहर को हर गांव के साथ सड्कों द्वारा मिलाया गया है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि मेरे हल्के में खरखरा वगैरह राक दो सड़कें हैं, जिन पर मिट्टी वगैरह डालने का काम हो चुका है लेकिन काम अभी तक पूरा नही हुआ है । (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए ) डिप्टी

स्पीकर साहब, मेरे हल्के में एक कालेज बनने जा रहा है उस कालेज को सड़क के साथ जोड़ने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । रास्ता कच्चा है जब तक उसको पक्की सड़क से न जोड़ जाएगा तब तक स्टुडैन्टस को आने जाने में असुविधा होगी । मेन सडक को कालेज तक मिलाया जाए । यह बड़ा आवश्यक है । इससे अगला प्वायंट मैं टूरिज्म के बारे में कहना चाहता हूं । गाबा साहब ने भी इस बारे में कहा है । हरियाणा सरकार के टूरिज्म कुए अन्डर जो बारज होती हैं, उनके लाईसैन्सिज तो अभी चालू हैं लेकिन प्राईवेट वारज के कैन्सिल कर दिए गए हैं । इससे लोग सोचेंगे कि सरकार खुद तो अपने होटलों में इस बात का प्रोत्साहन देती है लेकिन प्राईवेट बारज वालों को इस बात की कोई छूट नहीं है । लोग तो यह कहेंगे कि सरकार का शराबबन्दी के बारे में केवल मात्र दिखावा है । खुद तो होटलों में शराब पिलाती है और दूसरीं तरफ इस के लिये बैन कर रखा है । इसलिये इस बारे में मेरी सजैशन है कि टूरिज्म के होटलों में जहां शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिलता है वहां यह बारज वगैर का धन्धा विल्कुल बन्द होना चाहिये । इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि सरकार को इससे काफी फायदा हैं लेकिन लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिये । आशा हए कि सरकार मेरे इस सुझाव पर ध्यान देगी । ऐजूकेशन के बारे में भी इसमें काफी प्रावधान रखा गया है । अभी कई साथी बता रहे थे कि स्कूलों के अन्दर हरिजन लड़कों के लिए सभी सहूलियतें हैं । मैं चाहूंगा कि वीलर सैकशन के जितने भी बच्चे है उन सब को भी की ऐजूकेशन की

सुविधा मिलनी चाहिए । आज हम देखते हैं कि हरियाणा के अन्दर प्राईवेट स्कूलों का जाल विख गया है । हर शहर में सैकड़ों की तादाद में प्राइवेट पब्लिक स्कूल खुल चुके हैं । इनमें एक बच्चे का सौ रुपये महीना खर्च आता है । आज यह एक दुकानदारी बन चुकी है । मैं मांग करूंगा कि ऐसे स्कूलों पर पाबन्दी लगाई जाए । आज जहां जिसकी मर्जी होती है स्कूल खोल कर बैठ जाता है । इन स्कूलों में बिना ऐक्सपीरिएंस के मास्टर्ज को रखा जाता है । जिन लोगों के पास पैसा है वे तो अपने वच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ा सकते हैं लेकिन गरीव आदमी ऐसा नही कर सकता । हर मां बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी ऐजूकेशन हासिल करे लेकिन गरीब लोगों के बच्चे ऐसे स्कुलों में नहीं जा सकते । वे तो सिर्फ गवर्नमैंट स्कूलों मे ही जा सकते हैं जहां बैठने का पूरा प्रबन्ध नही है । प्राइवेट दुकानों के सफल होने का यह भी एक कारण है । मैं हांसी की बात करता हूं कि वहां किसी भी स्कूल की गवर्नमैंट बिल्डिग नहीं है । पिछले 50 सालों से वहां पर प्राइवेट बिल्डिगों में ही स्कूल चल रहे हैं । उन बिल्डिगों की हालत बहुत खस्ता है और वे किसी वक्त भी गिर सकती हैं । जैसे पीछे पंजाब में हुआ था, कई बच्चे मर गए थे । प्राइवेट बिल्डिग होने की वजह से गवर्नमैंट उसकी रिपेयर पर पैसा खर्च नही करती । मालिक भी उन पर खर्चा नहीं करता क्योंकि वह चाहता है कि मेरी बिल्डिग खाली हो जाए ताकि वह उसको ज्यादा किराए पर चढ़ा सके । सरकार ने पीछे एक प्रोग्राम भी बनाया था और मैं चाहूंगा कि जितने भी स्कूल प्राइवेट बिल्डिंगों मे चल रहे हैं उन

सभी बिल्डिंगों को ऐक्वायर करके नई बिल्डिग्ज बनाई जाए । ऐसा करने से गरीब बच्चों को स्कूलों में बैठने की सहूलियत होगी और एक अच्छा वातावरण भी. बनेगा । सरकार ऐसा प्रबन्ध करे कि प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा बच्चे न जाएं । प्राइवेट स्कूलों पर पाबन्दी लगनी चाहिए । ऐजूकेशन का तभी फायदा होगा जब गरीब आदमी इससे फायदा उठा सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

**चौधरी सूबे सिंह पुनिया (उचाना कलां ) :** डिप्टी स्पीकर साहब, मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत हरियाणा विनियोग विधेयक (संख्या 4 ) पर जो चर्चा चल रही है, मैं उसमें अपने आप को शामिल करता हूं । इसमें जो मांगें रखी गई हैं मैं उनका भी समर्थन करता हूं । पिछले दिनों राज्य के कई जिलों में वड़ी भारी ओलावृष्टि हुई । आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने इस विषय में आज सदन में काफी प्रावधान भी रखे हैं । जो किसान ओलावृष्टि मे प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसलों का नुक्सान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा । यह बहुत सराहनीय कदम है । मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जो स्पैशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं उनमें सरसों और मेथी की फसलों पर विशेष ध्यान दिया जाए । कई जगह तो ये फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं । किसान जब फसल काटेगा नौ उसको कुछ भी नहीं मिलेगा । इनी तरह मे किसान तो इससे प्रभावित हुए ही है उनके साथ बढई और लुहार भी प्रभावित हुए हैं क्योंकि वे हमारे यहां हल पर काम

करते हैं । बढ़ई और लुहार किसान से एक मन अनाज के पीछे आधा किलो अनाज लेता है । इसलिये इन लोगों को भी काफी धक्का लगा है । अगर किसान का 100 मन अनाज पैदा होता है तो इन लोगों को 50 किलो अनाज नि तता हैं । मैं अपनी सरकार की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता कि इसने किसानों को बहुत बड़ा सहारा दिया है । अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं आपके द्वारा माननीय मन्त्रियों के नोटिस में लाना चाहूंगा । मेरे हल्के मैं कुछ सडकें अधूरा पड़ी हुई हैं । कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनके न होने की वजह से कुछ गांव मण्डी और ब्लकि से नही जुड़े हुए हैं । इन सडकों के नाम हैं सेंथली–लितानी रोड, सुखरा–दरोली खेड़ा, झील–भगवानपुरा अलीपुरा–कावरछा और करसिन्धु–छातर । इसी तरह से मेरे हल्के में एक धनखडी गांव है जो उचाना ब्लौक में पड़ता है । यह गांव उचाना से सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है । लोगों को जीन्द होकर उचाना आना पड़ता है । अगर उस गांव को उचाना के साथ जोड़ दिया जाए तो रास्ता काफी छोटा हो जाएगा । इसके अलावा मेरे हल्के में दो गांव ऐसे हैं जिनके छोटे–छोटे टुकड़े सड्क के बनने हैं । अगर इनको जोड़ दिया जाए तो शूगर मिल और परचेज सैंटर में गन्ना पहूंचाने के लिए लोगों को वहुत सुविधा मिलेगी । पहली सड़क है 'बम–झड़ी से भौंसला और दूसरी है मोहनगढ़ से भौंसला । अगर इनको सड़क से जोड़ दिया जाए तो शूगर मिल की दूरी बहुत कम रह जाती है । इसी तरह मे जो अबूरी. सडके हैं जोकि 4– 5 साल से पड़ी हुई हैं उनको भी जोड़ दिया जाए । इससे किसानों और

विद्यार्थियों को काफी सुविधा होगी । इमके अलावा शिक्षा के विषय में मेरे हल्के मे लड़कियो के लिए काफी संस्थाएं हैं । मेरे हल्के में गेंडा खेड़ा में गुरुकुल है उसके भवन का बहुत अच्छा निर्माण हुआ है । मैं चाहता हूं कि इस विद्यालय को स्थाई मान्यता दी जाए ताकि सरकार के अनुदान से स्कूल के अध्यापकों तथा दूसरे स्टाफ को तनखाह समय पर मिल सके ओर स्कूल आगे वढ सकें । मेरे हल्के का प्रमुख कस्बा उचाना है जिसके अन्दर व्लौक हैडक्वार्टर, तहसील हैडक्वार्टर, मंडी और बहुत से केन्द्र हैं । लेकिन वहां पर अभी तक कोई सिविल हस्पताल या कम्यूनिटी हैल्थ सैटर नहीं है । पिछले दिनों वहां की सिविल डिस्पैसरी को पी ० एच ० सी ० में अपग्रेड किया था लेकिन अभी तक वहां पर लेडी डाक्टर नहीं आई है । मैं अनुरोध करूंगा कि उचाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कस्बा है और वहां पर एक सामुदायिक विकास केन्द्र खोलने की योजना बनाई जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, उचाना कस्बा एक नगर का रूप लेता जा रहा है । वहां की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है । वहां पर सीवरेज की एक स्कीम काफी समय से लम्बित पड़ी है । इस स्कीम को पूरा पैसा पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के पास पहुंचा नहीं है । अगर पूरा पैसा विभाग को देकर इस स्कीम को चालू कर दिया जाये तो उससे वहां के लोगों को सीवरेज की सुविधा हासिल हो जायेगी । मेरे इलाके में सिंचाई की सुविधा पिछले सालों से बढ़ती जा रही हैं और अनाज की पैदावार भी पहले से

काफी बढ़ी है । आपके माध्यम से खाद्य एवं आप्रूर्ति मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मेरे हल्के में दनोदा गांव के अन्दर जो इस समय परचेज सैन्टर है उसको मण्डी पेन रूप में अपग्रेड किया जाये । इसी' प्रकार से धनखेड़ी गांव में एक परचेज सैन्टर खोना जाये ताकि किसानो को अपने अनाज की ढुलाई में दिक्कत का सामना न करना पड़े और पेनको अपनी उपज का पुरा मूल्य मिल सके । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे इलाके के काफी भाग मे अब भी सिंचाई की बड़ी भारी असुविधा है क्योंकि कुष्टरू गांवों में बहुत लम्बा सफर तय करके पानी कौं पहुंचना पडता है । उसका कारण यह है कि वे गांव नहर के टेल पर पड़ते हैं । जिन गांवों में सिंचाई के पानी की 'दिक्कत हुएए वे हैं, खटकड रोजखेड़ा, गोगडिया, कालता, भौसला, कसून छातर और मण्डी कलां आदि । इन गांवों में जिस किसान के पास 50 एकड जमीन है उसमें से एक या दो एकड में ही गेहूं की बिजाई हो पाती है । इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस इलाके को पानी पहुंचाने का कोई न कोई प्रवन्ध अवश्य करना चाहिए । सिंचाई एवं बिजली मन्त्री वहां की सारी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं । इस इलाके का सवे करवा कर लिपट इरीगेशन या दूसरी स्कीमों से वहां पर पानी. पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों कौ भी अपना जीवन स्तर सुधारने में मदद मिल सकै । मेरे इलाके के कुछ गांव नरवाना के साथ लगते हैं । वे गांव सेन की गम्भीर परि– स्थितियों से गुजर रहे हैं । यदि इन गांवों में थोड़ी बहुत बून्दा–बान्दी हो जाये या आगे पीछे से पानी आ जाए तो हालत

बहुत खराब हो जाती है । इसका कारण यह है कि वहां से सिरसा ब्रांच निकली हुई है । एक तो इस नहर की वजह से सेम रहती है और दूसरी वहां पर पानी खड़ा रहने से फसलें खराब रहती है । इन गांवों के लिये डीवाटरिग का कोई न कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिए । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सरकार मेरी कास्टिचुऐंसी के सुन्दरपुरा, बुढन पुर, डोहाना, खेड़ा, भागलपुर आदि गांव में सम्प वैल्ज बनाये या ट्यूबवैल्ज का या और कोई प्रबन्ध किया जाये ताकि वहां के लोग भी अपनी अधिक से अधिक जमीन में फसलें बीज सकें । यदि सम्प वैल्ज के जरिए या ट्यूबवैल्ज के जरिए इन गांवों का पानी नहर में डाल दिया जाये तो उससे लोगों को काफी राहत मिल सकती है। ऐसा होने से वहां के लोग भी अपनी कृषि की पैदावार को वड़ा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में जीन्द जिले के लिये जीन्द 'में एक शूगर मिल लगा हुआ है। जब वहां पर किसान अपना गन्ना लेकर जाते हैं तो उनको कई बार दो–दो दिन व हफ्तों–हफ्तों ठहरना पड़ता है । इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर शूगर मिल के पास एक रैस्ट हाउस किसानों के ठहरने के लिए बनाया जाना चाहिए ताकि किसान लोग वहां पर आराम से रह सकें और सर्दी से बच सके । लोगों को वहां पर शूगर मिल के पास एक रैस्ट हाउस खोलने की बर्ड भारी मांग है । मुझे उम्मीद है कि सरकार हुस दिल में कोई न कोई कदम अवश्य उठायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय. सरकार ने जिस तरह से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है उसी तरह से कृषि के सहायक उद्योग धन्धे जो है उनको भी उद्योग का दर्जा दे देना चाहिए । आज कृषि की जोते बहुत छोटी–छोटी होती जा रही हैं । आज बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है । देहात से बेरोजगारी की समस्या को दूर करेने के लिँए यदि कृमि के सहायक उद्योग धन्धों को उद्योग का दर्जा दे दिया जाता है तो उससे देहात के पढे लिखे नौजवान और दूसरे अनपढ़ नौजवान खेती की अधिक से अधिक पैदावार कर सकेंगे जिससे काफी हद तक गांवों से बेरोजगारी दूर हो जायेंगी । कृषि के जो सहायक उद्योग धंधे हैं, उनके बारे में भी मैं हाउस में जिक्र कर देता हुं कि पशुपालन. मछली. पालन, मुर्गी पालन, खुम्भ की खेती और फलफ्ल का खेती आदि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए । मेरे कहने का मतलव यह है कि उद्योगों को जो कर्जे की सहूलियतें व दूसरी सहूलियतें मिलती है, उसी प्रकार की सुविधाएं कृषि के इन सहायक उद्योग धन्धों को भी मिलना चाहिए । यदि ऐसी सुविधाए कृषि के सहायक उद्योग धन्धों को मिल जाती है तो हमारे काफी नौजवान कृषि के सहायक उद्योग धन्धों के प्रति आकर्षित हौ सकेंगे और अपने जीवन स्तर कौ काफी हद तक सुधार सकेंगे । नौजवानों की बेरोजगारी की गम्भीर समस्या से यदि छुटकारा पाना है तो सैल्फ ऐम्पलायमैंट की जो स्कीम है उसको और बिलकुल तथा व्यापक बनाया जाना चाहिए । इस बारे में मेरा सुझाव है कि दस्तकारी व कृषि से सम्बन्धित उद्योग धन्धो को इस सैल्फ

ऐम्पलायमैट स्कीम मैं शामिल किया जाये ताकि वे अपनी इच्छा के मुताबिक अधिक प्रोडक्ट पैदा कर सकें ऐसा होने से वे वही चीज पैदा करेंगे जिसके बेचने पर उन्हें अधिक मुनाफा मिल पायेगा । इन्ही शब्दों के माथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

**श्री दया नन्द शर्मा ( राजौन्द ) :** डिप्टी स्पीकर साहब, इस समय हाउस मे ऐप्रो प्रिएशन बिल (नं ० 4 ) पर बहस चल रही है । डिमांड नं ० 4 रैवेन्यू से सम्बन्धित है । आज मुख्य मन्त्री महोदय ने हाउस में स्टेटमैंट दी. थी कि जिन इलाकों के अन्दर ओले पड़े हैं उनको मुआवजा देंगे । पिछले हफ्ते हम अपने हल्कों से हो कर आए हैं । वहां पर जो गिरदावरी हो रही है वह सारे गांव को एक ईकाई मान कर की आ रही है यानि जिस गांव की टोटल जमीन में 1/3 या 2/3 हिस्से में ओले पड़े हैं उन्हीं की गिरदावरी की जा रही है । डिप्टी स्पीकर साहब, इस ढंग ने गिरदावरी करना सारे हरियाणा के लिए ठीक नही है, क्योंकि गांव में कुछ भाग में तो ओले पड़ गए और कुछ भाग में ओले बिल्कुल नही पड़े । नुक्सान तो उन्हीं किसानों का हुआ जिनके खेत में ओले पड़े है । यदि किसी गांव का रकबा 22 हजार एकड़ का है और ओले सिर्फ 40– 50 या 100 एकड़ जमीन में पड़े है तो नुक्सान तो सिर्फ उन्हीं किसानों का हुआ जहां पर ओले पड़े हैं । ऐसी सूरत में सरकार ने मुआवजा देने के लिए गिरदावरी का जो क्राइटेरिया अपनाया हुआ है वह ठीक नहीं है । मैं यह चाहूंगा कि

सारे गांव की इकट्ठी गिरदावरी एक ईकाई मान कर करने की बनाये हर गांव के हर खेत की अलग अलग गिरदावरी होनी चाहिए । मेरे कहने का मतलब यही है कि जिन जिन किसानों की फसलें ओलों की वजह से प्रभावित हुई हैं उन्हीं को मुआवजा मिलना चाहिए । यदि किसी किसान की दो एकड़ फसल को नुकसान हुआ है तो उसे दो एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और यदि किसी की 5 एकड़ जमीन में ओलों से नुकसान हुआ है तो उसै 5 एकड़ जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए । मेरा सरकार को फिर सुझाव हे कि टोटल गांव के एरिया को शामिल करने की जो पालिसी अपनाई हुई है इसको बदल देना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले दिनों जब प्रधान मन्त्री जी– हरियाणा के अन्दर आये थे तो मुख्य मन्त्री महोदय ने एक घोषणा की थी कि सूखाग्रस्त इलाकों की हम पूरी मदद करेंगे । जब मुख्य मन्त्री महोदय जीन्द गए थे तो हमने कहा था कि हमारे एरिया का सर्वे करवाओ जिसमें जुलाना और राजौन्द का एरिया शामिल है । ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहां पर ट्यूबवैल्ज भी नहीं लग सकते और न नहर का पानी कामयाब है । ये एरियाज जीन्द जिले के सबसे पिछड़े हुए एरिया हैं । उस समय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि इस एरिया के बारे में कुछ विचार करेंगे । जुलाना को तो सूखाग्रस्त घोषित कर दिया लेकिन राजौन्द को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया । यह मुझे नहीं पता कि सरकार ने किन कारणों से राजौन्द को सुखाग्रस्त घोषित नहीं किया? हमारे आई०

पी ० एम० साहब यहां पर बैठे हैं । इनको पता है कि मेरे हल्के में जितनी भी नहरें पड़ती हैं वे सारी की सारी टेल पर पड़ती हैं । मेरे एरिया का आधे से ज्यादा हिस्सा बगैर इरीगेशन के रह जाता है । मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरे हल्के के जिन गांवों में नहर का पानी नहीं लगता वहां पर पानी पहुंचाने का नहर के अलावा कोई और प्रबन्ध किया जाये । मेरे हल्के के 5–6 गांव जैसे कुचराना कलां और कुचराना खुर्द आदि हैं इनकी जमीन रेतीली है । इन गांव की जमीन टीलों की जमीन है । इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर एम० आई० टी ०–सी ० के ट्यूबवैल्ज लगाएं जाएं तकि वहां पर अधिक पैदावार वहां के किसान लेखके' । सरकार की पालिसी का भी मुझे पता नही है । मुझे बसाया गया है कि एम० आई० टी० सी० ट्यूबवैल्ज नहीं लगती मैं चाहूंगा कि जहां पर पानी नहीं लगता वहां पर भिवानी की तरह लिपट इरीगेशन की स्कीम सरकार नहीं बना सकती तो कम से कम एम० आई० टी ० सी ० के ट्यूबवैल्ज ही वहां पर लगवा दिए जाएं । लिपट इरीगेशन के लिए तो यह कह कर जवाब ना में आ जायेगा कि इस पर वहुत अधिक खर्च आयेगा । मैं अपने इलाके के उन लोंगों के लिए सरकार से फिर प्रार्थना करता हूं कि वहां पर एज ए स्पैशल केस ट्यूबवैल्ज एम० आई० टी ० सी ० से लगवाएं । मैंने तीन चार रजबाहो की बात आई० पी ० एम० साहब से की थी लेकिन अभी तक वह सिरे नहीं चढ़ी । मैं आई० पी ० एम० साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि हमारे हल्के में अभी बहुत बैकवर्डनैस है इसलिये वहां पर भी सिचाई कीं सुविधाएं मिलनी

चाहिए । मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि उस इलाके को भी सूखाग्रस्त धोषित किया जाना चाहिए ।

आजकल सरकार लोगों को सुविधा देने के लिए बेरोजगारी लोन देती है । जब सरकार अच्छा काम करेगा तो उससे सरकार की पब्लिसिटी होगी और लोगों को भी सुविधा होगी लेकिन यह काम उल्ट हो रहा है । अगर कोई भाई लोन लेता है तो उसको आधा लोन पल्ले पड़ता है बाकी का लोन बीच वाले खा जाते हैं। इसलिये मैं बार बार सरकार से रिक्वैस्ट करुंगा कि इस लोन के तरीके को सरल बनाया जाये वरना यी सरकार के लिए अभिशाप है । एक तो बेरोजगारी लीन लोगों को पूरा नहीं मिलता है दूसरे जितने नेशनेलाइज्ड बैंकों के मेनेजर हैं वे पास नहीं लगने देते । अगर हम उन्हें अप्रोच करते है तो वे कहते हैं कि हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और हम लोगों को कुछ नहीं समझते । हम उन लोगों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते । आजकल डैमोक्रेसी में कुछ सख्ती करते हैं तो वे यूनियनबाजी और स्ट्राइक में पड़ जाते हैं । इसलिए ऐसी ऐजेन्सी नैशनल लैवल पर होनी चाहिए जो लोन के तरीके को सरल कर सके । जहां तक बेरोजगारी की बात है, वह तो पापुलेशन के हिसाब से बढ़ती है । हमारी सरकार की तरफ से बेरोजगारी द्र करने के लिए काफी साधन जुटाये जाते हैं लेकिन लोन देने के तरीके को सरल बनाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस ऐप्रोप्रिऐशन बिल का समर्थन करता हूं और रिक्वैस्ट करता हूं कि इसे पास किया जाये ।

**सेठ राम दास धमीजा ( अम्बाला छावनी ) :** आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवादी हू कि आपने मुझे बालने के लिए टाईम दिया । मैं हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन बिल (नम्बर 4 ) पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा । सब से पहले ऐक्साइज एन्ड टैक्सेशन के बारे में दो लफ्ज कहने हैं । सरकार टैन्ट और क्राकरी के टैक्स में कुछ रियायतें दे रई। है । यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नमक की थैली दो रुपये या डेढ़ रुपये की मिलती है और उसके लिए जो प्लास्टिक की थैली पांच पैसे की आती है उसपर टैक्स है लेकिन नमक पर नहीं है । दुकानदार का अलग–अलग खाता जोड़ते जोड़ते परेशान करने वाली बात है । मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में भी विचार करेगी । जहां दो रुपये की चीज पर टैक्स नहीं लगता है तो पांच पैसे की चीज को टैक्स की क्यों नही किया जाता आगे बिल्डिग्ज और रोडज के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । मैं अपनी कास्टिचुऐंसी के लिए पांच साल से पांच किलोमीटर सड़क के लिए कहता आ रहा हूं । मैं तो सरकार को कह कह कर थक गया हुं लेकिन यह पांच किलोमीटर की सड़क नहीं बनी है । सरकार हर साल कहती है कि पांच किलोमीटर की सड़क अम्बाला में बनेगी लेकिन बनती नहीं है । यदि एक किलोमीटर भी एक साल में बनती तो अब तक पांच किलोमीटर बन जानी थी । इसलिए मैं समझता हूं कि इस बारे में मन्त्री जी विचार करेंगें मन्त्री जी का रास्ता भी यहीं है, इस सड़क के बगैर वे अपने घर नहीं पहुंच सकते । साढ़े तीन

किलोमीटर फौर लेन और डेढ़ किलोमीटर बवियाल रोड है । अगर यह सड़क वन जाती है तो मेरे हल्के का मसला हल हो जायेगा ।

इसके बाद मैं ऐजूकेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । अम्बाला जिले में कोई भी सरकारी कालेज नही है । अम्बाला कैन्ट में जितने भी कालेज हैं वे सब सोशल और धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं । वहां पर सरकारे का कोई कालेज नहीं है । सरकारी कालेज तो वहां पर न अम्बाला शहर में है और न ही अम्बाला कैन्ट में है खासतौर पर लडकियां का कालेज वहां पर होना जरूरी है । सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है । हमारी सरकार भी कहती णै और लोग भी कहते हैं कि एक लड़की पढ़ती है तो पूरा खानदान का खानदान पढ़ता है और अगर एक लड़का पढता है तो लड़का ही पढता है । सरकार जो लड़कियों के पांच सौ स्कूल खोलने जा रही है, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है । जिस तरह से आजकल नई आबादी बढ़ रही है उसके लिए स्कूलों की आवश्यकता है । हमारे यहां जो महेशनगर है वहां की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है । जायदाद बेचने वाले कोई भी जमीन का टुकड़ा स्कूल के लिये या पार्क वगैरह के लिये नहीं छोड़ते हैं बल्कि नक्शा पास करवाकर मकान बनाते जाते हैं । हर प्रापर्टी डीलर को कुछ न कुछ जगह स्कूल के लिये और कम्युनिटी सैन्टर के लिये छोड़नी चाहिए । अब मडेशनगर की आबादी 25 हजार के करीब हो चुकी है लेकिन इस आबादी में सब के सब प्राईवेट स्कूल हैं । वहां पर कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है । प्राईवेट स्कूलों

की फीस बहुत ज्यादा होती है । जैसा कि भाई अमीर चन्द मक्कड जी ने बताया था प्राइवेट स्कूल की फीस औसतन 100 रुपये होती है । मैं थोड़ा नैशनल कैरेक्टर के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं । स्कूलों में एक पीरियड नैशनल कैरेक्टर के बारे में हे चाहिए ताकि बच्चों का नैशनल कैरेक्टर बने । अगर नैशनल कैरेक्टर नहीं बनेगा तो कौम कैसे बनेगी? आप कालेज और स्कूलों में देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही पै । हमारे स्कूलों में जहां मौरल ऐजूकेशन केलिए एक पीरियड रखा हुआहै वहां नैशनल कैरेक्टर केलिये भी एक पीरियड रखा जाना चाहिए । अम्बाला कैन्ट में 12 स्कूल गवर्नमैंट के हैं । तीन हाई स्कूल हैं, तीन मिडन स्कूल हैं और बाकी छः प्राइमरी स्कूल हैं । उन 12 स्कूलों में चालीस साल से कोई पैसा नहीं लगा है । कई स्कूलों की छतें गिरने वाली हैं । जो पैजाब में स्कूल के हालात हुए हैं वही हालात यहां होंगे । सरकार की तरफ से दो हजार रुपये दिये जाते हैं उससे न बिल्डिग बन पाती है और न ही स्कूल की मरम्मत ही हो पाती है । वे. पैसे इधर उधर दे कर खत्म हो जाते हैं । कम से कम इतने पैसे तो देने चाहिएं जिससे एक कमरा बन सके या दो बन सके । इतना नौमीनल रुपया देने से कभी बिल्डिग नहीं बनती । जिस शहर की जितनी आबादी है या जितने पैसे की वहां जरूरत है, उसे वहां उतना पैसा दिया जाना चाहिए 1 कोई क्राइटेरिया तो फिक्स किया जाये । पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अम्बाला कैन्ट सारे हरियाणा में नम्बर एक पर है लेकिन यह सोशल संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं की वजह से है । इसलिये मैं चाहता हूं कि

सरकार भी अपना कुछ हिस्सा डाले । जहां तक अर्बन डिवैल्पमैंट की बात है, शहरों में जो लोग शहरी हैं वे तीस परसैन्ट हैं और 70 परसैन्ट टैक्स देते हैं लेकिन उनका हक उन्हें पूरा नही मिलता शहरों में सफाई का नाकिस इन्तजाम है । म्यूनिसिपल कमेटियों के पास पैसा नहीं है । हर म्यूनिसिपल कमेटी में एक एक रिफ्यूज कुलैक्टर दे दें तो सौ कर्मचारियों का काम वह कर देता है । मेरे शहर में 273 सफाई कर्मचारी हैं । वहां पर 700 की जरुरत है । जहां सात सौ की जरुरत है वहां पर पौने तीन सौ होंगे तो ऐसा ही होगा । शहरों मैं सफाई का इन्तजाम पूरा करने के लिए सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए । जहां पर आबादी बढ़ गई है और जो कालोनीज काफी मुद्दत से रेगुलेराइज हो गई हैं उन कालोनीज में बड़ी भारी तकलीफ है । अन्दर शहर में इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है लेकिन जो बैरुनी आबादी है जिसमें मकान तो एक लाख रुपये से लै कर दस लाख रुपए तक के बन गये हैं लेकिन वहां पर सड़क और नालियों का कोई इन्तजाम नहीं है । जब बारिश के दिनों में उन कालोनीज में जगह–जगह पर पानी खडा हो जाता है तो वहां पर तालाब से बन जाते हैं जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कत –होती है । हाउस में लोन देने के बारे में भी बात आयी । लोन के फार्म वैको को भेजे जाते हैं । दो हजार रुपये का लोन देते हैं तो पांच सौ फार्म भेज दिये जाते हैं । उनमें से कुल 100 आदमियों को लोन दिया जाता है । अम्बाला की पोजीशन यह है कि जो आदमी कमंजोर होता है बैंक वाला उसकी कोई बात सुनता ही नहीं है । वे कहते हैं कि हमारा

भारत सरकार से ताल्लुक है । एम० एल० एज० की तो कोई ' सुनाई ही नही होती है । फार्म पहले ही जांच करा कर देने चाहिए ताकि जितने आदमियों के फार्म जाते उनमें से पचास और 75 परसेन्ट कौ लोन मिल जाये । अगर पांच परसेन्ट के ही मिलना है तो बाकी 95 परसैन्ट तो वापिस हो जायेंगे । इतनी ही दरखास्तें ऐप्रूव की जायें जितनी दरखास्तो का लोन पास हो सके । इन्डस्ट्री में हरियाणा ने काफी तरक्की की है । सन् 1966 में चार हजार के करीब इन्डस्ट्रीज थी लेकिन अब 70–71 हजार के करीब हो गई हैं । अम्बाला छावनी में आज से 15 साल पहले इन्डस्ट्रियल एरिया बना था लेकिन वहां पर पूरे प्लाटस नहीं बिके । वहां पर कोई इन्तजाम नहीं है । 15 साल से वह इन्डस्ट्रियल एरिया आज तक पनप नहीं सका । छोटी छोटी और बडी– बड़ी इन्डस्ट्रीज वहां पर जाना चाहती हैं लेकिन वहां पर पूरी सुविधा न होने के कारण नही जा रही हैं । खासतौर पर वहां पर बिजली की दिक्कत है । अगर उस इन्डस्ट्रियल एरिया की तरफ ध्यान दिया जाये तो यह एस्टेट भी आबाद हो सकती. है । मैं थोड़ा ऐनिमल हस्वैन्डरी के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं । जहां पर ज्यादा पशुओं की तादाद हो वहां पर ज्यादा हस्पताल खोले जाने चाहिएं । ऐसा भी देखने में आया धै कि जहां पर पशुओं की तादाद पांच सौ है वहां पर हस्पताल पांच हैं लेकिन जहां पर पशुओं की तादाद 20 हजार है वहां पर हस्पताल दो हैं । मेरी अर्ज है कि जितने दूध देने वाले जानवर हैं उनकी गिनती के

हिसाब से हस्पताल खोले जाने चाहिएं । कोई क्राइटेरिया तो हो कि इस हिसाब से हस्पताल खोलेंगे ।

**12.00 बजे ।**

हमारे यहां अम्बाला कैन्ट में सब से पुराना बस स्टैन्ड है । वह सब से ज्यादा कमाने वाला बस स्टैन्ड है । सरकार ने वायदा किया था कि वह वस स्टैन्ड 31 मार्च तक बन जायेगा लेकिन सरकार ने साल नहीं बतलाया कि कौन से साल तक बन जायेगा । यह पता ही नहीं लग रहा है कि कौन से साल में 31 मार्च आयेगा जब वह बस स्टैन्ड बनेगा । उस बस स्टैन्ड की काफी अहमियत है । जब वह बस स्टैन्ड बना था उस समय अम्बाला कैन्ट की 20–25 हजार की आबादी थी लेकिन अब वहां पर डेढ़ लाख की आबादी हो गई है । हरियाणा में वह सब से पुराना बस स्टैन्ट है। जब हिमाचल, हरियाणा और पंजाब एक थे उस समय वह बस स्टैन्ड नम्बर एक पर बना था । कमाई के लिहाज से भी अच्छा बस स्टैन्ड है लेकिन फिर भी उसे क्यों नहीं बनाया जा रहा है यह बात समझ में नहीं आती बै । जब किसी बस स्टैन्ड का ठेका नीलाम किया जाता है तो तीन तीन और चार चार लाख रुपए में जाता है लेकिन वहां जो छोले भटूरे का रेट लिखा होता है वह कुछ और होता है और पैसे देते समय कुछ और होता है । रेट एक रुपया लिखा होता है लेकिन जब आदमी भटूरे खा लेता है तो दस रुपये मांग लेते हैं । इसलिये मेरी अर्ज है कि वहां पर स्पैशल तौर पर रेट अवश्य लिखा होना चाहिए । कभी कभी

सरकार की तरफ से भी चौकिंग होनी चाहिए । जब पी ० ए० सी ० चौक करने जाती है तो नया रेट लिखा होता है लेकिन दूसरे ही दिन उस रेट को उतार देते हैं । वहां पर कोई रेट लिस्ट नहीं होती' है और जो उनकी' मर्जी में आता है, वह चार्ज करते हैं । मेरा कहना यह है कि डिपार्टमैंट को इसका चौकिंग करनी चाहिये कि जो रेट गवर्नमैंट मुकरर्र करनी है, उसके मुताविक लोगों को सामान मित्रता भी है या नहीं । इनके अलावा वहां पर नकली सौदा बेचा जाता है । वहां फर 12 आने के सामान को बसों मे चढ़ कर 3 रुपये में बेचा जाता है । मेरा कहना यह है कि बसों में चढ़कर सामान बेचने की इजाजत नही होनी चाहिये । सारी जगहों पर चाहे वह अम्बाला कैन्ट हो या पानीपत हो, लोगॉ को दुकानों के अन्दर तो ये लोग जाने ही नहा देते जहां पर माल भी अच्छा मिलता है और सही भी मिलता है और रेट भी ठीक है । जिस आदमी ने 2,000 रुपये महीने का ठेका ले रखा है, वह इस तरह का कोई न कोई तो हिसाब किताब जरूर करेगा । खाने–पीने की, रोटी के।, चाय की और समोसे वगैरा की कोई न कोई ऐसी दुकान वहां पर जरुर होने। चाहिए जहां पर गरीब आदमी कुछ खा पी सके । इतना ही कहकर मैं हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न० 4 ) बिल कीं ताईद करते हुए अपना स्थन लेता हूं ।

**चौधरी लीला कृष्ण (फतेहाबाद ) :** डिप्टी स्पीकर साहब, बोलने के लिये मुझे समय देने हेतु आपका धन्यवाद । मैं हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न० 4 ) बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं

। मैं केवल 2– 4 मिनट का ही समय लूंगा सबसे पहले मैं रैवेन्यू की मद को लूंगा । हम ही नहीं सारा हरियाणा मुख्य मन्डी जी का इस बात के लिये मशकूर है कि उन्होंने लैन्ड टैक्स माफ किया और पक्के खालॉ का खर्चा माफ किया । इसके अलावा ओलों की वजह से जो नुक्सान हुआ था, उसको पूरा करने के लिये भी मुआवजा देने की घोषणा की गयी है । इस वारे में मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं । जब नमें की फसल को कीड़ा लग जाता है तव उस पर जहाज से स्प्रे होता है । सरकार ने लैन्ड टैक्स माफ करके किसानों को बहुत वड़ी राहत दी है । लेकिन एक छोटी सी बात शायद सरकार के नोटिस में आनी रह गयी णै । अगर फसल का लैड टैक्स माफ कर दिया है तो यह स्प्रे के ड्यूज आफ एरियर भी माफ कर दिए जाएं । ये बाकी रह गये हैं । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जब आप माफी दे ही रहे हो तो, सरकार इस बात पर भी विचार करे कि जो स्प्रे के एरियर बकाया हैं उनको भी माफ कर दिया जाये । किसानों कौ लैड टैक्स की जो छूट दी गयी है, चाहे वह व्यापारी है या, दुकानदार है, सब की इससे तसल्ली हुई है । यह एक बहुत अच्छा कदम है । इससे बहुत राहत व्यापारियों को भी मिली है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं बिल्डिग्ज एण्ड रोड्ज की बाबत कहना चाहता हू । हमारे यहां पर सड़कों का बहुत वड़ा जाल बिछाया गया है । तरह–तरह की अच्छी बिल्डिग्ज और कालोनीज हुड्डा ने बनायी हैं । हमारे पी ० डब्ल्यू० डी० विभाग के

मंत्री जीं यहां पर बैठे हैं । मेरे हल्के में केवल नाम मात दो सड़कें एक–एक किलोमीटर की हैं जिन्हें मेहरवानी करके जल्दी बनवा दें । एक तो कुलाल की और दूसरी बेडी खेड़ा गांव की है । मैं मंत्री जी के सामने भी। कई बार पेश हो चूका है । मेरे ख्याल में उन सड़कों पर काफी काम हो गया है । थोड़ा सा ही बाकी रह गया है यानी हाथी निकल गया और पूंछ रह गयी वाली बात है । यह नहीं रहनी चाहिये । मेरी रिक्वैस्ट है कि पर्सनल अटैशन देकर उन सड्कों को बनवायें । मेरे ख्याल में ये सड़कें पिछले तीन साल से पैडिंग पड़ी हैं । इसी तरह से हुड्डा के मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं । स्टेट मे हर जगह हुड्डा कालोनीज बनाता है । पता नहीं फतेहाबाद की किस्मत ठीक नही या कोई और कारण है, वहा पर कोई कालोनी नहीं बनाई गया है । सेठ साहब बैठे हैं । मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि वहां पर भी एक कालोनी जरूर बनवायें । फतेहाबाद का भी हक बनता है क्योंकि वह सब डिवीजन है और बहुत बड़ा टाउन है । मेरा कहना यह है कि वहां की जरूरत के मुताविक हुड्डा की एक कालोनी बनाने के लिये जरूर विचार करें । स्पीकर साहब, अर्बन डिवैल्पमैंट के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा । मुख्य मंत्री जी ने अब कमेटीज के लिये बहुत पैसा दिया है । फतेहाबाद में तकरीबन 30 साल से माडल टाउन बना हुआ है । उस माडल टाउन कीं सड्कों की हालत विशेष तौर पर बहुत बुरी है । कोई व्हीकल तो क्या वहां से कोई रिक्शा वाला भी नहीं गुजर सकता । सरकार से मेरा अनुरोध है कि फतेहाबाद माडल टाउन की सड्कों के लिये अलग

से अनुदान दिया जाये, 2 लाख रुपये से काम चल जायेगा । मैं आशा करूंगा कि फतेहाबाद का माडल टाउन अवश्य ही ठीक होगा ।

'इसके बाद मैं लेबर एण्ड एम्पलायमैंट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । अन– एम्पलायमैंट की समस्या बहुत बड़ी है । आज बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने मुंह बाये खड़ी है । यूथ बेचौन हो रहा है । इस समस्या को हल करने के लिये सबसे पहली प्रायरिटी दी जानी चाहिये । अन–एम्पलायमैंट दूर करने के लिये सरकार ने एक स्कीम चला रखा है । यह ठीक बात है कि उसके तहत 20–20 या 25–25 हजार रुपये कर्जे के रूप में देते हैं । में यह गत कहे बगैर नहीं रहूंगा इस अमाउन्ट का मिसयूज हो रहा है । एक यूथ को अगर 20,000 रुपया अपना कोई काम धन्धा चलाने के लिए कर्जा. दे भी दिया जाये तो उससे कुछ नहीं होता । कई बार कर्जा देकर महकमा फिर यह नहीं पूछता कि वह 20,000 रुपया कहां गया । उस पैसे से कोई इंडस्ट्री सेट–अप हुई शै या नहीं । किसी की शादी वगैरा पर तो खर्च नहीं हो गया है । मै यह बात कहूंगा कि यूथ को ऐब्जौर्ब करने के लिये ऐसी–ऐसी स्कीमज बनाई जायें ताकि उनको रोजगार जल्दी मिल सके । मेरे ख्याल में बेरोजगारी की एक बड़ी भारी समस्या है जो हरेक एम० एल० ए० को सताती है । जव हम घर जाते हैं तो बीसियों लोग हमारे घर पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लड़के को

नौकरी दो, हमारे बेटे को नौकरी दो या हमारी बेटी को नौकरी दो । हम क्या जवाब दें? हम तो यह कहते हैं कि आप इन्टरव्यू दोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे । इस समस्या का कोई न कोई समाधान होना चाहिये । नौजवान जब काम में लगेंगे तो उनके दिमाग गलत बातों से हटेंगे। यह जो अन–ऐम्पलायमैट का मसला है, यह बहुत इम्पौटैंट मसला है । सरकार को इस मसले को टौप प्रायरिटी देकर हल करना चाहिये । डिप्टी स्पीकर साहव. इसको वार–फुटिग पर हल किया जाना चाहिये ।

इसके अलावा ऐग्रीकल्चर के मामले मे भी बड़ी तरक्की की जा रही है । ट्यूबवैल्ज को बिजली के कनैक्शन्ज दिये जा रहे हैं । मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि फतेहाबाद और रतिया के एरियाज को पैडी एरिया डिक्लेयर किया गया था, मे त् ख्याल से इस बात को हुए दो साल हो गये हैं । जब हम यह कहते है कि हमें प्रायरिटी पर पानी दिया जाये और दूसरा सहूलियातें दी जायें तो हमें यह जवाब मिलता है कि हम इसकी पालिसी बना रहे हैं । सरकार ने एक बार एक चीज डिक्लेयर कर दी है तो उसके लिये पालिसी बनाने में इतना ज्यादा टाईम लगे, यह अच्छी बात नहीं है । मैं आशा करता हूं कि वह पालिसी जल्दी बनाएंगे ताकि लोगों को सहूलियतें मिल सकें । वह धान का एरिया है । हम इस अनाउसमैंट का पूरा फायदा होते हुए देखेंगे । मैं एक बार फिर यह आशा करूंगा कि इस बारे में पालिसी या रूल्ज जल्दी बनाये जायें । मैं यह कहने से भी गुरेज नहीं करूंगा कि ' फतेहाबाद में

कोई भी टूरिस्ट कम्पलैक्स नहीं है । वह एक सब–डिवीजन है । कई सालों से मैं कह रहा हूं कि वहां पर एक ट्रिस्ट कम्पलैक्स बनाया जाये लेकिन अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है । यह बहुत बड़ा सेंट्रल प्लेस है । चण्डीगढ मे, पंजाब से, दिल्ली से और राजस्थान से आने–जाने वालों के लिये तुक सेंट्रल प्लेस पड़ता है । वहां पर अगर कोई टूरिस्ट कम्पलैक्स न हो तो यह हमारे लिये बड़ी शर्म की बात है । मैं आपके द्वारा सरकार से यी कहूंगा कि वहां पर प्रायरिटी बेस पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाया जाना चाहिये । इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है । ये यूथस को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिससे उनको ऐम्पलायमैंट मिलता है । फतेहाबाद मे कोई आई० टो ० आई ० नही है । पता नहीं उधर इनकी नजर क्यों नहीं गयी? वहां पर आई० टी ० आई० का होना वहुत जरूरी है । पिछले सैशन में चीफ मिनिस्टर साहब वहां के लिये आई ० टी ० आर्ड ० की अनाउसमैंट कर चुके हैं । वहां पर जगह पड़ी हुई है । हमारे पास ओल्ड तहसील की जगह है फिलहाल हम इसको वहां पर खोल सकते हैं । जव तक इसके लिये कोई जमीन ऐक्वायर नहीं होती, तब तक हम इसे वहां पर खोल सकते हैं. । इसके बाद मैं यह कहूंगा कि हरियाणा की चहूमुखी तरक्की हुई है । व्हाईट रैवोल्यूशन ग्रीन रैवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रैवोल्यूशन हमारी स्टेट में आया है । इतना ही कहकर मैं इस बिल का अनुमोदन करते हुए अपना स्थान लेता हू ।

**बहिन शान्ति देवी (करनाल ) :** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस ऐप्रोप्रिएशन (न० 4 ) बिल का समर्थन करते हुत कुछ शब्द इसके बारे में कहूंगी जिनका सम्बन्ध विशेषतः करनाल से है । सबसे पहली मांग गृह की है । वहां पर पुलिस का प्रबन्ध ठीक है, लेकिन एक बात मैं पुलिस थानों के बारे में कहना चाहूंगी । इस बारे में लोगों से अकसर शिकायतें आती रहती हैं कि अगर कोई आदमी वहां पर एफ० आई० आर० दर्ज कराने या किसी और किस्म का काम करवाने जाते है तो उनसे 20—30 रुपए कागज कार्बन पेपर आदि के मांगे जातै हैं । मेंरा नम्र निवेदन यह है कि कम से कम हर पुलिस थाने में काफी तादाद मैं कागज—कार्बन जरूर मुहैया करवाये जायें ताकि लोग परेशान न हों और न ही यह रिश्वत का मामला बने । सभी पुलिस थानों में कागजों की कोई कमी नही रहने देनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने भवन तथा सड्कों के बारे मे कुछ न कुछ कहा है । मैं भी एक सड़क के लिए निवेदन करना चाहती हूं । करनाल में मधुबन कम्पलैक्स के पीछे पूर्बियों की गामड़ी सिरसी को वजीदा जाटान लिक रोड से दाह जगीर के स्थान पर मिला दिया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे— में मैंने आज सी० एम० साहब से भी निवेदन किया कुए और पी० डब्लू ० डी ० मिनिस्टर साहब से भी निवेदन किया है कि यह सड़क बननी बहुत जरूरी है । पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने बहुत काम किए हैं और कई आश्वासन दिए हैं इस गांव

में जो लोग बसते हैं वे भी पिछड़ी जाति के हैं इसलिए इस सड़क को बनाकर उन लोगों को भी पक्की सड़क पर चलने की सुविधा प्रदान की जाए । इस समय उन लोगों को मधुबन कम्पलैक्स से गुजर कर आना–जाना पड़ता है । कई बार वहां पर पुलिस वाले खड़े रख्ते हैं और वे उनको रोक लेने हैं । कभी जाने देते हैं कभी नहीं जाने देते ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं चिकित्सा के बारे में कहना चाहती हूं । मनुष्य जीवन के लिए चिकित्सा बहुत जरूरी है और उसके लिए अच्छी दवा दारू का इन्तजाम होना चाहिए । मैं करनाल के अस्पताल के बारे में नम्र निवेदन करना चाहती हू ताकि वहां के अस्पताल का ध्यान रहे । उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर डाक्टर्ज के क्वार्टर्ज तो बन गए हैं लेकिन अस्पताल का मुख्य भवन बनना बाकी. है । सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए । इसी तरह से पशु पालन के लिए पशु अस्पताल का होना बहुत जरूरी है । अच्छा दूध प्राप्त करने के लिए पशुओं का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है । आजकल एक पशु कई हजार रुपए का आता है और अगर वह बीमार हो जाए और उसके इलाज के लिए कोई प्रबन्ध न हो तो लोगों का काफी नुक्सान हो जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, करनाल के आसपास कई गांव जैसे मुसली और कलानपुरा है जिनमें जल्दी से जल्दी पशु अस्पताल बनाए जाने जरूरी हैं ।

उपाअध्यक्ष महोदय, जहां तक वनों का सम्बन्ध है, काफी वृक्ष लगाए जा रहे है । पहले तो सफेदे के वृक्ष लगाए जाते थे लेकिन अब कीकर के वृक्ष भी लगाते हैं । मैं चाहती हूं कि सड़कों के साथ साथ बोगन बिलिया भी लगने चाहिएं ताकि सड्कों की शोभा बढ़े और उन पर चलने वाले लोगों को वे अच्छे लगे और हरियाणा की शान और सुन्दरता बढ़े । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर परिवहन के बारे में भी जिक्र आया ई उपाध्यक्ष महोदय, करनाल का जो सामान्य बस स्टैण्ड है 'उसके सामने की जो दीवार है उसके बाहर को द्रव्य अच्छा नहीं लगता । उसका गैट–अप अच्छा लगे इसके लिए भी वहां कुछ पैसा दिया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेती हुं ।

**श्री नेकी राम (रतिया, अनुष्चित जाति )** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं ऐप्रोप्रिएशन बिल (नम्बर 4 ) के बारे में बोलना चाहता हू । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का रतिया है और वह चूकि पंजाब के साथ लगता है इसलिए वहां पर सड्कों का होना जरूरी है । वहां पर कोई सड़क दो किलोमीटर की हैं और कोई डेढ किलोमीटर की है । इस तरह से कुल मिलाकर पचास किलोमीटर की सड़कें हैं जो बननी है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में चावल पैदा होता है । पंजाब मै चावल का रेट ज्यादा दिया जाता है और हरियाणा में कम दिया जाता है । इसलिए वे लोग अपना चावल पंजाब में ले जाते है । यही कारण है कि वहां

के लोगों की माग है कि वहां पर सड़कें बनाई जाए जिससे कि उनको अपनी उपज मंडी में ले जाने मैं दिक्कत न हो । अगर पंजाब में और हरियाणा में एक ही रेट हों तब तो कोई बात नहीं है लेकिन पंजाब में ज्यादा रेट मिलता है । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर सड़कें बनाई जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में घग्गर नदी वहती है । वहां नदियो के ऊपर पुल है लेकिन ड्रेन के ऊपर पुत्र नहीं है । मेरे यहां एक गांव है तेलवाड़ा। तेलवाडा से रतिया जाने के लिए रास्ता जाता है लेकिन वहा पर कोई पुल नहीं है । गांव ऐसे हैं जहा पर नदियों की वजह से रास्ता बंद हो गया है क्योंकि वहां पर पुल नही हैं । इसलिए वहा पर कम से कम दो पुल अवश्य बनाए जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूध ज्यादा पैदा करने के लिए सरकार ने वहुत अच्छे कदम उठाए हैं । सरकार पशु खरीदने के लिए लोगों को कर्जा भी देती है और दूसरी तरह की इमदाद भी देती है लेकिन पशुओं को जो बीमारी होती है उसका इलाज करने के लिए डाक्टर्ज उप–लब्ध नही होते और अगर हैं तो उनके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने हल्के का दौरा करके अस्पतालों की लिस्ट बनाकर सरकार को भेजी' थी पता नहीं उसका क्या हो रहा है । मेरी प्रार्थना है कि मच्छी महोदय उस पर रोशनी डालें कि कितने अस्पताल वहां देने हैं । इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, वहा पर पब्लिक के लिए

अस्पताल की मांग है, स्कूलों की मांग है और स्कूलों को अपग्रेड करने की माग है । इन सब बातों के बारे में मैने लिखकर भेज दिया हैं लेकिन अभी तक जवाब नही आया है कि उनके बारे में क्या हो रहा है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, रतिया राक कोने में लगता है इसलिए वहा पर बस स्टैण्ड की मांग है । वहा पर सब्जी मार्किट तथा रिक्शा स्टैण्ड की माग है । सरकार ने एलान नहीं किया हैं कि इन मागों को कब तक पूरा कर दिया जाएगा । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में तीन चार जगह ऐसी है जहां टीचर नहीं हैं । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहा पर टीचर्ज भेजे जाए । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मदन से प्रार्थना करता हूं कि इस बिले को पाम कर दिया जाए ।

**वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर ) :** उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें पहले सदन में कही जा चुकी हैं ज्यादातर तो वही बातें दोहराई गई हैं और वे अपने निजी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं । उनको नोट कर लिया गया है और उन पर उचित कार्यवाही करने के लिए विचार किया जाएगा । जो जनरल बातें हैं और सब से सम्बन्धित हैं उनका मैं जवाब देना चाहूंगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात कुरुक्षेत्र में लगने वाले सूर्य ग्रहण मेले के बारे में भी कही गयी है कि वहां पर यात्रियों की सुविधाओं के लिये हर प्रकार का बन्दों– बस्त करना चाहिये ।

इसके लिये मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पहले से ही सरकार इसके लिये जागरूक है और सरकार की ओर से कुरूक्षेत्र डिवैल्पमैन्ट बोर्ड को चालू साल में जो नार्मल ग्रांट दी जाती है उसमें वृद्धि की गयी है । डिवैल्पमैन्ट बोर्ड, कुरूक्षेत्र की जमीन खरीदने की, ऐकवायर करने की जो लायबिलिटी थी, उसकी अब सरकार ने अदायगी की है । सरकार ने स्पैशल ग्रान्ट के तौर पर 50 लाख रुपया और दिया है (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए । ) स्पीकर साहब, सरोवरों की डिवैल्पमैन्ट का काम काफी जोरशोर से शुरू है । खासतौर से ब्रह्मसरोवर का काम शुरू है और उसे और सुन्दर वनाया जा रहा है । स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र शहर में ब्रह्मसरोवर नाम से एक बहुत सुन्दर सरोवर बना हुआ है जिस पर एक साथ लाखो आदमी स्नान कर सकते है और तहां पर ठहर भी सकते हैं । अब उसके बराबर का दूसरा हिस्सा भी डिवैल्प किया जा रहा है । सूर्य ग्रहण तक तो सारा काम मुकम्मल होना मुश्किल हए लेकिन स्टेयर्ज तक का दूसरे हिस्से का भाग पूरा होने की पूरी संभावना है । सरकार ने डिवैल्पमैन्ट बोर्ड को इस बात की औफर भी की है कि अगर वे सारा काम सितम्बर तक कर सकते हैं तो इसके लिये सरकार की ओर से और पैसा भी दिया जा सकता है । इसी तरह से इसके साथ वाले और सरोवर थीं जो पहले कच्चे थे, उनको भी अब तेजी के साथ डिवैल्प किया जा रहा है । वहां स्टाफ भी बढाया जा रहा है । बोर्ड को यह कहा गया है कि जितना ज्यादा काम कर सको उतना ही ज्यादा पैसा आपको दिया जाएगा । इसी तरह से स्पीकर

साहब, जो स्नेहीत सरोवर है, उसको भी और सुन्दर कर रहे है, रैनोवेट कर रहे हैं गहरा कर रहे हैं और? अच्छा बना रहे हैं । उसके लिये भी सरकार ने कहा है कि जितने पैसे की आवश्यकता होगी, दिया जाएगा । इसके अलावा कुरूक्षेत्र के आस–पास का जो इलाका है, रोडज हैं, धार्मिक नगर हैं, उनको भी बोर्ड के माध्यम से डिवैल्प करने के लिये बोर्ड को पै सा दे रहे हैं । सडकें बनायी जा रही हैं, पौन्डज की– दीवारें बनाये। जा रही हैं औंर उनको रैनोवेट किया जा रहा है ।

स्पीकर साहब, यहां कोर्टस के अन्दर वकीलों के बैठने की व्यवस्था करने के बारे में भी जिक्र आया कि वकीलों के लिये कोर्टस के बाहर कोई प्रोपर जगह नहीं है जहां पर वे बैठ सकें । वे लोग छोटे मोटे छप्पर वगैरह डाल कर वहां बैठते है जिससे कोर्टस की आउट–लुक खराब होती है । इस समय बहुत थोड़े चौम्बर वकीलों के लिये वने हुए हैं, लेकिन सरकार इममें विचार कर रही है कि इस मामले में और मदद दी जा सके और सुन्दर तरीके से और चौम्बर बनाये जा सके । यह मामला सरकार के विचाराधीन है । इससे अगली बात यह कही गयी कि हरियाणा के अन्दर एक दो जिलों को छोड़कर सभी जिलों में हेल स्टौर्मज से नुकसान हुआ है । जो यार्ड स्टिक है, जो पैमाना है वह यह है कि जिस गांव में 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ हो वे ही रिलीफ के हकदार हों । उन्होंने चाहा है कि अगर किसी इडीविजुअल, कें एक खेत का भी नुकसान हुआ है,

तो उसको भी रिलीफ देने का प्रावधान होना चाहिए । मैं इस बात से सहमत हू और सरकार की यह नीति भी है कि एक गांव में चाहे कितने ही परसैन्ट का नुकसान हो वहां पर एक आदमी के नुकसान को भी देखा जाए और उसी प्रतिशत की मात्रा में, जिस हिसाब से उसका नुकसान हुआ होगा, उसे उसी हिसाब से रिलीफ दी जाएगी । एक बात स्कूलों के भवनों, कालेजों एवं हस्पतालों के भवनों के बारे में कही गयी । साथ में वैटरिनरी हस्पतालों का भी जिक्र आया कि इन के लिये भी पैसा रखा जाए । स्पीकर साहब, रिपेयर औफ रोडज और नई सड्कों के लिये सरकार कीं जो पालीसीज हैं उन के बारे में यहां हाउस में कई बार बताया गया है । सरकार की सारी नीति सदन के सामने रखी गया है । इन सब के बारे में एक बात यहां हाउस में बताना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्यों की ओर से अपने अपने हल्कों के बारे में बार–भू बातें आई हैं कि हमारे प्रदेश में भवनों पर बहुत कम पैसा खर्च किया जा रहा है । इसका कारण यह है कि हम अपने दूसरे इम्पौटैंट प्रोजैक्ट्स जैसे बिजली, इरीगेशन, जिस में एस० वाई० एल० भी शामिल है, पर काम चरन रहे हैं और उन पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं । उन पर जो साधन हमें जुटाने पड़ते हैं, उसके लिये दूसरी तरफ से हम पैसा बचाकर इधर लगाते हैं । यह बात सदस्यों की सही है कि प्रदेश में सरकार बिल्डिगों, जैसे पुलिस स्टेशनों की बिल्डिगें हैं, उनकी बुरी हालत है, स्कूलों और कालेजों की बिल्डिगों का भी बुरा हाल है, केवल अपने दूसरे प्रोजैक्ट्स पर पैसा खर्च करने के कारण हम इस तरफ ध्यान नहीं

दे पा रहे है । जो हमारी बिजली और पानी की योजनाएं हैं, वे तकरीबन पूरी होने जा रही है । वैसे एस० वाई० एल० का सारा खर्चा केन्द्र सरकार ही वहन कर रही है । बिजली के दो बडे प्रोजैक्ट्स पूरे हो गये हैं । तीसरा 210 मैगावाट का प्रोजैक्ट पूरा होने जा रहा है । वह की अगरने सारन में पूरा हो जाएगा । जो यमुना नहर की माइक्रो–हाईडल स्कीम्ज थीं वे भी पूरी होने जा रही हैं । उम्मीद है कि हम कुछ पैसा बचा भी पाएंगे । अब पिछले साल से थोड़ा थोड़ा पैसा दूसरे कामों के लिये देना आरम्भ कर दिया है । अभी' शिक्षा मन्त्री महोदया ने बताया था कि हम स्कूलों को लिये हर साल दो चार करोड़ रुपया रखते हैं । इसके अलावा, दूसरे जो सोर्स हैं जैसे एन० आर० ई० पी. ० और आर० एन० ई० जी ० पी ० या डिसैन्टेरलाईजड योजनाओं के तहत और मैचिंग ग्रान्टस के द्वारा सरकार काफी पैसा जुटाती है । जो दूसरी छोटी छोटी योजनाएं है, उनको हम पैसा दे भी रहे हैं लेकिन भविष्य में और दूसरे कामों के लिये पैसा बचाया भी. जाएगा ।

स्पीकर साहब, सरकार की एक जनरल पालिसी की बात भी यहां पर कही गयी कि शराब बन्दी की जानी चाहिये और जहां पर पंचायतें कोई प्रस्ताव पास करते।– हैं कि फलां जगह वैन्डज न खोले जाएं, तो वहां नहीं खोले जाने चाहियें । इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई पंचायत सितम्बर के अन्दर कोई प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजती है तो उसको अवश्य

कंसिडर किधा जाल है और इस के लिये' दौ तीन महीने की अवधि जांच पड़ताल करने के लिये लग जाती है । मार्च के महीने में वैन्डज की औक्शन होती है । इसकी वजह यह है कि यह देखा जाए कि कहीं गांव वालों ने जो रैजोल्यूशन दिया है, वह सही है या किसी और भावना से तो नहीं दिया । कई जगह दूर द्र के जो ठेकेदार होते हैं वे आस पास की पंचायतों से मिलकर के ऐसा रैजोल्यूशन भिजवा देते हैं ताकि वे ही अकेले उस इलाके में शराब सप्लाई करते रहें । डसके अलावा नाजायज शराब का धन्धा करने वाले भी पंचायत। से मिल कर इस तरह की डिमांडज भिजवा देते हैं ताकि उनका धन्धा चलता रहे । सालवन गांव का एक बार प्रस्ताव आया था और उसकी जांच करवायी गयी थी । जांच के बाद यह पाया गया कि वहां पर ऐक्साईज के 40 केसिज चल रहे हैं और सारे गांव में नाजायज शराब बिकती है और बनती है । उस गांव की पंचायत की ओर से प्रस्ताव आया कि यहां पर जो। वैन्ड खोला गया है, उसको बन्द कर दिया जाए । केवल इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए दो तीन महीने पंचायतों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए और जांच पड़ताल करनें के लिए समय रखा जाता है ताकि कही कोई गल्त आदमी मिल मिला कर ऐसा काम न करवा ले । जहां पर पंचायतों का प्रस्ताव ठीक लगे, पंचायतें सिनसीयर हों, वहां पर हम ठेकों को बन्द कर देते हैं । इसी तरह से टूरिजम की वात भी आयी कि टूरिस्ट कम्पलैक्सिज में तो सरकार ने वारज चला रखी हैं. लेकिन प्राईवेट लोगों के लाईसैन्स कैन्सिल कर दिये हैं । उनकी यह बात सही है । साथ

में यह बात भी कही गयी कि प्राईवेट लोगों के साथ साथ टूरिस्टस कम्पलैक्सिज में जो बारज खोली जाती हैं, वे भी बन्द की जाएं । मैं यह कहूंगा कि जब लोग पब्लिक प्लेसिज पर पीएंगे तो वहां पर शोर शराबा ज्यादा होगा लेकिन जो हमारे टूरिज्म कम्पलैक्सिज में बारज है, वहां वे अन्दर बैठ कर पीएंगे और वहां पर सरकार का उनके ऊपर कुछ न कुछ नियन्त्रण भी रहेगा इसलिये जो लोग पीये बगैर नहीं रह सकते केवल उन्ही के लिये टूरिस्टस कम्पलैक्सिज में इस तरह की व्यवस्था रखी गयी है ।. कहीं यह न हो कि लोग मजबूर होकर अपना दूसरा धन्धा न करने लग जाएं ।

स्पीकर साहब, म्युनिसिपल कमेटीज में पार्ट टाईम सफाई कर्मचारियों की बात यहां पर कही गयीं कि उनका पूरे वेतन नहीं मिलते पार्ट टाईम रखे जाते हैं और स्वीपर्ज की वही पुरानी गिनती आबादी के हिसाव से है जवकि आबादी बढ़ गयी है और कर्मचारियों की संख्या उतनी की उतनी ही है । साथ ही यह भी बताया कि कमेटियों का खर्चा बढ गया है । यह बात ठीक है कि बची बढ़ गया है । मैं इस बारे में जानकारी देना चाहता हू कि सर्कार ने हर साल कमेटियों की मदद की है । स्पैशल ग्रांट थीं दी है और इस साल उनकी ग्रांट दोगुनी की गई है । हमने करीब दो करोड़ रुपए की स्पैशल ग्रांट दी है । हमने डिसैट्रेलाइजेशन औफ प्लानिंग में भी 1 करोड़ 10 लाख तपत शहरों के लिए रखे हैं ताकि वहां पर सफाई वगैरह का ज्यादा कार्य हो सके । जो

लोकल बौडीज एल० आई० सी ० वगैरह का लोन नही दे पा रही थी वह भी सरकार ने दिया है । अभी भी देखा जा रहा है कि जहां जहां जरुरत है वहां इंडीविजुअल कमेटी की मदद कर रहे हैं । तो सरकार इस बारे में पूरा ध्यान रखती है । इनके अलावा यहां पर जो इंडीविजुअल बातें कही गई है, वे चाहे दोहराई गई है या नई बातें कही गई हैं उन सव का ध्यान रखा जाएगा । धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** पश्न है–

That the Haryana Appropriation (No.4) Bill be taken into consideration at once.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अव सदन बिल पर क्लाज वार्ड क्लाज विचार करेगा ।

**क्लाज 2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 3**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 3 किन का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**शड्यूल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

कि शड्यूल बिल का शड्यूल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**अनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न हैं–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनौइक्टंग फार्मूला हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**टाइटल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**Finance Minister** (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir, move—

That the Bill be passed.

**श्री अध्यक्ष :** अब मन्त्री जी मूव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ–

कि बिल पास किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(3) दि पंजाब ऐन्टरटेनमैंटस डियूटी (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलिडेशन) बिल, 1987**

**श्री अध्यक्ष :** अब ऐक्साइज एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर दि पंजाब ऐंटरटेनमैंटस डियूटी ( हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन )

बिल. 1987 को इन्टोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I introduce the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1987.

I also move—

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ–

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

**सब क्लाज ( 2 ) आफ क्लाज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि सब क्लाज ( 2 ) आफ क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 3**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 4**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

## सब क्लाज ( 1 ) आफ क्लाज 1

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि सब क्लाज ( 1 ) आफ क्लाज 1 बिल का पार्ट वने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

## अनैक्टिंग फार्मूला

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न हैं–

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

## टाइटल

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I move—

That the Bill be passed.

**श्री अध्यक्ष :** अब मन्त्री जी मूव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ–

कि बिल पास किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(4) दि पंजाब बैकवर्ड क्लासिज (ग्रान्ट औफ लोन्ज) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1987**

**श्री अध्यक्ष :** अब मिनिस्टर औफ स्टेट फार सोशल वैलफेयर दि पंजाब बैकवर्ड. क्लासिज (ग्रांट औफ लोन्ज ) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1987 को इन्ट्रोडयूस करेंगी तथा उसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगी ।

**Minister of State for Social Welfare** (Smt. Kartar Devi) : Sir, I introduce the Punjab Backward Classes (Grant of Loans) Haryana Amendment Bill, 1987. I also move—

That the Punjab Backward Classes (Grant of Loans) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ––

That the Punjab Backward Classes (Grant of Loans) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

That the Punjab Backward Classes (Grant of Loans) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब मदन बिल पर क्लाज वार्ड क्लाज विचार करेगा ।

**क्लाज 2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लोज 2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 4**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

## क्लाज 1

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

## अनैक्टिंग फार्मूला

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि अनैक्टिंग फर्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

## टाइटल

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब मन्त्री जी मूव करेगी कि बिल पास किया जाए ।

**Minister of State for Social Welfare** (Smt. Kartar Devi) : Sir, I move—

That the Bill be passed.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ–

कि बिल पास किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(5) दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1987**

**(6) दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1987**

**श्री अध्यक्ष :** अब डिवैल्पमैंट मिनिस्टर दि पंजाब ग्राम पंचायत ( हरियाणा अमैंडमैंट ) बिल, 1987 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

**विकास मंत्री (कर्नल राव राम सिंह ) :** स्पीकर साहब, इससे अगला बिल भी इसी तरह का है । अगर आपकी इजाजत हो तो दोनों बिल्ज इकट्ठे इन्ट्रोडयूस और मूव कर दिए जाएं ताकि दोनों पर एक साथ डिस्कशन हो सके । वोटिंग भले ही दोनों पर अलग अलग करवा ली जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है ।

**Development Minister** (Col. Rao Ram Singh) : Sir, I

beg to introduce the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1987.

Sir, I also beg to introduce the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill, 1987.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryna Amendment) Bill be taken into consideration at once.

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ––

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryarna Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिह सुरजेवाला ) :** स्पीकर साहब, ये जो दो बित पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट ) और पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट ) हैं, इन पर मैं बोलना चाहूंगा । इन दोनों बिलों का मुद्दा यही है कि जो बैकवर्ड क्लासिज के भाई है जिनकी गिनती बहुत सी जगह इतनी नहीं है कि वे अपने साथियों की वोटे लेकर पंचायत समिति के अन्दर या ग्राम पंचायत में उन लोगों का रिप्रैचौन्टेशन कर सकें । इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये दोनों बिल लाये गए हैं । पानीपत मैं प्रान्त के स्तर के बैकवर्ड

क्लासिज के लोगों का एक सम्मेलन सम्बोधित करते हुए मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों को भी आम पंचायतों में और पंचायत समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा । मौजूदा ऐक्ट में सिर्फ महिलाओं के लिए और हरिजनों के लिए ही प्रावधान था कि जहां पर हरिजन या महिलाएं चुनकर नहीं आएगी वहां पर इनको प्रतिनिधत्व दिया जायेगा । जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने पानीपत में की थीं उसी को क्रियान्वित करने के लिए डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट ये दोनों बिल लेकर आया है । इस बिल के लाने की सरकार की बड़ी साफ मन्शा है । इस बिल के जरिए उन लोगों को नुंमाइंदगी देना है जिन्होंने न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के निर्माण में बहुत भारी योगदान दिया है और दे रहे हैं । चाहे इनकी बिरादरी अपने स्तर पर या गांव के स्तर पर बहुत ज्यादा नहीं है । बैकवर्ड क्लासिज के जिस सम्मेलन को मुख्य मंत्री महोदय ने सबोधित किया था उसको देख ने का मुझे भी अवसर मिला था । सम्मेलन अपने आप में एक बडा भारी सीन था । स्पीकर साहब, हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज के भाई जिन्होंने इस देश का या प्रान्त क ख निर्माण किया है ठे पानीपत–मे हजारों की तादाद मे आये थे । उस सम्मेलन मे सभी बैकवडे क्लामसज के भाई जिन्होंने इस देश/प्रदेश की सडकें बनाई हैं या इमारते खड़ा की है बड़े जोशो–खरोश के साथ आये थे । जिन तमन्नाओ के साथ वे आये थे उन्हीं तमन्नाओं के साथ यानी पूरे जजबात से संतुष्ट होकर वे वहां से गए थे । यह वह सीन था जिसमें गरीब आदमी आपस में कन्धे से कन्धा मिला कर चलता

हुआ दिखाई दे रहा था । ये भाई पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से गये थे । स्पीकर साहब, आपको भी पता है कि पानीपत करनाल जिले का सबडिवीजन है । एक तो चन्द रोज पहले हमारा वहां पर सम्मेलन हुआ था और दूसरा पानीपत के पास एक गांव में अपोजीशन पार्टी के भाइयों ने भी एक हमारे जैसा ही सम्मेलन किया था । उनके सम्मेलन में क्या नजारा था, वहां पर क्या सीन था उसकी खवर इण्डियन ऐक्सप्रैस में छपी है । शायद वह खबर आपने भी और माननीय सदस्यों ने भी पढ़ी होगी । जो खबर उनके बारे में अखबार में छपी थी उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूगा । स्पीकर साहब, किम प्रकार से हमारे यहा प्रान्त के अन्दर ऐसे तत्व हैं या ऐसे लोग हैं या ऐसी ताकत समझें जो इस बात को बर्दास्त नहीं कर सकती कि समाज का जो पहिया आगे चल रहा है वह निरंतर चलता रहे। उनकी यही कोशिश है कि किसी प्रकार से समाज के चलते हुए पहिये को उल्ट दिया जाये । वे किस प्रकार से आतंक फैलाकर, घृणा फैलाकर, झूठा प्रचार करके सारे वातावरण को दूषित करना चाहते हैं । आज ऐसे तत्वों से प्रान्त को और देश को पूरा खतरा है । ऐसे लोग पंजाव में जो आतंक फैला ने हैं उसका अंजाम पूरा देश भुगत चुका है थे ओर भुगत रहा है । यह बहुत ही संतोष की बात है कि पंजाव में जो वातावरण बनता जा रहा है पिछले महीने उसके खिलाफ वहां की जो साइलैट मैजोरिटी है उसने एक बार फिर पंजाब में शान्त वातावरण कायम करने के लिए जन सभाओं के द्वारा अपनी भावनाएं ऐक्सप्रैस करने की कोशिश की है ताकि देश के लिए जो

खतरा उग्र तत्वों द्वारा बनता जा रहा हे, उसको समाप्त किया जा सके । जिन लोगों द्वारा पंजाब में वातावरण दूषित किया जा रहा है उन्हीं के भाई यानी उनके समर्थक हरियाणा में भी वातावरण दूषित करने की कोशिश में है । स्पीकर साहब, मैं उस सम्मेलन का जिक्र कर रहा था जिसको हमारे अपोजिशन के भाइयो ने संबोधित किया है । उस सम्मेलन में जो कुछ हुआ है, उसकी खबर इण्डियन ऐक्सप्रैस में छपी है । उसी खबर की मैं अब चर्चा करना चाहूंगा । मैरे कहने का मतलब यह है कि उस सम्मेलन मे जो कुछ इन्होंने किया है, उसको बड़ी गम्भीरता से देखना चाहिए । इस खबर का हेडिंग है "Militant note in Lok Dal Meetings". इसका मतलब यह है कि उस मीटिंग में उग्रवादिता का वातावरण था । उस मीटिग में जिन–जिन मुद्दे ओं पर चर्चा की गई उस बारे में भी मैं जिक्र करना चाहूंगा । इस सभा को चौधरी देवी लाल जी जो लोक दल के और सघर्ष समिति के लीडर हैं, ने संबोधित किया है । उस सम्मेलन में उनकी सरोपा पेश किया गया । पंजाब समझोते का विरोध किया गया और आनन्दपुर प्रस्ताव का विस्तार मे समर्थन किया गया । सरकारी अधिकारियों को सरकार के' आदेश न मानने की काल दी गए । किसानो को भी कर्जा और लैन्ड टैक्स न देने की कानून दो गई । वहां पर आग भडकाने गले भाषण और गाने गाये गये जिससे दर्शक उत्तेजक हो सके । लोक दल और अकाली दल के जलसे में बहुत नारी समानता थी जोकि इंडियन ऐक्सप्रेस में लिखी हुई है । इराडी जैसे ट्रिव्यूनल की जिनमें इस देश के बहुत हो ऊंचे स्तर के जजिन हैं उनकी

बुराई की गई । उस ट्रिब्यूनल मैं हरियाणा को बहुत उम्मीद है कि हमें इन्साफ मिलेगा लेंकिन उसके खिलाफ भी बहुत सी बातें कही गई जिससे उनकी मन्शा का पता चलता है कि वे हरियाणा के हितों के लिए कितने चिन्तित हैं । हरियाणा संघर्ष समिति ने अकली दत के युद्ध के काल की तरह मिलिटैन्ट कारन दी । उन्होंने जवानों को कुर्बानी देने के लिए आवाहन दिया । सरवत खालसा की तरह समस्त हरियाणा के जलसे अक्षों– नाइज किये गये और उनमें इस प्रकार की चर्चा की गई । उन्हेंने इलैक्शन पोस्टपोन– करने का भी प्रचार किया जिसमें रत्तीभर भी वजन नही है । इससे मिथ्या कोई और बात नही हो सकते।– । काग्रेस पार्टी और काग्रेंस सरकार इस बारे में तो कभी सोचती भी नही है कि ड्यू डेट के बाद इलैक्शन न हो । मैं आपके माध्यम सें यह वात कहना चाहता हूं कि जहां हमारी सरकार और भारत सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि इस प्रान्त मे भाईचारा, बराबरी का वातावरण हो वहां ये लोग दूसरी बातें कर रहे हैं । यह सरकार चाहती है कि हुस प्रान्त के गरीब और नाचे दबे हुए लोग जौ आर्थिक और सामाजिक तौर पर नाचे हैं, वे आगे बड़े । लेकिन दूसरी तरफ राजनैतिक– तौर पर वे तत्व और फोर्सिज मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि इस प्रान्त मे तरक्की।– न हो और वे यह भी नही चाहते कि इराडी ट्रिब्यूनल हरियाणा को पूरा हिस्सा दे । वे यह भी नहीं चाहते हैं कि हरियाणा में एस ० वाई ० एल ० नहर बचे चौधरी बंसी लाल की सरकार ने इस प्रकार का वातावरण माइन्योरिटी कम्युनिटीज, हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लिए बनाया है

ताकि वे सुख से रह सकें लेकिन हमारे अपोजिशन के भाई ऐसा नहीं चाहते हैं । अपोजिशन वाले नहीं चाहते हैं कि वे ठीक तरह से अपना निर्वाह कर सके । इस अच्छे वातावरण को वे भंग करना चाहते हैं वे यहां उपद्रव करना चाहते हैं और पंजाब जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं । इस बारे में सरकार का चिन्तित होना स्वाभाविक हैँ औंर हमें भी उस बारे में राजनैतिक तौर पर विचार करना चाहिए । इन शव्दों के साथ मैं हाउस से कहूंगा कि ये बहूत अच्छे बिल्ज है और इन्हें पास किया जाना चाहिए ।

**विकास मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) :** स्पीकर साहब, ये जो दो बिल पेश किये गये है, ये ग्राम पंचायत में और ब्लौक समिति में बैकवर्ड क्लासिज को रिप्रैजैन्टेशन देने के लिए पेश किये गये हैं । मुख्य मन्त्री' जी. ने पानीपत में पब्लिक मीटिंग में यह अनाउन्स किया था कि बैकवर्ड. क्लासिज को ब्लौक समिति और पंचायतों में रिप्रैजैन्टेमंन दी जाये क्योंकि शडयूल्ड कास्टस को तो यह आलरेडी अश्योरड है और बैकवर्ड क्लासिज को नहीं है । इस वजह से सरकार ने और मुख्य मन्डी जी ने विशेष रूप से यह फील किया कि बैकवर्ड क्लासिज इस विषय में कुछ नैगलेक्टिड हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए ताकि वे भी बाकी समाज के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चल सकें । उनको भी वही औनर और इज्जत दी जा सके जो दूसरे लोगों को प्राप्त है । स्पीकर साहब, जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है, उनकी स्टैरन्थ वेरी करती है । किसी भी गांव की पंचायत में कम से कम पांच

पंच और एक सरपंच होता है । कम से कम पांच और ज्यादा से ज्यादा नौ मैम्बर होते हैं । इस वक्त ग्राम पंचायत में एक महिला को कोआप्ट करने का प्रावधान है । अगर गांव में प्राड्यूल्ड कास्टस की स्टैरन्थ पांच परसैन्ट से दस परसैन्ट हो तो एक शड्यूल्ड कास्ट मैम्बर कोआप्ट किया जाता है । अगर शड्यूल्ड कास्टस की स्टैरन्थ दस परसैन्ट से ज्यादा हो और पंचों की संख्या सात से ज्यादा हो तो दो पंच नौमीनेट करने का प्रावधान है । अब इस ऐक्ट के तहत ग्राम सभा के अन्दर एक बैकवर्ड क्लास के भाई को भी नौमीनेट करने का प्रावधान किया जा रहा है । अगर कोई बैकवर्ड ग्लास का भाई इलैक्शन लड़ता है और उसमें वह जीत जाता है तो वह अपने आप इलैक्ट हो जायेगा । अगर हार भी जाता है तो इलैक्टिड ही समझा जायेगा । उसे नौमीनेशन की कोई जरुरत नहीं है । अगर एक से ज्यादा बैकवर्ड क्लासिज के भाई इलैक्शन लड़ते हैं तो जिसकी सब से ज्यादा राय होंगी तह इलैक्टिड समझा जायेगा । यह बात चूकिं ग्राम पंचायत पर लागू होगी इसलिये इस ग्राम पंचायत ऐक्ट में अमैंडमैंट लाये हैं । जब अगली पंचायत का इलैक्शन होगा तब से यह ऐक्ट लागू किया गया है उससे पहले डिपार्टमैंट इसके रूल्ज बनायेगा । जब रूल्ज बनेगे तो उस समय यह लिखा जायेगा कि नौमीनेशन करने के लिए प्रैस्क्राइब्ड अथोरिटी कौन होगा । जसे शड्यूल्ड कास्टस के लिए डायरैक्टर है और कुछ केसिज में गवर्नमैंट है । जहां तक ब्लौक समिति का ताल्लुक है, जिस वक्त ब्लौक समिति कांस्टीच्यूट होती है उस वक्त एक ब्लौक समिति में

16 मैम्बर्ज डायरैक्ट इलैक्ट होते हैं, जो ग्राम पंचायतों के पंचों और सरपंचों में से चुने जाते हैं, दो मैम्बर्ज कोआप्रेटिव सोसाइटीज से इलैक्ट होते हैं और एक मैम्बर मार्किट कमेटी से होता है । इसके अलावा अगर इन 19 प्राइमरी मैम्बर्ज में कोई महिला इलैक्ट नहीं होती है तो दो महिलाओं को कोआप्ट किया जाता शै । डसके अतिरिक्त चार आदमी जो शड्यूल्ड कास्टस से बीलौंग करते हों, उन्हें ब्लौक समिति में कोआप्ट किया जाता है । अब जो ऐक्ट हम पास करने जा रहे हैं उसके मुताबिक एक बैकवर्ड क्लास का मैम्बर भी ब्लौक समिति में कोआप्ट किया जायेगा। यह अगले इलैक्शन से इन बौडीज में लागू होगा । इसमें दूसरी क्लाज यह है कि यह वहीं पर लागू होगा जहां पर बैकवर्ड क्लासिज की पापुलेशन दो परसैन्ट से ज्यादा होगी यानी जिस प्रकार से शड्यूल्ड कास्टस में पांच परसैन्ट का प्रावधान है इसमें दो परसैन्ट का है । सैसस के दौरान शड्य्ल्ड कास्टस को अलग से जनगणना होती है और यह पता लगता है कि यहां पर पांच परसैन्ट हैं या दस परसैन्ट हैं लेकिन बैकवर्ड क्लासिज का इस बारे में अलग से कोई अरेन्जमेंट नहीं है । इस बारे में जब भी रूल्ज बनेंगे तो उस समय हमें यह प्रैस्क्राइब्ड करना पड़ेगा कि दो परसैन्ट जनसंख्या देखने की अथोरिटी कौंन सी बौडी के पास होगी । ये चन्द– एक बातें थी जो हम ऐक्ट में पास करने जा रहे हैं और जिन्हें मैंने हाउस के सामने रखना मुनासिब समझा था ।

**13.00 बजे**

**Mr. Speaker :** Now I will put the motions in respect of the first Bill to vote.

Question is—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**श्री अध्यक्ष :** अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

**क्लाज 2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**अनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है ––

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनौक्टग फार्मूला हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**टाइटल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब मन्त्री जी मूव करेंगे कि बिल पास किया जाये ।

**Development Minister** (Col. Rao Rain Singh) : Sir. I move—

That the Bill be passed.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाये ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाये ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**Mr. Speaker :** Now, the motions is respect of the second Bill will be put to vote.

Question is—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**श्री अध्यक्ष :** अब सदन बिल पर क्लाज वाई क्लाज विचार करेगा ।

**क्लाज 2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है —

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**अनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है—

कि अनैक्तिग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**टाइटल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब मन्त्री जी मूव करेंगे कि बिल पास किया जाये ।

**Development Minister** (Col. Rao Ram Singh) : Sir, I move—

That the Bill be passed.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाये ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाये ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(6) दि पंजाब ऐक्साईज ( हरियाणा अमैंडमैंट ) बिल, 1987**

**श्री अध्यक्ष :** अब एक मन्त्री दि पंजाब ऐक्साईज (हरियाणा अमैंडमैंट ) बिल, 1987 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1987.

I also move—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ–

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into considerationat once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into considerationat once,

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

**क्लाज 2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**अनैक्टिंग फार्मुला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**टाइटल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब मन्त्री जी मूव करेंगे कि बिल पास किया जाये ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher

Singh Surjewala) : Sir, I move-

That the Bill be passed.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाये ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाये ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**(8) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैंट) बिल, 1987**

**श्री अध्यक्ष :** अब मिनिस्टर साहव दि हरियाणा जनरल सेल्ज टेक्स (अमैंडमैंट ) बिल 1987 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

Sir, I introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1987.

I also move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into considerationat once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

**क्लाज 2**

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री जी की ओर से क्लाज 2 पर मुझे अमैंडमैंट का नोटिस मिला है । वे उसे मूव करें ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I beg to move--

That in the proposed sub-Clause (a) of clause 2 of the Bill, in Note 2 as proposed to be inserted, after the word "furniture", the following wordss hall be inserted, namely :-

"and all other goods dealt with by the tent dealer as also other allied dealers for decoration and lighting purposes".

in sub-clause(b) of clause 2 of the Bill , in Note 2 as proposed to be inserted, after the word "furniture", the following words shall be inserted, namely

"and all other goods dealt with by the tent dealer as also other allied dealers for decoration and lighting purposes";

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ–

That in the proposed sub-clause (a) of clause 2 of the Bill, in Note 2 as proposed to be inserted, after the word "furniture", the following words shall beinserted, namely :-

"and all other goods dealt with by the tent dealer as also other allied dealers for decoration and lighting purposes."

In sub-clause(b) of clause 2 of the Bill, in Note 2 as proposed to be inserted, after the word "furniture", the following words shall be inserted, namely:—

"and all other goods dealt with by the tent dealer as also other allied dealers for decoration and lighting purposes.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

That in the proposed sub-clause (a) of clause 2 of the Bill in Note 2 as proposed to be inserted, after the word "furniture", the following words shall be inserted namely :—

"and all other goods dealt with by the tent dealer as also other allied dealers for decoration and lighting purposes".

In sub-clause (b) of clause 2 of the Bill, in Note 2 as proposed to be inserted, after the word "furnture", the following words shall be inserted, namely :—

"and all other goods dealt with by the tent dealer as also other allied dealers for decoration and lighting purposes".

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 2, ऐज अमैंडिड, विल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 3**

**श्री अध्यक्ष' :** मुझे मन्त्री जी की ओर से क्लाज 3 पर भी अमैंडमैंट का नोटिस मिला है । वे उसे मूव करें ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I move—

That in clause 3 of the Bill, in clause (v) as proposed to be inserted, after the word "furniture", the following words shall be inserted, namely :-

"and all other goods dealt with by the tent dealer as also other allied dealers for decoration and lighting purposes".

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

That in clause 3 of the Bill, in clause (v) as proposed to be inserted, after the word" furniture", the following words shall be inserted, namely :—

"and all other goods dealt with by the tent dealer as also other allied dealers for decoration and lighting purposes".

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

That in clause 3 of the Bill, in clause (v) as proposed to be inserted, after the word "furniture", the following words shall be inserted namely :--

"and all other goods dealt with by the tent dealer as also other allied dealers for decoration and lighting purposes".

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 3, ऐज अमैंडिड, बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 4**

**श्री अध्यक्ष :** मुझे मन्त्री जी की ओर से क्लाज 4 पर भी अमैंडमैंट का नोटिस मित्रा है । वे उसे मूव करे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I move--

following That in clause 4 of the Bill, for the Note as proposed to be inserted, the Note shall he substituted, namely :-

"Note—Entry as substituted by Haryana Act No. 7 of 1986, shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 1986".

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ ।

That in clause 4 of the Bill, for the Note as proposed to be inserted, the following Note shall be substituted, namely :-

"Note.—Entry as substituted by Haryana Act No. 7 of 1986, shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April 1986".

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

That in clause 4 of the Bill, for the Note as proposed to be inserted, Ihe following Note shall be substituted, namely :—

"Note—.Entry as substituted by Haryana Act No. 7 of 1986, shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 1986".

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है

कि क्लाज 4, ऐज अमैंडिड बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 5**

**श्री अध्यक्ष :** आनरेबल मैम्बर्ज,, मुझे. मिनिस्टर साहब की तरफ से क्लाज न पर अमैंडमैंट का नोटिस मिला है । आनरेवल मिनिस्टर उसके मूव करें ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That in clause 5 of the Bill, in sub-section (5) as proposed, to be substituted, after the words "personal surety", the 'following words shall be inserted namely:—

"and security as may be prescribed"

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

That in clause 5 of the Bill, in sub-section(5) as proposed to be substituted, after the words "personal surety", the following words shall be inserted, namely

"and security as maybe prescribed".

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

That in clause 5 of the Bill, in sub-section (5) as proposed to be, substitu ted, after the words "personal surety", the following -words shall be inserted namely

"and security as may be prescribed'

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 5 ऐज अमैंडिड बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**अनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**टाइटल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि टाइटस बिल का टाइटल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir. I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Bill, as amended, be passed.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है—

That the Bill, as amended, be passed.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

## (9) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1987

**श्री अध्यक्ष :** अब इरिगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर दि हरियाणा लैकिलेढिव असैम्बली ( फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज ) अमैंडमैंट विल, 1987 कौ डैट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislatiye Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 1987.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana. Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहब, जो ऐग्जिसटिग प्रोविजन है उसमें हर मैम्बर को हाउस बिल्डिग ऐडवांस के लिये एक लाख रुपये की लिमिट है, मकान की रिपेयर के लिए साठ हजार रुपए की लिमिट है और कारू की परचेज के लिये साठ हजार रुपए की लिमिट है

। इस समय सारी चीजों की कीमत चूकि बढ़' गई है इसलिए परचेज आफ दि कार और कंस्ट्रक्शन आफ दी हाउस दोनों के लिए एक लाख रुपए की लिमिट ऐडमिसिबल है लेंकिन पहले वाले बिल में यह नही थी । अब यह कर दिया है कि बिल्ट हाउस परचेज करने या मकान बनाने के लिये एक लाख रुपया मिल सकता है, साठ हजार रुपया रिपेयर्ज, ऐडीशंज या आल्ट्रेशन वगैरह के लिए या सत्तर हजार रुपया फार दि परचेज आफ दि कार के लिए मिल सकता है लेकिन टोटल एक लाख रुपए से ज्यादा मही होगा । मामूली सी फैसिलिटी दी है ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

**चौधरी लीला कृष्ण (फतेहाबाद ) :** स्पीकर साहब, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हु । मान लो एक मैम्बर कार के लिए साठ हजार रुपया ऐडवास ले लेता है क्या वह मैम्बर उसको वापिस करके एक लाख रुपया मकान के लिये लोन ले सकता है?

**चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला :** अब दोनो ले सकते है पहले एक लाख की लिमिट मे ही ले सकते थे ।

**एक आवाज :** स्पीकर साहब. हममें कुछ कंफ्यूजन है । वात क्लीयर नही हुई ।

**वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर ) :** स्पीकर साहब, पहले ऐसा था कि एक मैम्बर सारी टर्म में एक ही लोन ले सकता था और उसको रिपे करने के के बाद दूसरा लोन नहीं ले सकता था । अब यह कर दिया है कि अगर एक लोन रिपे कर दिया तो दूसरा भी ले सकता है । कार परचेज लोन की लिमिट साठ हजार से सत्तर हजार कर दी है ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करे गा ।

**क्लाज 2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 3**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है ––

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**अनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**टाइटल**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब मन्त्री जी मूव करेंगे कि विल पास किया जाए ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) **:**

Sir, I beg to move--

That the Bill be passed.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ ––

कि बिल पास किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(10) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एण्ड अलाउंसिज (अमैडमैट) बिल, 1987**

**श्री अध्यक्ष :** अब इरिगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज ऐण्ड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज ऐण्ड अलाउन्सिज (अमैंडमैंट ) बिल. 1987 को इन्ट्रोड्यूम करेंगे और उसे कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1987.

Sir, I also move

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's

and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy. Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into onsideration at once.

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

**क्लाज 2**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लाज 1**

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

## अनैक्टिंग फार्मूला

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

## टाइटल

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है––

कि टाइटल बिल का टाइटल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष :** अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

**Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) Sir, I beg to move--

That the Bill be passed.

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

## सिंचाई तथा बिजली मन्त्री /अध्यक्ष आदि द्वारा धन्यवाद देना

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ) :** सर, हाउस ऐडजर्न होने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहूंगा । आज सैशन का लास्ट दिन है और इम असैम्बली की जो पूरी टम है उसका भी यह लास्ट सैशन है । उसके बाद चुनाव होंगे लेकिन सरकार या स्पीकर जब चाहें बीच में सैशन बुला सकते हैं । नौर्मली यह आज का दिन इस असैम्बली का लास्ट दिन है । इसलिये मैं यह कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि यह सैशन और इससे पहले जितने भी सैशन आपकी टर्म के अन्दर हुए है, उनको आपने जिस कुशलता से, डैकोरम से, तरीके से सूझबूझ के साथ चलाया है इसके लिये हम सब आपके आभारी है । स्पीकर साहब. पहले कई सैशनों में विरोधी पक्ष के भाई भारी गिनती में यहां हाउस में आते थे अब तो सरदार लछमन सिंह जी अकेले मैम्बर उस तरफ से रह गये हैं और सारी विरोधी पार्टी को वे अकेले ही रिप्रेजैन्ट करते हैं लेकिन उस वक्त भी आपने बडे ही निष्पक्ष तरीके से हाउस की प्रोसीडिंग्ज को चलाया है । आपने बड़ी सहनशीलता का परिचय दिया है और सभी ओर के मैम्बर्ज को आपने जिस तरीके से बोलने का मौका दिया है, चाहे वे नये

मैम्बर थे या चाहे किसी भी पार्टी से सम्बन्धित थे, चाहे किसी किस्म के थे वह सचमुच सराहनीय था । आपने सारे हाउस का ग्रैटीव्यूड और ऐप्रीसिएशन अर्न की है । (तालियां ) यह इस हाउस के लिये बड़े फब की बात है कि आप जैसे स्पीकर हमारे इस हाउस में विराजमान है । अब यह टर्म खत्म होने जा रही है हमें इस बात का सन्तोष है कि आपके प्रति किसी के दिल में मलाल कोई इल बिल या पक्षपात करने की या किसी प्रकार के दुख की बात नहीं है । इन सारी बातों का श्रेय आपको ही जाता है । इसके साथ साथ स्पीकर साहब, मैं यह भी कहे वगैर नही रह सकता कि जब कभी डिप्टी स्पीकर साहब, चेयर पर बैठे हैं तो उन्होंने भी बहुत ही योग्यता– पूर्वक निष्पक्षता से और बहादुरी से अपने काम को .सरअन्जाम दिया है । इसके लिये हम उनके आभारी हैं । स्पीकर साहब, आप जो पैनल आफ चेयरमैन नौमीनेट करते आये हैं, उन्होंने भी अपना फर्ज बखूबी निभाया है । इस के साथ साथ हम विधानसभा स्टाफ के मैम्बर्ज और अधिकारीगण को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने फर्ज को अच्छे ढंग से पूरी मेहनत करके निभाया है और पूरा सहयोग दिया है ।

स्पीकर साहब, अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि सुनील गावस्कर ने दस हजार रन बनाकर अपने जीवन का कीर्तिमान स्थापित करके सारी दुनिया में जो रिकार्ड कायम किया है वह पूरे देश के लिये फख्र की बात है । इस हाउस के मैम्बर आपके द्वारा उन्हें द्रुम के लिये मुबारिकबाद देते हैं । इन शब्दों के साथ एक

बार फिर, मैं आपका इस हाउस के सभी मैम्बर साहेबान की ओर से धन्यवाद करता हूं । जय हिन्द ।

**श्री लछमन सिंह (कालका ) :** स्पीकर साहब, मैं भी पूरी अपोजीशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं हालांकि अपोजीशन की तरफ से बहुत बार प्रोवोकेशन भी हुई, ऐसे अलफाज भी कहे गये जो नाकाबिले बर्दाश्त थे, वे एक्सपन्ज भी हुए, फिर भी आपने बड़ी तहलम मजाजी और मुसतकिल मिजजिा में ही सब कुछ सहन किया और बडे ठण्डे दिल से काम लिया । इसके लिये सारी अपोजीशन आपकी शूक्रगुजार है हम तो यही दुआ करते हैं कि आगे से भी आप जैसे महानुभाव स्पीकर वन कर आयें या खुदा करे आप खुद ही दोबारा यहां स्पीकर बनकर आएं । यही मेरी खुदा के दरबार में इल्तजाह है । इसके साथ साथ मैं अपने वाकी सभी मैम्बर साहेबान से, अगर कोई मेरे से यहा पर गल्त बात कही गयी हो तो उसके लिये मैं माफी चाहूंगा । ऐसा' चलता ही रहता है ।

अध्यक्ष महोदय, इसके माथ साथ मैं डिप्टी स्पीकर साहब और पैनल आफ चेयरमैन कर भी सारी अपोजीशन की ओर से शुक्रिया अदा करता हुं जिन्होंने अपने फर्ज को बखूबी निभाया है । विधान सभा स्टाफ द्वारा इरा कोआपरेशन देने के लिये भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं । जय हिन्द ।

**श्री अध्यक्ष :** आनरेबल मैम्बर्ज, 1982 से 1987 तक की जो इस असैम्बली की टर्म थी उसने आप लोगो ने मुझे इस कुर्सी पर बैठा कर पूरा मान दिया है और जो मैंने वायदा किया था कि मैं पूरा इम्पार्शियल होकर चराने की कोशिश करुंगा उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस अर्से में, अपनी ओर मे अपनी सूझबूझ से. अपनी अक्ल से इस बात की पूरी कोशिश की है कि इम हाउस मे पूरी इम्पार्शिऐलिटी से काम किया जाए । मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं उन भाइयों के लिये जो आज यहां सदन में नहीं हैं, क्या लफ्ज कहूं जबकि मैं एक तरफ तो कहता हूं कि मैं उनके लिये इम्पार्शियल था और उनकी फेवर में इम्पार्शियल रहा भी हूं क्योंकि जब दो तिहाई हिस्से टेरकी बैन्चिज मैम्बर के थे और एक तिहाई हिस्सा वे थे तो एक तिहाई हिस्से. वालों को हाउस में बोलने के लिये डबल टाइम देता रहा हुं और यहां हाउस में यह कहता रहा हूं कि ट्रेजरी बैन्चिज वालों ने मिनिस्टर्ज ने तो काम करना है, अपनी कलम ही चलानी है और ये जो दूसरे अपोजीशन के भाई हैं, इनका काम है सरकार के कामो पर सरकार की नीतियो पर निगाह रखना और क्रिटीसाइज करना लेकिन आज हम यह देखते हैं कि वे भाई उधर बैन्चिज पर नही बैठे हैं औंर मै इस कुर्सी पर बैठा, यह कहता अच्छा नही लगता लेकिन जनता के लोग तो अच्छे।. प्रकार से यह जानते है कि उनके यहां नहोने से, हरियाणा की जनता का, हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के इलाकों का कितना फायदा हुआ हए या कितना नुकसान हुआ णै । साहेबान आप जानते है कि इस तरफ पहले 27– 28 मैम्बर्ज होते

थे लेकिन आज सरदार लछमन सिंह जी एक यानी सवा लाख ही है जो सारी अपोजीशन की तरफ से वात कर रहे हैं । वे बड़े माकूल हैं । मैं आप सब का बड़ा शुक्रग्रुजार हूँ कि आप सबने मुझे पूरा मान दिया है पूरी इज्जत दी है और मेरे साथ काआपरेट किया है । चाहे मैंने आप लोगों की निस्बत अपोजीशन को वोराने के लिये ज्यादा ही टाईम दिया है और आपको कम टाईम दिया, फिर भी आपने उसे महसूस नही किया । मैं डिप्टी स्पीकर साहब, तथा पैनल आफ चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करता हू जिन्होंने हाउस की कार्यवाही चलाने में मुझे पूरी मदद दी है । हमारे विधान सभा के जो कर्मचारी है, उन्होंने जिस ढंग से मेहनत करके और कई मामलों में अगर मैं यह कहूं कि मुझे गाइड करके इतने अच्छे ढंग से इस हाउस को पांच मालों तक चलाने में असिसटैन्स दी है, वह प्रशंसनीय है । अगर मैं यह भी कहूं कि इसमें उनका भारी योगदान रहा है, तो यह कोई गल्त बात नहीं होगी । इसके साथ साथ मैं प्रैस वाले अपने भाईयों को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे ढंग से हमारी विधान सभा की प्रोसीडिंग्ज के पब्लिश किया है । इसके लिये मैं उन का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं । ( विघ्न ) इसके साथ साथ अन्त में मैं अपने वाहेगुरु से परमात्मा से अल्लाताला से प्रार्थना करता हूं कि जितने मैम्बर साहेबान यहां पर बै टे हैं वे अगले इलैक्शन में चुनकर अवश्य आयें । इन अलफाज के साथ मैं एक बार फिर आप सब का शूक्रिया अदा करता हूं ।

The House now stands adjourned sine-die.

**13. 28 बजे**

(The Sabha then *adjourned sine-die)